



Annual Report | 2022-23

वार्षिक रिपोर्ट | 2022-23



काजू और कोको विकास निदेशालय
DIRECTORATE OF CASHEWNUT & COCOA DEVELOPMENT



सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2022-23

काजू और कोको विकास निदेशालय

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

केरा भवन, कोचिन – 682011 केरल, भारत

DIRECTORATE OF CASHEWNUT AND COCOA DEVELOPMENT

Government of India

Department of Agriculture & Farmers Welfare

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

Kera Bhavan, Kochi-682011, Kerala, India

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

सही प्रशस्ति पत्र:

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

काजू और कोको विकास निदेशालय

कोचिन-11

Correct Citation:

Annual Report 2022-23

Directorate of Cashewnut & Cocoa Development

Cochin - 11

प्रकाशित:

रवींद्र कुमार,

प्रभारी निदेशक

Published by:

Ravindra Kumar

Director in Charge

संपादक

दादासाहेब देसाई

उप निदेशक

Editor

Dadasaheb Desayi

Deputy Director

संपादकीय सहायक

जयलक्ष्मी वी एस

निखिल वी एम

अनन्या सूसन

Editorial Assistance

Jayalakshmi V S

Nikhil V M

Anannya Susan

अनुवादक:

रश्मी आर आई

Translator:

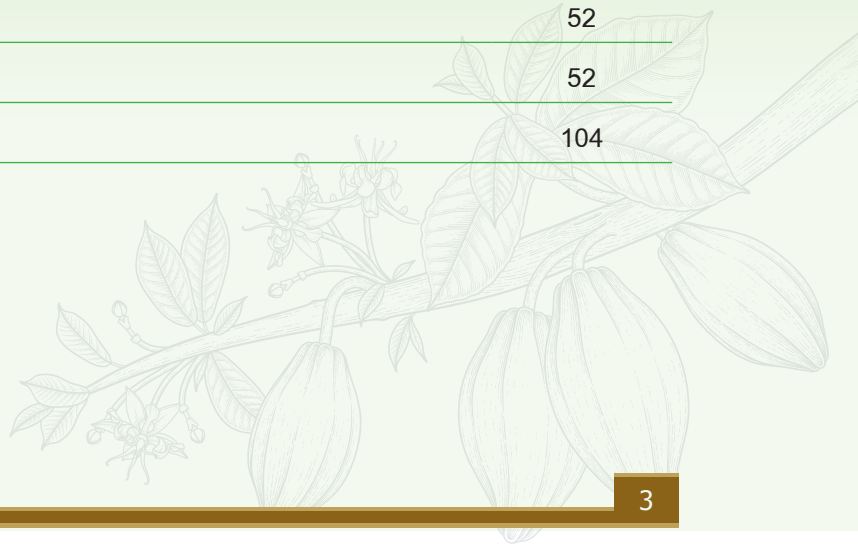
Resmi R I

Printed at:

M/s. P.P. Entreprises, New Delhi.

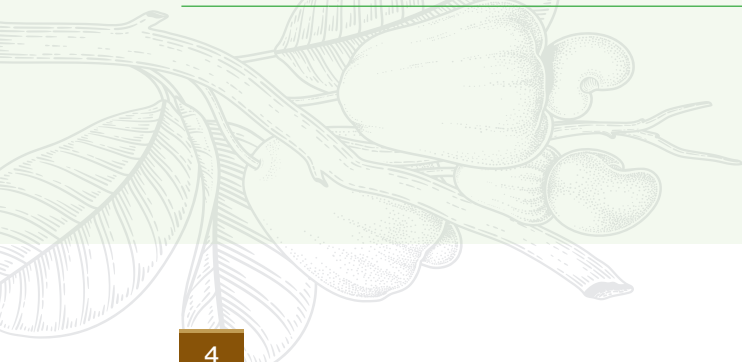


क्रम सं.	विषय-सूची	पृ.सं.
	मुख्य विशेषताएं	7
1.	भूमिका	8
1.2	अधिदेश	9
1.3	संगठनात्मक ढाँचा	9
2.	काजू और कोको परिदृश्य	11
2.1	काजू	11
2.2	कोको	13
2.3	गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ	14
3.	कार्यान्वयन स्थिति – (काजू/कोको)	16
3.1	विकास पहल	17
3.2	बैठकें/सम्मेलन/संगोष्ठियाँ	34
4	प्रशासनिक मामले	51
4.1	सूचना का अधिकार	51
4.2	सतर्कता जागरूकता सप्ताह	51
4.3	दिव्यांगजन संबंधी कार्य की रिपोर्ट	52
4.4	राजभाषा कार्यान्वयन रिपोर्ट	52
5	कार्यक्रम फोटो गैलरी	104





Sl.No.	Chapter	Page No.
	Highlights	59
1.1	Introduction	60
1.2	Mandate	61
1.3	Organizational Setup	61
2.	Cashew & Cocoa Scenario	63
2.1	Cashew	63
2.2	Cocoa	65
2.3	Activities and Achievements	66
3.	Implementation status (Cashew/Cocoa)	67
3.1	Developmental initiatives	69
3.2	National campaigns/Meetings/Conference/Workshops	83
4.	Administrative matters	98
4.1	Right to Information	98
4.2	Vigilance and special campaign 2.0	98
4.3	Report on PWD	98
4.4	Official Language Implementation Report -2022-23	99
5	Programme photo gallery	104



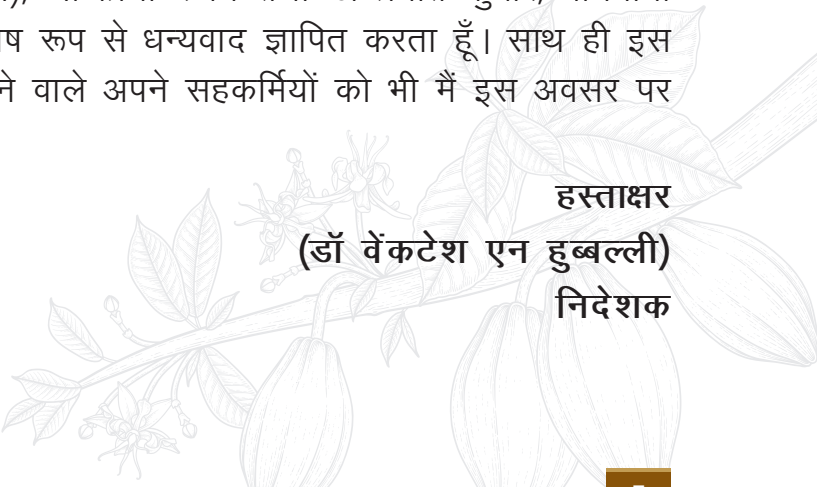
आमुख

काजू और कोको विकास निदेशालय जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय स्तर का एजेंसी है, ने देश में काजू और कोको के विकास कार्य के पचपन उज्ज्वल वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किए हैं। हमारे देश को काजू और कोको की खेती के लिए नवीनतम तकनीकी ज्ञान, पर्याप्त मानव शक्ति और जन्मजात वातावरण आदि के व्यापक संसाधन हैं। विभिन्न राज्यों में काजू और कोको के लिए अच्छी तरह से बनाई गई विकास पद्धतियों के कार्यान्वयन के साथ निदेशालय ने काजू और कोको के तहत क्षेत्र को क्रमशः 11.93 लाख हेक्टेयर और 1.08 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने और उत्पादन क्रमशः 7.82 लाख मीट्रिक टन और 30,000 मीट्रिक टन करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश को काजू कर्नल और संबंधित उत्पादों के निर्यात से रु. 2733 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है और कोको उत्पादों से रु. 1242 करोड़। अर्थव्यवस्था में इन फसलों की प्रधानता के मद्देनजर भारत सरकार ने एकीकृत बागानी विकास मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन वर्ष 2022-23 में क्षेत्र विस्तार, पुराने जीर्ण बागानों का उच्च क्षमतायुक्त कलमों से पुनर्रोपण के साथ-साथ मानव संसाधन विकास और प्रचार कार्य जैसे कई विकास परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी है।

छप्पन वर्ष पुरा करने वाले निदेशालय के वर्ष 2022-23 की इस वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। रिपोर्ट में निदेशालय की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है और रिपोर्ट वर्ष के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों, विशेषकर किसानों की आय बढ़ाने और दोनों फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में उठाई गई कदमों दर्शाई गई है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के भाग के रूप में निदेशालय ने इस अवधि के दौरान 'किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी' अभियान, नारी शक्ति मेला तथा किसान के खेती में काजू और कोको जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहूंगा कि हम अपने कार्यकलाप जारी रखेंगे तथा देश में काजू और कोको के विकास के लिए जीतोड़ प्रयत्न करेंगे और इसप्रकार इन फसलों के उत्पादन द्वारा देश को इस दिशा में आत्मनिर्भर बनाकर किसानों को अच्छी आमदनी दिलाने में मदद करेंगे।

इस अवसर पर मैं संयुक्त सचिव (बाग), श्री प्रिया रंजन तथा डॉ प्रभात कुमार, बागवानी आयुक्त को उनके प्रचुर समर्थन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही इस निदेशालय के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देने वाले अपने सहकर्मियों को भी मैं इस अवसर पर धन्यवाद देता हूँ।



हस्ताक्षर
(डॉ वेंकटेश एन हुब्बल्ली)
निदेशक

PREFACE

The Directorate of Cashewnut and Cocoa Development (DCCD), a National Level Agency (NLA) under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare had successfully completed fifty five years of glorious service in the promotion and development of Cashew and Cocoa in the country. In India, Cashew and Cocoa crops have got wide resources with regard to latest technical knowhow, adequate manpower and congenial environment for its cultivation. The Directorate had made a significant achievement in increasing the Area under Cashew and Cocoa to 11.93 lakh ha and 1.08 lakh ha respectively and Production to 7.82 lakh MT and 30,000 MT respectively with the implementation of well-designed developmental strategies for Cashew and Cocoa in various states. Considerable foreign exchange worth Rs. 2733 cr. per annum have been earned by India through the export of cashew kernels and allied products and also another value of foreign exchange worth Rs. 1242 cr. was also earned by the export of cocoa beans and cocoa products from India during the year 2022-23. Considering the importance of these crops to the Indian economy, Govt. of India has sanctioned several developmental schemes under MIDH during 2022-23 focusing on expansion of area, removing senile cashew plantations and replanting with high yielding varieties supported with HRD and Publicity activities.

I am extremely happy in bringing out the Annual Report 2022-23 of this Directorate during its 56th year of existence. This report highlights various activities undertaken by this Directorate and the efforts taken up in achieving the goal with a specific focus in increasing farmer's income and to improve production and productivity of both crops. As a part of the AzadiKaAmritMahotsav celebration the Directorate had organised Kisan Bhagidhari Pradhaamikta Hamari campaign, Narishaktimela and awareness programme on cashew and cocoa for the farmers in the farmers field.

I would like to confirm that we shall continue our activities and put our whole-hearted efforts for the development of Cashew and Cocoa in the country and make the country self-sufficient in the production of these crops in future.

I take this opportunity to thank Shri. Priya Ranjan, Joint Secretary (Horticulture) and Dr. Prabhat Kumar, Horticulture Commissioner, Govt. of India for providing unstinted support in carrying out the activities of the Directorate in the most befitting manner. I also thank my colleagues for the efforts and co-operation rendered in achieving the goals set by this Directorate.

Sd/-
(Dr. Venkatesh N. Hubballi)
Director

मुख्य विशेषताएं

- राज्य और केंद्र के प्रयासों से 8,456 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र काजू के उच्च क्षमतायुक्त किस्मों से रोपण किया गया।
- राज्य और केंद्र के प्रयासों से कोको के 3,422 हेक्टेयर उच्च उपज देने वाली किस्मों के क्लोन के साथ रोपण किया गया।
- राज्य और केंद्र के प्रयासों से कुल 1,200 हेक्टेयर पुराने जीर्ण बागानों का उच्च क्षमतायुक्त कलमों से पुनर्रोपण किया गया।
- नर्सरी की मान्यता के लिए एक नोडल एजेंसी की हैसियत से निदेशालय ने, 46.00 लाख ग्राफ्ट की उत्पादन क्षमता वाली 31 काजू नर्सरी और 18.30 लाख कोको संकर पौध उत्पादन की क्षमता वाली 9 कोको नर्सरी को गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता दी है।
- विकास कार्यक्रमों के लिए कुल 7,23,141 काजू ग्राफ्ट और 1,00,000 कोको संकर पौध का उत्पादन और वितरण किया गया।
- नए रोपण कार्यक्रम के तहत निदेशालय ने काजू और कोको के लाभार्थियों को 8158 सीधा लाभ अंतरण (डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) किया।
- दो बड़े और दो छोटे नर्सरियों की स्थापना की गई और सात नर्सरियों का उन्नयन किया गया।
- प्रचार और फसल संवर्धन गतिविधियों के भाग के रूप में, 42 जिला स्तर के सेमिनार और एसएयू / केवीके / निगमों और आईसीएआर संस्थानों के सहयोग से विभिन्न राज्यों में 9 फील्ड दिवस आयोजित किए गए। निदेशालय ने केरल और कर्नाटक में दो 'किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी' अभियान, कण्णूर में दो काजू जागरूकता कार्यक्रम तथा केरल और कर्नाटक में दो नारी शक्ति मेले आयोजित किए। लगभग 2000 हितधारकों ने काजू और काको के बारे में जानकारी हासिल की।
- मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत काजू & कोको की खेती के तरीकों पर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर संस्थानों के सहयोग से 76 किसान स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम (राज्य के भीतर) आयोजित किए गए थे जिसमें 3800 किसानों को प्रशिक्षण दिलाया गया।
- काजू आपिल के मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने के प्रशिक्षण के तहत 19 बैच में 475 बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया।
- फील्ड तथा विस्तार कर्मियों के लिए काजू/कोको पर दो राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका 80 अधिकारियों ने फायदा उठाया।
- भारत से वर्ष 2022-23 की काजू कर्नल निर्यात आय रु.2677 करोड़ और निर्यात मात्रा 44,271 मेट्रिक टन थी।
- वर्ष 2022-23 के दौरान भारत से कोको उत्पादों का निर्यात 34,250 मीट्रिक टन था जिसका मूल्य 1242 करोड़ रुपये था।



1

भूमिका

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत 1966 में काजू विकास निदेशालय की स्थापना ने भारत में विभिन्न काजू विकास कार्यक्रमों की अच्छी तरह से बनाई गई विकास रणनीतियों का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय केंद्रीय मसाले और काजू समिति के उन्मूलन के परिणामस्वरूप, काजू को बढ़ावा देने और उसके उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ काजू विकास निदेशालय (डीसीडी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1.4.1966 को केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी। वर्ष 1997 में, कोको की फसल भी काजू विकास निदेशालय को सौंप दी गई और संस्था का नाम बदलकर काजू और कोको विकास निदेशालय (डीसीसीडी) कर दिया गया।

निदेशालय वर्तमान में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एबाविमि) के तहत राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों में से एक के रूप में कार्य कर रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर काजू और कोको से संबंधित गतिविधियों के कार्यान्वयन, समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। निदेशालय काजू और कोको पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए भी जिम्मेदार है और काजू & कोको नर्सरी के मूल्यांकन और मान्यता के लिए नोडल एजेंसी भी है। इस निदेशालय का गठन इन दो बहुमुखी बागवानी फसलों के समग्र विकास में एक सफलता थी। निदेशालय की यह वार्षिक रिपोर्ट 01-04-2022 से 31-03-2023 की अवधि के दौरान गतिविधियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है।

इस निदेशालय की स्थापना के बाद से, इन फसलों के विकास के लिए लगातार प्रयास किए गए थे। निदेशालय की विकास गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र विस्तार और रोपण सामग्री के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और यह राज्यों द्वारा निष्पादित कार्यक्रमों की बारीकी से निगरानी और समीक्षा कर रहा है। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना के बाद से काजू और कोको का क्षेत्र और उत्पादन बढ़ रहा है, जिसमें काजू और कोको के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जाती है।

निदेशालय देश में विभिन्न काजू और कोको विकास कार्यक्रमों को लागू करने वाले विकास विभागों, अनुसंधान संगठनों, निगमों, स्थानीय पंचायत और किसान संगठनों जैसे सभी हितधारकों के साथ जुड़े है। निदेशालय नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/क्षेत्र अभियान/सेमिनार आयोजित करके, स्थानीय भाषाओं में साहित्य लाकर उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों का आदान-प्रदान करने में कृषक समुदाय के साथ सौहार्दपूर्वक सहयोग करता है। निदेशालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ केंद्रीय और राज्य संस्थानों के बीच काजू और कोको को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों का समन्वय और निगरानी करता है।

भारत सरकार द्वारा बारहवी योजना में बागवान सेक्टर के समग्र विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन नाम से एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किया है जो काजू और कोको के विकास के लिए उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने में, प्रशिक्षण एवं फील्ड दारे द्वारा मानव संसाधन विकास, तथा फसलनोत्तर प्रबंधन एवं विपणन के लिए आधारिक संरचना बनाने में सहायता प्रदान करती है। निदेशालय अब एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अधीन परियोजनाओं का राज्य और केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वयन कर रहा है।

1.2 अधिदेश

काजू और कोको विकास निदेशालय के लक्ष्य एवं अधिदेश निम्नलिखित हैं :

- काजू और कोको के विकास कार्यक्रमों का निर्माण, कार्यान्वयन और निष्पादन तथा देश में काजू तथा कोको के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रम बनाना तथा उन कार्यक्रमों का एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अधीन राज्य सरकारों द्वारा निष्पादन सुनिश्चित करना।
- देश में काजू और कोको के रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण की निगरानी करने और नर्सरियों को मान्यता देने के लिए नोडल एजेंसी।
- काजू एवं कोको प्रवर्धन कार्यों में कृषि मंत्रालय एवं केंद्रीय/राज्य संस्थाओं के बीच में समन्वय का कार्य।
- पूरे उत्पादन सेक्टर में प्रौद्योगिकियों का प्रचार-प्रसार का कार्य।
- फसल क्षेत्र, उत्पादन, कीमत, विपणन, आयात-निर्यात आदि के आँकड़े रखना।
- फसल विकास, विपणन तथा उपोत्पादों की उपयोगिता आदि पहलुओं पर निरीक्षण करने और संस्तुतियाँ प्रदान करने वाला सलाहकार निकाय।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा, राष्ट्रीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और फील्ड दिवसों के आयोजन द्वारा तथा पत्रिकाओं एवं पुस्तिकाओं के प्रकाशन द्वारा प्रौद्योगिकियों का व्यापक प्रचार प्रसार करना।
- उद्यमियों को तकनीकी सलाह और सुझाव प्रदान करना तथा किसान समुदाय को खेती के विभिन्न पहलुओं पर सलाह प्रदान करना।
- विभिन्न राज्यों में काजू और कोको कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगे अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

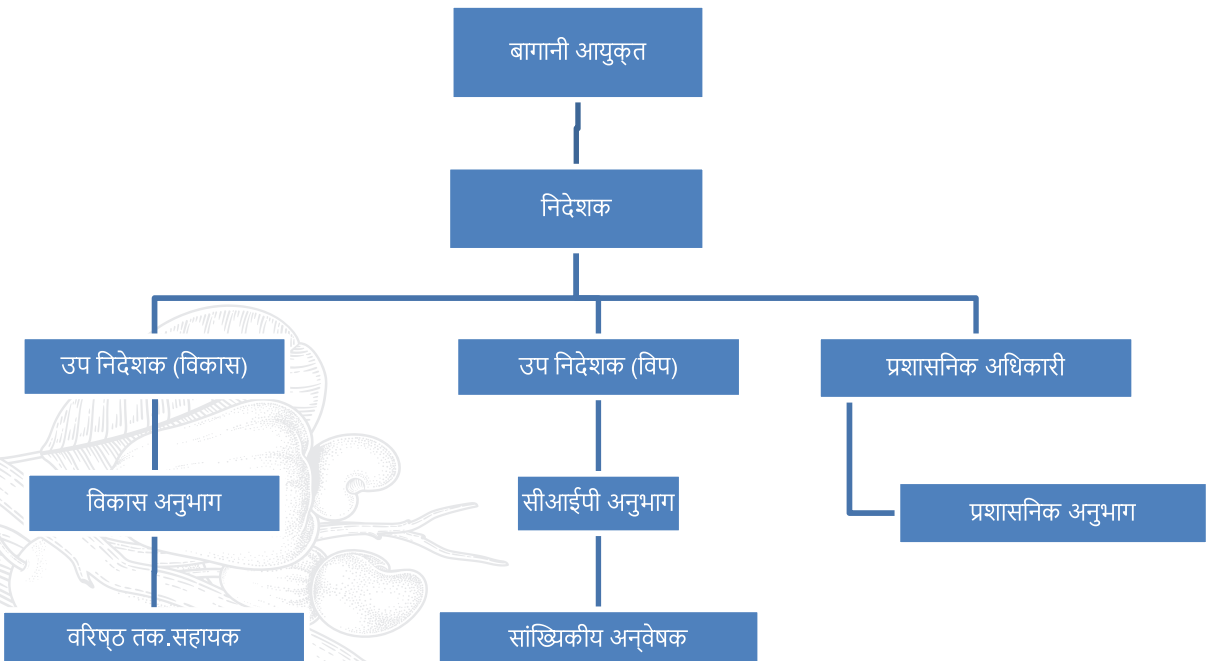
1.3 संगठनात्मक ढाँचा

काजू और कोको विकास निदेशालय निदेशक की अध्यक्षता पर कार्य कर रहा है। उनकी सहायतार्थ दो उपनिदेशक, एक प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी हैं। निदेशालय के तीन अनुभाग हैं रू विकास अनुभाग, फसल सूचना एवं प्रचार अनुभाग तथा प्रशासन अनुभाग। निदेशालय की स्टाफ सूची नीचे प्रस्तुत है

स्टाफ सूची

पदनाम	स्वीकृत पद	वर्तमान संख्या
निदेशक	01	01
उप निदेशक	02	02 (1 प्रतिनियुक्ति पर)
प्रशासनिक अधिकारी	01	01
सांख्यिकीय अन्वेषक	01	01
वरिष्ठ तकनीकी सहायक	01	01
कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी	01	01
तकनीकी सहायक	04	04 (1 प्रतिनियुक्ति पर)
आशुलिपिक (ग्रेड I)	02	-
वरिष्ठ संगणक	01	01
प्रवर श्रेणी लिपिक	01	01 (प्रतिनियुक्ति पर)
अवर श्रेणी लिपिक	02	02
हिन्दी टंकक	01	01
एम.टी.एस	03	0
कुल	22	16 (3 प्रतिनियुक्ति पर)

संगठनात्मक सेटअप – डीसीसीडी



2

काजू और कोको परिदृश्य

2.1 काजू

ब्राजील मूल के काजू को 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में लाया गया था। 1950 के दशक में यूरोपीय देशों को काजू के निर्यात की शुरुआत के साथ, काजू ने व्यावसायिक महत्व प्राप्त कर लिया। 1970 के दशक तक भारत ने काजू के वैश्विक बाजार में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखी। अब, काजू देश में एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है, जिसने ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था के उत्थान और छोटे और सीमांत किसानों की मुख्य आजीविका के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय काजू गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है और भारत ने विश्व महामारी की स्थिति पर काबू पाते हुए 2022–23 के दौरान 2734 करोड़ रुपये मूल्य के काजू गिरी और सीएनएसएल का निर्यात किया। आर्थिक महत्व के अलावा, लगभग आधा मिलियन किसान काजू की खेती में लगे हुए हैं और दस लाख लोग प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्र में लगे हुए हैं।

वर्तमान में काजू की खेती 19 राज्यों में व्याप्त है। इसकी खेती मुख्यतः केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, ओडीशा, एवं पश्चिम बंगाल तथा कुछ हद तक इसकी खेती छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, नागालैंड, मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय तथा अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह में की जाती है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काजू और कोको विकास निदेशालय को विभिन्न काजू विकास कार्यक्रमों के निर्माण और निष्पादन कार्य सौंपा गया है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, सचिवों के समूह की सिफारिशों पर 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित करने के लिए डीसीसीडी ने मंत्रालय के अनुमोदन पर तीन साल का कार्यक्रम तैयार किया है तथा राज्य और केंद्र के प्रयासों से वर्ष 2017–18 से 87,842 हेक्टेयर के क्षेत्र को काजू के तहत लाया गया था। अब, काजू 11.93 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 7.82 लाख मीट्रिक टन कच्चे माल के उत्पादन और 766 किलोग्राम/हेक्टेयर (2022–23) की उत्पादकता के साथ फैला है।



काजू उत्पादन परिदृश्य (2022-23)

राज्य	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता
	(000 हे)	(000 मे.ट)	(कि/हे)
केरल	108.589	74.63	839
कर्नाटक	138.867	77.85	653
गोवा	59.444	25.81	491
महाराष्ट्र	191.551	197.30	1145
तमिलनाडु	174.960	80.39	594
आंध्रप्रदेश	198.848	132.31	764
ओडीशा	223.450	126.13	655
पश्चिम बंगाल	14.552	13.28	1169
झारखंड	15.580	6.60	424
छत्तीसगढ़	32.585	22.30	716
गुजरात	11.848	7.01	802
पोंडिचेरी	5.000	2.33	466
असम	1.050	1.16	1105
त्रिपुरा	4.250	3.55	835
मेघालय	8.780	10.38	1182
मणिपुर	0.900	0.33	367
नागालैंड	2.000	0.55	1100
कुल	1192.254	781.92	766

भारत में संगठित एवं असंगठित सेक्टर में लगभग 3940 संसाधन एकक चालू है जिसका कुल उत्पादन क्षमता 17 लाख मेट्रिक टन कच्चा काजू प्रति वर्ष है। इसलिए, काजू उद्योग यहाँ की आंतरिक माँग की पूर्ति के लिए अन्य देशों से आयात के माध्यम से लगभग 56 प्रतिशत कच्चे माल का आयात करता है, विशेषकर अफ्रीका से। वर्ष 2010-11 में 5.29 लाख मेट्रिक टन की दर पर आयात शुरू किया था जो अब बढ़कर वर्ष 2022-23 में 13,29,751 मेट्रिक टन हो गया है। अफ्रीका में अब अपना संसाधन कार्य शुरू हुआ है और इसलिए हमारी कमी को दूर करने के लिए आंतरिक उत्पादन बढ़ाना होगा।

जब कच्चे काजू नट के उत्पादन में सुधार करने की कोशिश की जाती है, तो क्षेत्र विस्तार के साथ-साथ उत्पादकता में वृद्धि को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। वर्तमान में, काजू के तहत क्षेत्र 11.94 लाख हेक्टेयर है, जिनमें से लगभग 75% निजी क्षेत्र में हैं, जो ज्यादातर छोटे और सीमांत होल्डिंग तक सीमित हैं जो राष्ट्रीय उत्पादन का 80% हैं। कुल क्षेत्रफल में से, 33 प्रतिशत मौजूदा क्षेत्रों ने 45 साल पार कर लिए हैं, जो कम से कम उत्पादकता दे रहे हैं, जो अत्यधिक अनुत्पादी है। कृषक समुदाय में ज्यादातर लोगों को वैज्ञानिक और बागवानी प्रौद्योगिकी के बारे में पता नहीं है। काजू की किस्मों, क्लोनों के उपयोग, आईएनएम और आईपीएम पैकेजों के संदर्भ में सभी वैज्ञानिक उन्नयन ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें क्षेत्र में अधिक प्रयोग की आवश्यकता है। कृषक समुदाय के बीच वैज्ञानिक उन्नयन में सुधार से उपज में वर्तमान उत्पादन की तुलना में न्यूनतम 15% की वृद्धि होगी। इसलिए इन सभी मुद्दों को रोपण सामग्री के उत्पादन को मजबूत करने के अलावा काजू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत लिया गया था। तदनुसार एमआईडीएच के तहत इस फसल पर ध्यान केंद्रित करने के कारण 2005-06 से काजू के क्षेत्र और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 में कुल 8.20 लाख हेक्टर काजू खेती से 5.44 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन होता था। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अधीन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के पश्चात् अब रिपोर्ट वर्ष में कुल 11.93 लाख हेक्टर में काजू की खेती की जा रही है और कुल उत्पादन 7.82 लाख मेट्रिक टन है।

2.2 कोको

कोको विश्व का सबसे मुख्य व्यावसायिक बागवानी फसलों में एक है। यह मुख्य रूप से चोकलेट उद्योग का कच्चा माल है। यह भारत में उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में लाया गया था लेकिन इसकी खेती 1960 में शुरू हुई थी। अब यह भारत में मुख्य रूप से चॉकलेट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण व्यावसायिक बागवानी फसलों में से एक बन गई है। इसकी खेती मुख्य रूप से चार दक्षिणी राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में की जाती है। भले ही कोको को चाय, कॉफी और रबड़ जैसे बागवान का दर्जा दिया गया हो, लेकिन भारतीय कृषि क्षेत्र के तहत इसे शायद ही कभी बागवानी फसल के रूप में मान्यता दी जाती है। कोको अत्यधिक पौष्टिक होते हैं और चॉकलेट का एकमात्र प्रमुख स्रोत हैं। चूंकि यह फ्लेवोनोइड्स में समृद्ध है, यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और यह एक ऊर्जा बढ़ाने वाला पेय है। यह अत्यधिक किफायती फसल है और भारत में नारियल और सुपारी के खेतों में एक उत्तम



अंतर फसल के रूप में उगाई जाती है। भारत में कोको का उत्पादन, मात्रा में कम है और अन्य प्रमुख उत्पादक देशों की तुलना में नगण्य है। कोको न केवल प्रति इकाई क्षेत्र में अतिरिक्त आय प्रदान करता है बल्कि नियमित अंतराल पर बड़ी मात्रा में पत्तियाँ गिराकर मिट्टी की उत्पादकता को भी बढ़ाता है। पिछले वर्षों में कोको के विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ, कोको के तहत वर्तमान क्षेत्र 1,08,985 हेक्टेयर है जिसमें कुल उत्पादन 29,792 मेट्रिक टन और उत्पादकता 825 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

कोको उत्पादन परिदृश्य (2022-23)

राज्य	क्षेत्र (हे)	उत्पादन (मे.ट)	उत्पादकता (कि / हे)
केरल	18233	10,535	1100
कर्नाटक	14269	4,061	650
तमिलनाडु	32580	3,061	350
आंध्रप्रदेश	43904	12,135	1200
कुल	108985	29,792	825

भारत में कोको उत्पादों के उपभोग में भी सालाना 15% की वृद्धि हुई है। भारत ने रिपोर्ट वर्ष में कोको उत्पादों के निर्यात से 1242 करोड़ से ज्यादा कमाया भी है। चॉकलेट उद्योग और कन्फेक्शनरी की वर्तमान मांग लगभग 70,000 मीट्रिक टन कोको बीन्स है जबकि घरेलू उत्पादन इसका केवल 38 प्रतिशत है। कोकोआ की फलियों की भारी कमी अब उद्योग के सामने मुख्य समस्या है और भारत ने मांग को पूरा करने के लिए 3531 करोड़ रुपये के 1,28,654 मीट्रिक टन कोको और कोको उत्पादों का आयात किया है। कुछ साल पहले तक, कोको के दाम में उतार-चढ़ाव होता था। लेकिन अब यह लगभग स्थायी होकर प्रति किलो सूखे बीन का दाम रु.150 – 180 है। इस उच्च मूल्य की फसल के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने एकीकृत विकास बागवानी मिशन (एमआईडीएच) के तहत इस फसल को बढ़ावा देने के लिए और अधिक जोर दिया है।

2.3 डीसीसीडी प्रयास, गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के रूप में डीसीसीडी, प्राथमिक खेत स्तर पर कृषक समुदाय के साथ सीधे हस्तक्षेप करने और प्रौद्योगिकियों

को अनुसंधान से खेत तक प्रभावी ढंग से स्थानांतरित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र है। निदेशालय देश में विभिन्न काजू और कोको विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए विकासात्मक विभागों, अनुसंधान संगठनों, निगमों, एफपीओ, स्थानीय पंचायत और किसान संगठनों के सहयोग से कार्यरत है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पिछले चार दशकों के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत निदेशालय के प्रयासों से क्षेत्रफल के मामले में चार गुना और उत्पादन के मामले में सात गुना वृद्धि हुई है और देश में काजू की उत्पादकता के मामले में 100% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत निदेशालय, इस फसल को सबसे उपयुक्त तरीके से विकसित कर रहा है और अपने सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को जारी रखेगा, अनुसंधान संगठनों, राज्य विकास विभागों, उद्योग के साथ पूरक और अनुपूरक बना रहेगा और सबसे बढ़कर बड़े पैमाने पर सलाह देगा। कृषक समुदाय को उत्पादन बढ़ाने के लिए काजू का वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाना चाहिए। डीसीसीडी की योजनाओं और हस्तक्षेपों का उद्देश्य न केवल विकास है बल्कि इसका उद्देश्य पिछड़े/आदिवासी/वन क्षेत्रों में किसानों को बहुत आवश्यक दैनिक आजीविका/सामाजिक उत्थान प्रदान करना भी है।





कार्यान्वयन स्थिति (काजू और कोको)

3. एमआईडीएच के तहत काजू और कोको पर कार्यान्वयन की स्थिति (2022-23)

क्रसं	कार्यक्रम	पिछले साल से 2021-22				2022-23			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय परिव्यय (लाखों में)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय परिव्यय (लाखों में)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय परिव्यय (लाखों में)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय परिव्यय (लाखों में)
1.	नए बागान की स्थापना								
क	काजू नया रोपण	160	19.20	160	19.20	3800	456.00	3346	401.726
ख	काजू- 2 वर्ष का रखरखाव	95.25	3.81	-	-	640	25.60	501	20.021
ग	काजू- 3 तक वर्ष का रखरखाव	-	-	-	-	803	32.12	752	30.054
घ	कोको नया रोपण	-	-	-	-	200	24.00	200	24.000
ङ	कोको - 2 nd वर्ष का रखरखाव	-	-	-	-	149	5.96	148	5.912
च	कोको - 3तक वर्ष का रखरखाव	-	-	-	-	150	5.98	149	5.968
2.	जीर्ण बागानों को उच्च क्षमतायुक्त किस्मों से पुनर्रोपण (हे)								
क	नया रोपण	40	4.80	40	4.80	650	78.00	650	78.00
ख	2 nd वर्ष का रखरखाव	-	-	-	-	1140	45.60	1140	45.60
ग	3तक वर्ष का रखरखाव	-	-	-	-	500	20.00	500	20.00
3.	एफएलडी द्वारा प्रौद्योगिकी का अंतरण								
क	उच्च सघन काजू रोपण का प्रदर्शनी प्लॉट	-	-	-	-	100	40.00	59	23.600
ख	कोको किस्म प्रदर्शनी	2	0.83	-	-	0.00	0.00		
4.	नर्सरी कार्यक्रम (सं)								
क	काजू उच्च-प्रौ नर्सरियों की स्थापना	---	---	-	-	-	-	-	-
ख	बड़ी काजू नर्सरियों की स्थापना	1	20.00	1	20.00	2	40.00	1	20.000
ग	छोटी काजू नर्सरियों की स्थापना	1	7.50	1	7.50	2	15.00	1	7.500
घ	नर्सरियों का उन्नयन/आधुनीकरण (सं)	3	15.00	3	15.00	4	20.00	4	20.00
ङ	नर्सरियों का प्रत्यायन	10	1.10	10	1.10	40	3.00	30	2.968
5.	फसल प्रवर्धन प्रचार (उत्तर-पूर्वी सहित)								
क	राष्ट्रीय सम्मेलन (काजू/कोको)	-	-	-	-	1	5.00	1	5.00
ख	जिला स्तर की संगोष्ठियाँ (सं.)	2	0.93	2	0.93	40	30.00	40	30.00
ग	काजू/कोको मेला/दिवस (सं.)	3	6.20	3	6.20	3	5.00	6	2.700
घ	प्रदर्शनी/विज्ञापन/प्रकाशन		0.25		0.25		21.50	NB	20.590
ङ	काजू/कोको पणधारकों की बैठक	-	-	-	-	2	4.00	2	3.855

क्रसं	कार्यक्रम	पिछले साल से 2021-22				2022-23			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय परिव्यय (लाखों में)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय परिव्यय (लाखों में)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय परिव्यय (लाखों में)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय परिव्यय (लाखों में)
6.	मानव संसाधन विकास								
क	काजू पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	-	-	-	-	1	7.50	1	5.750
ख	कोको पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	-	-	-	-	1	4.00	1	4.000
ग	काजू आपिल उपयोगिता प्रशिक्षण	3	0.39	3	0.398	25	5.00	16	3.250
घ	काजू/कोको उत्पादन प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण	-	-	-	-	90	27.00	76	22.70
ङ	मूल्य वर्धन पर कौशल विकास प्रशिक्षण	25	13.65	20	9.85	-	-	-	-
च	प्रदर्शनी दौरा	-	-	-	-	5	15.00	4	11.050
7.	उत्पादन पूर्वानुमान (जिला)	9	1.80	4	0.800	8	1.60	8	0.800
8.	कोको की प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई	-	-	-	-	5	10.00	-	-
9.	मिशन प्रबंधन	-	0.99	-	0.990	-	48.54	-	46.261
	कुल (काजू और कोको)	-	96.45	-	87.018	-	995.40	-	861.305

3.1 विकासात्मक पहल

उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के ज़रिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता पर काजू और कोको विकास निदेशालय, देश के विभिन्न काजू/कोको उत्पादक पारंपरिक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में इन फसलों का विकास कार्य कर रहा है। ये विकास कार्यक्रम दो तरीके से किए जा रहे हैं : एक तो काजू और कोको विकास निदेशालय की कार्य-योजना के आधार पर राज्य द्वारा कार्यान्वयन तथा दूसरे, राज्य अपनी ही कार्य योजना के आधार पर राज्य द्वारा कार्यान्वयन करते हैं और काजू और कोको विकास निदेशालय इसका मॉनीटरिंग करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशालय द्वारा पणधारियों के सहयोग से किए गए मुख्य कार्य हैं नए बागानों का विकास, पुनर्रोपण, पुनर्युवन, अच्छे रोपण सामग्री का उत्पादन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ, प्रदर्शनी दौरे आदि। इसके अलावा, राज्य बागवानी मिशन द्वारा कार्यान्वित विकासात्मक कार्यक्रमों की निगरानी समीक्षा बैठकों, पत्राचारों, फोन पर चर्चा, क्षेत्र का दौरा मूल्यांकन और नए रोपण और पुनर्रोपण के निरीक्षण द्वारा निदेशालय ने अपना मॉनीटरिंग कार्य सुचारु रूप से किया।

i) किसान के खेत में नए बागान की स्थापना (काजू और कोको)

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों के खेत में काजू और कोको की उच्च क्षमतायुक्त किस्मों के साथ नए बागान विकसित करना है। कार्यक्रम सीधे डीसीसीडी द्वारा स्थानीय पंचायत, केवीके, एनजीओ और विभागों के सहयोग से कार्यान्वित किया गया था। सहायता का पैटर्न 20,000 रुपये



प्रति हेक्टेयर (भारत सरकार द्वारा 100% हिस्सा) था जो काजू और कोको के नए रोपण के लिए प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर तक सीमित था। व्यक्तिगत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता अनुसंधान संस्थानों की सामान्य सिफारिशों के अनुसार काजू के लिए 200 पौधे प्रति हेक्टेयर और अंतरफसल के रूप में कोको के लिए 500 पौधे प्रति हेक्टेयर तक सीमित कर दी गई थी।

कार्यक्रम के तहत, एमआईडीएच दिशानिर्देशों के अनुसार गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा राज्यों में क्लस्टर आधार पर काजू और कोको के बागान स्थापित किए गए। वर्ष 2022-23 के दौरान काजू और कोको के तहत 3960 हेक्टेयर ताजा रोपण और 1742 हेक्टेयर रखरखाव के लिए कुल 568.86 लाख रुपये निर्धारित किए गए थे। वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल 3506 हेक्टेयर क्षेत्र काजू और कोको के तहत कवर किया गया था। कार्यक्रम के तहत कुल 8192 किसान लाभान्वित हुए। कार्यक्रम का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है।

कर्नाटक

वर्ष 2022-23 के दौरान, केवीके, अनुसंधान स्टेशनों और बागवानी विभाग के सहयोग से नया रोपण कार्यक्रम लागू किया गया था। कालाबुरागी, हावेरी, हनुमानमट्टी, गदग, खानापुरा, चल्लकेरे, उत्तर कन्नड़ और हिरियूर में 73.46 लाख रुपये की वित्तीय उपलब्धि के साथ 612 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र इस कार्यक्रम के तहत लाया गया। नए बागानों की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों के बीच लगभग 1.22 लाख अच्छी गुणवत्ता वाले काजू कलमें वितरित की गईं। इसके अलावा, कार्यक्रम के तहत 386 हेक्टेयर क्षेत्र में दूसरे और तीसरे वर्ष की रखरखाव गतिविधि शुरू की गई। कार्यक्रम के तहत कुल 818 लघु एवं सीमांत किसान लाभान्वित हुए।

केरल

वर्ष 2022-23 के दौरान नया रोपण कार्यक्रम सीधे ग्रामपंचायत के सहयोग से लागू किया गया। कार्यक्रम के तहत 38.37 लाख रुपये की वित्तीय उपलब्धि के साथ केरल के कन्नूर और कासरगोड जिलों के आलक्कोड*, बलाल, कुरमात्तूर*, चेंगलयी, चप्पारपडव*, मलप्पट्टम, नाडुविल, पदियूर, पयावूर और उदयगिरि पंचायत में 323 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में काजू लगाया गया। नए बागानों की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों के बीच लगभग 64800 अच्छी गुणवत्ता वाले काजू कलमें वितरित की गईं। इसके अलावा, कार्यक्रम के तहत 344 हेक्टेयर क्षेत्र में दूसरे और तीसरे वर्ष की रखरखाव गतिविधि शुरू की गई। केरल में काजू कार्यक्रम के तहत कुल 1759 छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हुए।

वर्ष 2022-23 के दौरान, केरल के वायनाड, इडुक्की, पलक्कड़ और कोझिकोड जिलों में ग्रामपंचायत के सहयोग से कोको के नए रोपण कार्यक्रम को भी डीसीसीडी द्वारा सीधे लागू किया गया था। रिपोर्ट वर्ष के दौरान, 12.00 लाख रुपये की वित्तीय उपलब्धि के साथ कनियाम्बेटा,

कंजीकुझी, कुडुरंजी और वडकरपति पंचायत में 100 हेक्टेयर क्षेत्र को कोको रोपण के तहत लाया गया और नए पौधों की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों के बीच 50000 अच्छी गुणवत्ता वाले संकर पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम के तहत कुल 293 लघु एवं सीमांत किसान लाभान्वित हुए।

गोवा

वर्ष 2022–23 के दौरान, नया रोपण कार्यक्रम किसानों की सहकारी समितियों जैसे सत्तारीतालुका किसान सेवा सहकारी समिति और गोवा बगायतदार खरेदी विक्री सौन्स्थ मर्यादित के सहयोग से लागू किया गया था। 50.87 लाख रुपये की वित्तीय उपलब्धि के साथ 424 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को काजू की खेती के तहत लाया गया। नए बागानों की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों के बीच लगभग 89,651 अच्छी गुणवत्ता वाले काजू कलमें वितरित की गईं। कार्यक्रम के तहत कुल 402 लघु एवं सीमांत किसान लाभान्वित हुए।

गुजरात में जनजातीय उत्थान कार्यक्रम

निदेशालय ने आदिवासी किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के उद्देश्य से विशेष रूप से गुजरात के तापी, डांग और वलसाड जिलों में आदिवासी किसानों के लिए काजू के नए रोपण कार्यक्रम को लागू किया। एनजीओ के श्री सेवियर पब्लिक ट्रस्ट और श्री राम एजुकेशन और ग्रामीण विकास चौरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से उपयुक्त आदिवासी कॉलोनियों की पहचान की गई। 245.77 लाख रुपये की वित्तीय उपलब्धि के साथ 2048 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को काजू की खेती के तहत लाया गया। डीसीसीडी से मान्यता प्राप्त काजू नर्सरी से आदिवासी किसानों के बीच कुल 4.20 लाख अच्छी गुणवत्ता वाले काजू कलमें वितरित किए गए। कार्यक्रम के तहत कुल 2558 आदिवासी किसान लाभान्वित हुए।

केरल में जनजातीय उत्थान कार्यक्रम

निदेशालय ने आदिवासी किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के उद्देश्य से केरल के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में विशेष रूप से आदिवासी किसानों के लिए कोको नया रोपण कार्यक्रम लागू किया। जनजातीय विस्तार विभाग और मॉडेलेज इंडिया फूड्स (प्राइवेट) लिमिटेड के सहयोग से उपयुक्त जनजातीय कॉलोनियों की पहचान की गई। रुपये 12.00 लाख की वित्तीय उपलब्धि के साथ 100 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को कोको की खेती के तहत लाया गया। डीसीसीडी से मान्यता प्राप्त कोको नर्सरी से आदिवासी किसानों के बीच 50000 अच्छी गुणवत्ता वाले संकर पौधे वितरित किए गए। इसके अलावा, नए रोपण कार्यक्रम के तहत 298 हेक्टेयर को दूसरे और तीसरे वर्ष के रखरखाव के तहत कवर किया गया था। कार्यक्रम के तहत कुल 903 आदिवासी किसान लाभान्वित हुए। राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि नीचे दी गयी है।



क. नया रोपण कार्यक्रम – काजू एवं कोको (लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ -2022-23)

क्र. सं.	राज्य	काजू (2022-23)				कोको(2022-23)			
		नया रोपण (सपिलओवर सहित)				नया रोपण			
		भौ.लक्ष्य (हे)	वित्त. परिव्यय (लाखों में)	भौ.लक्ष्य (हे)	वित्त. परिव्यय (लाखों में)	भौ.लक्ष्य (हे)	वित्त. परिव्यय (लाखों में)	भौ.लक्ष्य (हे)	वित्त. परिव्यय (लाखों में)
1	गोवा	600	72.00	423.93	50.87	-	-	-	-
2	गुजरात	2100	252.00	2048.16	245.77	-	-	-	-
3	कर्नाटक	652	78.24	612.2	73.46	-	-	-	-
4	केरल	330	39.60	322.99	38.76	200	24.00	200	24.00
5	महाराष्ट्र	128	15.36	100.58	12.07	-	-	-	-
6	नागालैंड	100	12.00	0	0	-	-	-	-
7	इम्फाल	50	6.00	0	0	-	-	-	-
	कुल	3960	475.20	3507.86	420.93	200	24.00	200	24.00

क्र. सं.	राज्य	काजू (2022-23)				काजू (2022-23)			
		दूसरे साल का रखरखाव				तीसरे साल का रखरखाव			
		भौ.लक्ष्य (हे)	वित्त. परिव्यय (लाखों में)	भौ.लक्ष्य (हे)	वित्त. परिव्यय (लाखों में)	भौ.लक्ष्य (हे)	वित्त. परिव्यय (लाखों में)	भौ.लक्ष्य (हे)	वित्त. परिव्यय (लाखों में)
1	आंध्रप्रदेश	320	12.8	235	9.38	339.5	13.65	289	11.53
2	कर्नाटक	212	8.48	159	6.36	225.43	9.02	227	9.09
3	केरल	108	4.32	108	4.28	236.25	9.45	236	9.43
	कुल	640	25.6	502	20.02	803	32.12	752	30.05

क्र. सं.	राज्य	कोको (2022-23)				कोको (2022-23)			
		दूसरे साल का रखरखाव				तीसरे साल का रखरखाव			
		भौ.लक्ष्य (हे)	वित्त. परिव्यय (लाखों में)	भौ.लक्ष्य (हे)	वित्त. परिव्यय (लाखों में)	भौ.लक्ष्य (हे)	वित्त. परिव्यय (लाखों में)	भौ.लक्ष्य (हे)	वित्त. परिव्यय (लाखों में)
1	केरल	149	5.96	148	5.91	149.75	5.98	149.2	5.97
	कुल	149	5.96	148	5.91	149.75	5.98	149.2	5.97

ii) पुराने जीर्ण बागानों का उच्च क्षमतायुक्त किस्मों से पुनरोपण

इस कार्यक्रम की परिकल्पना है पुराने जीर्ण बागानों का उच्च क्षमतायुक्त किस्मों से पुनरोपण करना। निदेशालय ने विभिन्न राज्यों के वन विभागों, राज्य फार्मों और निगमों के स्वामित्व वाली भूमि में जीर्ण काजू बागानों के क्लस्टर समूहों में योजना को सीधे लागू किया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान 1180 हेक्टेयर ताजा रोपण, 500 हेक्टेयर में दूसरे वर्ष के रखरखाव कार्य और 700 हे में तीसरी वर्ष के रखरखाव कार्य के लिए कुल 148.40 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई थी। वर्ष 2022-23 के दौरान, 690 हेक्टेयर के पुराने बागानों को हटा दिया गया और काजू की उच्च क्षमतायुक्त किस्मों से पुनरोपण किया गया है। इसके अलावा 1648 हेक्टेयर क्षेत्र में रखरखाव किया गया था। रिपोर्ट वर्ष में निम्नलिखित निगमों को कुल 148.40 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

क्र.सं	राज्य	भौतिक लक्ष्य(हे)	वित्तीय लक्ष्य (लाखों में)	भौतिक उपलब्धि (हे)	वित्तीय उपलब्धि (लाखों में)
1	कर्नाटक न.रो.	150	18.00	150	18.00
	र2	250	10.00	250	10.00
	र3	0	0.00	0	0.00
2	तमिलनाडु न.रो.	0	0.00	0	0.00
	र2	250	10.00	250	10.00
	र3	238.95	9.55	238.95	9.55
3	ओडीशा न.रो.	540	64.80	540	64.80
	र2	640	25.60	640	25.60
	र3	261.05	10.45	261.05	10.45
	कुल न.रो	690	82.80	690	82.80
	र2	1140	45.60	1140	45.60
	र3	500	20.00	500	20.00



iii) प्रदर्शना/फ्रंट लाइन प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रसार – काजू और कोको

इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को विभिन्न वैज्ञानिक उत्पादन प्रौद्योगिकियों के लाभों को प्रदर्शित करना और समझाना है। प्रत्येक प्रदर्शन इकाई 1 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए और वित्तीय सहायता की दर अधिकतम रु. 40,000/- प्रति हेक्टेयर होगी।

उच्च सघन रोपण (एचडीपी) काजू क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण है जो प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक संख्या में पौधे लगाकर उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम है। परंपरागत रूप से काजू को 8 मीटर x 8 मीटर के अंतराल पर लगाया जाता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर 150 से 160 पौधे लगाए जाते हैं और पौधों को आवंटित स्थान को कवर करने और उचित प्रबंधन प्रथाओं के साथ 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की संभावित उपज देने में 7-8 साल लगते हैं। इसलिए, आर्थिक उपलब्धि के लिए प्रारंभिक लंबी प्रतीक्षा अवधि के कारण कम उत्पादकता को दूर करने के लिए उच्च घनत्व रोपण सबसे उपयुक्त समाधान प्रतीत होता है। अत्यधिक कायिक वृद्धि पर नियंत्रण उत्पादकता को बढ़ावा देता है और यही उच्च सघन रोपण का प्रमुख सिद्धांत है। इसलिए, उच्च सघन वाले वृक्षारोपण में पेड़ों की नियमित रूप से छंटाई की जाती है। एचडीपी प्रणाली में, रोपण के शुरुआती वर्षों में पैदावार में सुधार होता है। प्रारंभिक वितान कवरेज के कारण, उच्च सघन रोपण प्रणाली खरपतवार की वृद्धि रोकती है और मिट्टी के तापमान को कम करती है जिससे मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, खासकर गर्मी के चरम मौसम के दौरान। यह वृक्षारोपण में पलवारन प्रभाव भी प्रदान करता है। काजू की एचडीपी में, अंतराल कम होने की वजह से, सामान्य अंतराल की तुलना में दो गुना अधिक उपज मिलती है। एचडीपी प्रणाली में काजू की पैदावार 6 साल तक चार गुना और 12 साल तक 2.27 गुना तक बढ़ाई जा सकती है।

एचडीपी प्रणाली को लोकप्रिय बनाने और कृषक समुदाय को समझाने के लिए, निदेशालय ने विभिन्न अनुसंधान स्टेशनों और विकास विभागों के सहयोग से प्रदर्शन प्लॉट स्थापित किए हैं। 2022-23 के दौरान, कर्नाटक और केरल राज्य में 100 इकाइयों के भौतिक लक्ष्य के मुकाबले 23.60 लाख रुपये की वित्तीय उपलब्धि के साथ कुल 59 इकाइयाँ स्थापित की गईं।

iv) नर्सरी कार्यक्रम

क) काजू/कोको नर्सरी की स्थापना/उन्नयन

इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में काजू/कोको के नए रोपण और पुनरोपण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले रोपण सामग्रियों का उत्पादन और वितरण है। अधिकतम वित्तीय सहायता बड़ी नर्सरियों के लिए कुल परियोजना लागत के 40%/20.00 लाख रुपये और छोटी नर्सरियों के लिए कुल परियोजना लागत के 50%/7.50 लाख रुपये तक सीमित होगी।

नर्सरियों के उन्नयन के लिए लागत का 50% निजी क्षेत्र को दिया जाएगा, बशर्ते कि अधिकतम रु 5.00 लाख/नर्सरी होगा।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, तमिलनाडु, ओडीषा, महाराष्ट्र और केरल राज्यों में 55 लाख रुपये की वित्तीय उपलब्धि के साथ दो छोटी नर्सरियाँ और दो बड़ी नर्सरियाँ स्थापित की गईं और 35.00 लाख रुपये की वित्तीय उपलब्धि के साथ सात नर्सरियों का उन्नयन किया गया।

क्र. सं.	नर्सरी का नाम	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
1	सुप्ता एगोटेक, ओडीषा	1 (छोटी नर्सरी)	7,50,000
2.	श्री कुरिंजी नर्सरी, तमिलनाडु	1 (छोटी नर्सरी)	7,50,000
3.	ग्रीन सोलेस नर्सरी, महाराष्ट्र	1 (बड़ी नर्सरी)	20,00,000
4.	श्री स्वामी नर्सरी, महाराष्ट्र	1 (बड़ी नर्सरी)	20,00,000
5.	जार्स, ब्रह्मवार, कर्नाटक	1 (उन्नयन)	5,00,000
6.	आर ए आर एस पिलिकोड, केरल	1 (उन्नयन)	5,00,000
7.	रसिका नर्सरी, महाराष्ट्र	1 (उन्नयन)	5,00,000
8.	अरोल्कर फार्मस, महाराष्ट्र	1 (उन्नयन)	5,00,000
9.	श्री रामेश्वर नर्सरी, महाराष्ट्र	1 (उन्नयन)	5,00,000
10.	मनोहर नर्सरी, महाराष्ट्र	1 (उन्नयन)	5,00,000
11.	नीलेश नर्सरी, महाराष्ट्र	1 (उन्नयन)	5,00,000
	कुल		90,00,000

ख) नर्सरियों का प्रत्यायन

डीसीसीडी द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के आधार पर यह निदेशालय मौजूदा काजू & कोको नर्सरियों की मान्यता के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और मान्यता का प्रमाण पत्र जारी करता है। निदेशक डीसीसीडी द्वारा गठित एक समिति जिसमें काजू अनुसंधान के विशेषज्ञ, डीसीसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी और बागवानी/कृषि विभाग के एक अधिकारी शामिल हैं, नर्सरी का दौरा करते हैं। मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, निदेशालय संबंधित नर्सरियों को मान्यता का प्रमाण पत्र जारी करता है। 2022-23 के दौरान, 40 काजू और कोको नर्सरी को मान्यता दी गई थी और निरीक्षण टीम के आकस्मिक खर्च को पूरा करने के लिए 4.068 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी।



राज्यवार काजू नर्सरियाँ और उनकी उत्पादन-क्षमता - 2022-23

राज्य	नर्सरियों की संख्या	उत्पादन क्षमता (लाखों में)
कर्नाटक	4	4,00,000
महाराष्ट्र	10	25,50,000
तमिलनाडु	15	10,40,000
ओडीशा	2	7,00,000
कुल	31	46,90,000

राज्यवार कोको नर्सरियाँ और उनकी उत्पादन-क्षमता - 2022-23

राज्य	नर्सरियों की संख्या	उत्पादन क्षमता (लाखों में)
केरल	3	5,55,000
कर्नाटक	2	2,50,000
आंध्रप्रदेश	3	9,75,000
असम	1	50,000
कुल	9	1,8,30,000

v) केंद्र और राज्य के प्रयास से क्षेत्र विस्तार की स्थिति

कच्चे नट और कोको की फलियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, 2022-23 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों में 8456 हेक्टेयर काजू और 3422 हेक्टेयर कोको के क्षेत्र को नई खेती के तहत लाया गया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

काजू/कोको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम की उपलब्धियाँ 2022-23

(एबाविमि/राकृवियो/राज्य कार्यक्रम) (क्षेत्र हे में)

राज्य	काजू	कोको
कर्नाटक	868	55
केरल	2068	463
महाराष्ट्र	101	—
ओडीशा	रि.न	—

राज्य	काजू	कोको
झारखंड	रि.न	
गुजरात	2048	
आंध्रप्रदेश	1042	2404
तमिलनाडु	1720	500
मेघालय	रि.न	
गोवा	424	
मणिपुर	रि.न	
छत्तीसगढ़	185	
मध्यप्रदेश	रि.न	
नागालैंड	रि.न	
पश्चिम बंगाल	रि.न	
कुल	8456	3422

रि.न – रिपोर्ट नहीं की गई।

vi) काजू उत्पादन पूर्वानुमान

कार्यक्रम का उद्देश्य 2022–23 सीजन में काजू की उपज का वास्तविक आकलन करना है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का अनुसंधान या आर्थिक विभाग इस कार्यक्रम में शामिल है। अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिक इस उद्देश्य के अनुकूल प्रगणक क्षमता वाले प्रगणकों की पहचान करते हैं और उन्हें गणन कार्य के लिए प्रशिक्षण देते हैं। इस निदेशालय द्वारा विकसित फसल अनुमान के प्रोफार्मे का उपयोग सर्वेक्षण के लिए प्रगणकों द्वारा किया गया था। फसल की गणना फलों के सेट (मूंगफली की अवस्था) के समय की जाती है।

वर्ष 2022–23 के दौरान 3.40 लाख रुपये के परिव्यय पर विभिन्न काजू अनुसंधान केंद्रों द्वारा इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए मंजूरी दी गई थी। यह सर्वेक्षण केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, तीनों मुख्य राज्यों में फलन काल के दौरान किए गए। एजेंसियों के प्रस्तावों के अभाव में गोवा, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे मुख्य राज्यों में यह योजना लागू नहीं की गई थी। इस उद्देश्य के लिए 2022–23 के दौरान 1.6 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया था।



क्र. सं	एजेंसी / रा.कृ.वि	सर्वेक्षण में शामिल जिला	रकम (रु.)
1	आर.एफ.आर.एस, वेंगुली	सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नगिरी, कोल्हापुर	40000
2	ए.एच.आर.एस. उल्लाल	दक्षिण कन्नड	40000
3	सी.आर.एस, बापटला	पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी	40000
4	सी.आर.एस, माडकत्तरा	मलपुरम, कासरगोड	40000
		कुल	160000

vii) फसल प्रवर्धन प्रचार – काजू और कोको

काजू और कोको पर उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रसार कृषक समुदाय के लिए फसलों को एक लाभदायक उद्यम बनाने के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, 'प्रौद्योगिकी प्रसार के माध्यम से काजू और कोको के फसल संवर्धन' के प्रचार को काजू और कोको, बागवानी मेले, क्षेत्र दिवसों, राष्ट्रीय सेमिनारों आदि पर जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन करके गहन प्रचार उपायों की परिकल्पना की गई है तथा अनुसंधान संस्थान/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और के.वी.के. के सहयोग से कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान प्रचार कार्यक्रम के लिए 72.88 लाख रुपये रखे गए और निम्नलिखित प्रचार कार्यक्रमों के तहत 69.530 लाख रुपये खर्च हुए।

क) काजू एवं कोको पर जिला स्तर की संगोष्ठियाँ

150 प्रतिभागियों के साथ काजू और कोको पर एक दिवसीय जिला स्तरीय संगोष्ठी आयोजित करने के लिए 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और संबंधित आयोजन संस्थानों को हॉल, श्रव्य-दृश्य, बिजली, प्रचार सामग्री, पेन और पैड, फोटोग्राफी, जलपान और प्रतिभागियों को कामकाजी दोपहर का भोजन प्रदान करने के लिए, संसाधन कर्मियों के लिए मानदेय, परिवहन आदि की व्यवस्था के लिए खर्चे उठाने के लिए राशि जारी की जाती है।

निधि का 100% उपयोग करके कार्यक्रम को विभिन्न राज्यों में सफलतापूर्वक लागू किया गया। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न राज्यों में 7650 लाभार्थियों की भागीदारी के साथ काजू और कोको पर 51 जिला स्तरीय सेमिनारों के आयोजन के लिए 37.375 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

काजू

राज्य	कार्यक्रमों की संख्या	रकम(रु.)	किसानों की सं
आंध्रप्रदेश	4	300000	600
छत्तीसगढ़	1	75000	150
गुजरात	1	75000	150
गावा	1	75000	150
कर्नाटक	10	763501	1500
केरल	8	527782	1200
महाराष्ट्र	2	144500	300
मध्यप्रदेश	1	75000	150
ओडीशा	5	375000	750
तमिलनाडु	4	300000	600
कुल	37	2710783	5550

कोको

राज्य	कार्यक्रमों की संख्या	रकम(रु.)	किसानों की सं
आंध्रप्रदेश	1	75000	150
असम	1	70000	150
कर्नाटक	3	206685	450
केरल	3	225000	450
तमिलनाडु	6	450000	900
कुल	14	1026685	2100

ख) काजू पर राष्ट्रीय सम्मेलन

ओडिशा राज्य काजू विकास निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर के सहयोग से अप्रैल 2022 के दौरान भुवनेश्वर में दो दिवसीय राष्ट्रीय काजू सम्मेलन निर्धारित किया गया था। किसान भागीदारी अभियान के संबंध में अत्यावश्यकताओं के कारण सम्मेलन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित नहीं किया जा सका। सम्मेलन को जनवरी 2023 के महीने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था।



वर्ष 2022-23 के दौरान सम्मेलन के आयोजन के लिए 2021-22 में 5.00 लाख रुपये की राशि पहले ही प्रतिबद्ध की गई थी।

व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों को अपनाकर काजू के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करने के उद्देश्य से काजू पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है। 2021-22 के लक्ष्य को रिपोर्ट वर्ष में 30 और 31 जनवरी 2023 को ओडिशा के भुवनेश्वर में ओएससीडीसी के सहयोग से काजू पर एक दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था इसके अलावा केलाडी शिवप्पा नायक विश्वविद्यालय के सहयोग से शिवमोग्गा, कर्नाटक में कोको पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था जिसमें राज्य विकास विभागों / राज्य के स्वामित्व वाले निगमों / एसएयू / अनुसंधान संस्थानों / उद्योग और विपणन के क्षेत्र में हितधारकों और प्रगतिशील किसानों के अधिकारी शामिल थे। उपरोक्त संगठनों के लगभग 350 प्रतिभागियों ने दो राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया। 2021-22 के स्पिल ओवर लक्ष्य सहित दोनों सम्मेलनों के संचालन के लिए 10.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

ग) काजू/कोको मेला/फील्ड दिवस

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में बागवानी मेला/क्षेत्र दिवस आयोजित करके इन फसलों के महत्व, दायरे और विकास के बारे में सामान्य जनता को अवगत कराना है। फसलों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के उद्देश्य से प्रदर्शनी आयोजित की जाती है जिसमें विभिन्न संगठनों, अनुसंधान केंद्रों आदि का स्टाल लगाया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान केरल, आंध्रप्रदेश एवं ओडीशा के राज्य कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से रु.8.90 लाख के खर्चे पर काजू और कोको मेला/फील्ड दिवस आयोजित किए गए थे। लगभग 5300 किसानों ने इस कार्यक्रम का फायदा उठाया। एजेंसीवार विवरण नीचे दिया गया है।

एजेंसी	कार्यक्रमों की सं.	किसानों की सं.	रकम(रु.)
एएचआरएस, उल्लाल	1	300	50000
एआरएस, हनुमनमट्टी	1	1000	120000
सीपीसीआरआई, विठल	1	1000	150000
सीआरएस, बापटला	1	300	50000
डीसीसीडी	1	300	60000

एजेंसी	कार्यक्रमों की सं.	किसानों की सं.	रकम(रु.)
एचआरएस, अंबाजिपेटा	1	200	30000
ओएससीडीसी, भुवनेश्वर	1	1000	200000
यूएसएस, रायचूर	1	1000	200000
जेड ए एच आर,रुस मुडीगेरे	1	200	30000
कुल	9	5300	890000

घ) काजू और कोको पर हितधारकों की बैठक

भविष्य के लिए एक कार्रवाई योग्य योजना विकसित करने और काजू और कोको क्षेत्र में मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने के लिए, हितधारकों की एक बैठक की परिकल्पना की गई है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, निदेशालय ने 27.08.2022 को पनाजी, गोवा में भारत सरकार के बागवानी आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार की अध्यक्षता में काजू और कोको पर हितधारकों की बैठक आयोजित की। इसी प्रकार कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर के सहयोग से मई-जून 2023 के दौरान आयोजित होने वाला है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए कुल रु. 3.855 लाख रुपये का उपयोग किया गया।

च.) काजू और कोको के प्रवर्धनार्थ प्रचार कार्य जैसे प्रदर्शनियाँ विज्ञापन, साहित्य के मुद्रण, विडियो, फील्ड दिवस आदि

एकीकृत बागवानी विकास मिशन की वित्तीय सहायता पर इस परियोजना के अधीन ज़रूरी आधार पर काजू और कोको उत्पादक राज्यों में प्रदर्शनी, फील्ड दिवस और अन्य प्रशिक्षण अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तिकाएं, पैम्फलेट, फोल्डर आदि की छपाई के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कृषक समुदायों और विस्तार श्रमिकों के बीच वितरित करने के उद्देश्य से अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में काजू और कोको साहित्य की तैयारी और छपाई के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। प्रचार कार्यक्रमों के तहत काजू और कोको की खेती और प्रसंस्करण पहलुओं पर वीडियो के विकास की भी परिकल्पना की गई है। भारत के कृषक समुदाय के बीच काजू और कोको पर नवीनतम तकनीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बागवानी विकास में लगे संस्थानों/सोसाइटियों और मीडिया को विकास संबंधी पहलुओं, काजू और कोको में मूल्य संवर्धन और फसलों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन भी दिए जाएंगे। आवश्यकता के आधार पर काजू और कोको उत्पादक राज्यों में फील्ड दिवस और कोई अन्य अभियान आयोजित किया जाएगा।



वर्ष 2022-23 के दौरान, इस निदेशालय ने किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं के बीच वितरित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में काजू और कोको पर साहित्य मुद्रित करने के लिए विभिन्न अनुसंधान और राज्य विकास एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। निदेशालय ने विभिन्न राज्यों में काजू और कोको पर एक दिवसीय सेमिनार/क्षेत्र दिवस/कार्यशाला आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी। निदेशालय ने 2022 के लिए त्रैमासिक पत्रिका और 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की। दिनांक 30-31 जनवरी 2023 को भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय काजू सम्मेलन के अवसर पर काजू पर एक स्मारिका भी प्रकाशित की गई थी। निदेशालय ने रिपोर्ट वर्ष के दौरान नीचे बताए अनुसार विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लिया और स्टॉल लगाए :

1. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 और 2 नवंबर 2022 को पुणे में बागवानी मूल्य श्रृंखला प्रदर्शनी।
2. भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 11-13 नवंबर 2022 को मुरैना, मध्य प्रदेश में आयोजित कृषि प्रदर्शनी।
3. नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर, दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा 9-12 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आयोजित तीसरा ग्रामोदय मेला और शरदोत्सव।
4. विस्तार प्रभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14-27 नवंबर 2022 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान प्रचार-प्रसार की उपरोक्त गतिविधियों पर कुल 20.843 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

viii) काजू और कोको के लिए मानव संसाधन विकास

योजना का उद्देश्य काजू और कोको क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को प्रबंधकीय और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करके काजू और कोको को बढ़ावा देना है। योजना का घटकवार विवरण इस प्रकार है।

क) काजू और कोको उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह कार्यक्रम, किसानों को काजू और कोको की खेती के विभिन्न पहलुओं जैसे उत्पादन तकनीक, किस्में, उच्च घनत्व रोपण, जैविक खेती, कीट प्रबंधन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन आदि पर उचित प्रशिक्षण प्रदान करता है।

प्रशिक्षण में भाग लेने वालों में कृषक समुदाय के सदस्य, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह, कृषि व्यवसाय को एक पेशे के रूप में अपनाने में रुचि रखने वाली महिलाएं और युवा, कृषि व्यवसाय उद्यमी और काजू और कोको के क्षेत्र में आने वाले किसान शामिल होंगे।

वर्ष 2022-23 के दौरान, इस निदेशालय ने विभिन्न एसएयूएस/अनुसंधान संस्थानों/राज्य विभागों के सहयोग से 64 फील्ड स्तरीय काजू प्रशिक्षण कार्यक्रम और 12 कोको प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 3800 किसानों ने काजू और कोको की विभिन्न उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण का लाभ उठाया। योजना के तहत 22.70 लाख रुपये की राशि खर्च की गयी। उपलब्धि का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है।

काजू

राज्य	कार्यक्रमों की सं.	रकम(रु.)	किसानों की सं.
आंध्रप्रदेश	5	150000	250
छत्तीसगढ़	2	60000	100
गुजरात	5	150000	250
कर्नाटक	9	260000	450
केरल	14	420000	700
महाराष्ट्र	6	180000	300
मध्यप्रदेश	1	30000	50
ओडीशा	2	60000	100
तमिलनाडु	18	540000	900
पश्चिम बंगाल	2	60000	100
कुल	64	1910000	3200



कोको

राज्य	कार्यक्रमों की सं.	रकम(रु.)	किसानों की सं.
आंध्रप्रदेश	2	60000	100
कर्नाटक	4	120000	200
केरल	4	120000	200
तमिलनाडु	2	60000	100
कुल	12	360000	600

ख) काजू एवं कोको में मूल्य संवर्धन पर कौशल विकास प्रशिक्षण

कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों/उद्यमियों/युवाओं को संबंधित अनुसंधान संस्थानों/एसएयूएस में काजू और कोको मूल्यवर्धन में उचित प्रशिक्षण प्रदान करना है। कार्यक्रम की अवधि एक दिन अथवा 3 दिन की होगी।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 25 ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करने के लक्ष्य से कुल 13.65 लाख रुपये प्रदान किए गए थे और इसमें से 9.85 लाख रुपये के परिव्यय के साथ केरल, कर्नाटक और ओडिशा में 11 प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। एजेंसीवार उपलब्धि नीचे दी गई है।

एजेंसी	कार्यक्रमों की सं.	रकम
सीटीसी, यूएचएस, शिवमोगा (बुनियादी ढाँचा सहित)	1	225000
डीसीआर, पुत्तूर	1	75000
ओएससीडीसी, भुवनेश्वर (बुनियादी ढाँचा सहित)	1	223000
सीआरसी, वेल्लानिककरा	6	60000
सीआरसी, वेल्लानिककरा	1	60000
एईईसी, हुविनहडगल्ली	1	335000
कुल	11	978000

ग) किसानों का प्रदर्शन दौरा

इस दौरा का उद्देश्य राज्यों के गैर-पारंपरिक काजू उत्पादक जिलों के आदिवासी और अन्य किसानों को अन्य राज्यों के पारंपरिक उत्पादक जिलों से परिचित कराना है ताकि उन्हें इन राज्यों में अपनाई जाने वाली उत्पादन और प्रबंधन प्रथाओं के बारे में परिचित कराया जा सके। इस योजना के तहत 50 किसानों के एक बैच को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और प्रशिक्षण की अवधि 7 दिन होगी। परियोजना आधारित प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर एमआईडीएच मानदंडों के अनुसार सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, विभिन्न एसएयूएस/अनुसंधान संस्थानों/राज्य विभागों के सहयोग से असम, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य में 4 एजेंसियों द्वारा एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लगभग 200 किसानों ने प्रशिक्षण सुविधा का लाभ उठाया। वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा 11.05 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

एजेंसी	कार्यक्रमों की सं.	किसानों की सं.	रकम(रु.)
आईसीसी, हुविनहडगल्ली	1	50	275000
केवीके, हनुमानमट्टी	1	50	275000
सहेजना, बलाघाट	1	50	275000
एनईओ, असम	1	50	280000
कुल	4	200	1105000

घ) बेरोजगार महिलाओं के लिए काजू सेब के उपयोग पर प्रशिक्षण

काजू आपिल का उपयोग वर्तमान में केवल गोवा में होता है और वह भी किण्वित पेय पदार्थ तैयार करने के लिए। बाकी सभी राज्यों में काजू सेब बर्बाद हो रहा है। काजू आपिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए बेरोजगार महिलाओं को काजू आपिल सिरप तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को राज्य कृषि विश्वविद्यालय के संबंधित अनुसंधान संस्थानों में प्रशिक्षित किया जाता है। अनुसंधान संस्थानों को 25 महिलाओं के एक बैच को प्रशिक्षण देने के लिए 20,000/- रुपये की दर से आकस्मिक व्यय प्रदान किया जाता है।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, काजू आपिल सिरप की तैयारी के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालय और केवीके के अनुसंधान संस्थान में 475 बेरोजगार महिलाओं के लिए प्रशिक्षण के 19 बैच आयोजित किए गए। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों में इस प्रशिक्षण के लिए 0.398 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि सहित 3.648 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। राज्यवार विवरण इस प्रकार है।

राज्य	कार्यक्रमों की सं.	रकम (रु.)	किसानों की सं.
आंध्रप्रदेश	2	40000	50
गुजरात	2	40000	50
कर्नाटक	7	125000	175
केरल	6	120000	150
महाराष्ट्र	2	39810	50
कुल	19	364810	475



च) काजू एवं कोको पर राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों के क्षेत्र में एमआईडीएच के तहत परिकल्पित काजू और कोको की विकासात्मक योजनाओं को लागू करने के लिए विभिन्न विकास विभागों के क्षेत्रीय स्तर के कार्यान्वयन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। उन्हें कृषकों तक आवश्यक कृषि तकनीकों को पहुँचाने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 दिन होगी। प्रशिक्षण किसी अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया जाएगा जैसे काजू अनुसंधान निदेशालय, पुत्तूर, जेएआरएस, ब्रह्मवर, आरएफआरएस, वेंगुर्ला, नाबार्ड संस्थान, मैंगलोर, सीपीसीआरआई, विट्टल, केएयू, वेल्लानिककारा और डीसीसीडी कोचीन। प्रतिभागी सभी काजू/कोको उत्पादक राज्यों से होंगे, जिन्हें बड़े पैमाने पर खेती की संभावनाओं के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। उत्तर-पूर्वी राज्यों को विशेष जोर दिया जाएगा।

वर्ष 2022-23 के दौरान, कोको पर ऐसा एक राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021-22 के स्पिल ओवर लक्ष्य का उपयोग करके विभिन्न कोको उत्पादक राज्यों के 40 अधिकारियों की भागीदारी के साथ बर्ड कैम्पस, मैंगलोर में आयोजित किया गया था। कोको पर एक और राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण 3 से 5 अप्रैल 2023 तक डॉ वाईएसआरएचयू, वीके गुडेम, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था और 40 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। काजू उत्पादक राज्यों के फील्ड तथा विस्तार अधिकारियों के लिए मई-जुलाई 2023 के दौरान केलाडी शिवप्पा नायक कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोग्गा में काजू पर राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। प्रशिक्षण में लगभग 60 अधिकारी भाग लेंगे। वर्ष 2022-23 के दौरान उपरोक्त प्रशिक्षणों के संचालन पर 9.750 लाख रुपये खर्च किए गए।

3.2. आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएम) के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय अभियान और डीसीसीडी द्वारा आयोजित सेमिनार/प्रशिक्षण/कार्यशालाएं

i) काजू पर राष्ट्रीय सम्मेलन, भुवनेश्वर

30 और 31 जनवरी 2023 को ओडिशा राज्य काजू विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से काजू और कोको विकास निदेशालय द्वारा ओडिशा राज्य कन्वेंशन सेंटर, लोक सेवा भवन, भुवनेश्वर में काजू पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन का विषय "काजू के उत्पादन और उत्पादकता के लिए तकनीकी नवाचारों का नकदीकरण" था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान, विकास, उद्योग और विपणन के क्षेत्र में सभी हितधारकों के साथ विभिन्न काजू

उत्पादक राज्यों में काजू की चुनौतियों और अवसरों के बारे में विस्तार से चर्चा करना था। उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भविष्य की विकास रणनीतियों को डिजाइन करना एक अन्य उद्देश्य था। इस प्रकार, सम्मेलन में प्रमुख काजू उत्पादक राज्यों के काजू क्षेत्र के दायरे में आने वाले सभी हितधारकों के साथ गहन चर्चा हुई और काजू के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करके किसानों की आय दोगुनी करने के लिए संभावित रणनीतियों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में वैज्ञानिकों, विकास अधिकारियों, किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों और उद्यमियों सहित लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।



उद्घाटन सत्र की शुरुआत डीसीसीडी के निदेशक डॉ. वेंकटेश एन हुब्ल्ली के स्वागत भाषण से हुई। इस अवसर पर ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक का सद्भावना संदेश सुनाया गया।

डॉ. अरबिंद कुमार पाधी, भाप्रसे, प्रधान सचिव (कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग), ओडिशा सरकार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि वर्तमान युग के जीवन में काजू का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि राज्य में काजू की काफी संभावनाएं हैं, जहां उद्योगों की भूमिका प्रमुख मुद्दा है जिस पर फोरम में चर्चा की जानी चाहिए।

प्रोफ. प्रवत कुमार राउल, कुलपति, ओयूएटी, भुवनेश्वर इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि थे और उन्होंने बताया कि ओडिशा के वर्तमान संदर्भ में इस सम्मेलन का बहुत महत्व है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि ओयूएटी भुवनेश्वर काजू की फसल की वैज्ञानिक खेती के लिए अपनी प्रचार गतिविधियों को जारी रखेगा और कृषक समुदाय को हर संभव सहायता देगा।



भारत सरकार के बागवानी आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार ने अपने भाषण में कहा कि काजू एक उच्च मूल्य वाली फसल है और देश में काजू उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है। इसलिए घरेलू उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण काजू ग्राफ्ट की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक काजू नर्सरी की स्थापना और मान्यता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पुराने पौधों को हटाने और उनके स्थान पर क्षेत्रीय विशिष्ट उच्च उपज देने वाली किस्मों को लगाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से और जनसंचार माध्यमों के उपयोग के साथ बड़े पैमाने पर और गहन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि देश में कच्चे काजू के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनछुए क्षेत्रों में काजू को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाना है। उन्होंने कम से कम समय में उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्यम उच्च सघन रोपण को अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।



ओएससीडीसी लिमिटेड, भुवनेश्वर के अध्यक्ष, श्री सुभाष चंद्र मोहना ने आश्वासन दिया कि उनका निगम काजू की खेती के लाभकारी पहलुओं पर कृषक समुदायों को प्रशिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए सभी उपाय करेगा।

इस अवसर पर एक प्रमोशन जारी की गई, जिसके बाद सर्वश्रेष्ठ काजू किसानों, सर्वश्रेष्ठ काजू नर्सरी और सर्वश्रेष्ठ काजू कार्यान्वयन एजेंसियों को पुरस्कार दिए गए। उद्घाटन समारोह का समापन ओएससीडीसी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, श्री सदानंद नायक, आईएस, के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

तकनीकी सत्र

उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद तकनीकी सत्र प्रारंभ हुआ। ऐसे कुल चार तकनीकी सत्र थे। सम्मेलन में काजू क्षेत्र की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, निर्यात और औद्योगिक आवश्यकताओं से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की गई और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उपयुक्त सिफारिशों की गईं:

सिफारिशें

1. डीसीसीडी काजू क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ कई बैठकें आयोजित करें और काजू के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति विकसित करें तथा अगले 10 वर्षों के लिए काजू विकास के लिए एक रोड मैप भी तैयार करें।
2. काजू की उत्पादकता में जीर्ण बागान एक बड़ी बाधा है और ऐसे बागान कुल काजू क्षेत्र का लगभग 30% हैं। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, मौजूदा पुराने काजू बागानों को उच्च उपज देने वाली किस्मों के साथ पुनरोपण करके और अच्छी कृषि पद्धतियों को अपनाकर उत्पादक काजू बागान में बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए।
3. काजू एप्पल का उपयोग गोवा राज्य में फेनी के उत्पादन के लिए सफलतापूर्वक किया जाता है और इसी मॉडल को अन्य राज्यों में भी दोहराए जाने की आवश्यकता है।
4. सिवाय आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के, बाकी सभी राज्यों में 15 अगस्त तक नए रोपण कार्य पूरा करना चाहिए। तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में उत्तर पूर्व मानसून के दौरान अच्छी वर्षा होती है।
5. किसानों को वितरण हेतु न्यूनतम 6 माह के आयु की गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का चयन किया जाना चाहिए।
6. डीसीसीडी को जहां भी अच्छे उद्यमी उपलब्ध हों, वहां काजू नर्सरी की स्थापना और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
7. काजू नर्सरी की मान्यता को प्राथमिकता दी जायेगी तथा प्रत्येक वर्ष जून माह से पहले नर्सरी का निरीक्षण कराया जाये।
8. कम से कम समय में उत्पादन बढ़ाने के लिए नए रोपण कार्यक्रम में प्रति हेक्टेयर 400 पौधों वाले मध्यम उच्च सघन रोपण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
9. अनुसंधान संगठनों को भी बौनी किस्मों के मूल्यांकन और विमोचन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।



10. गोवा सरकार कच्चे नट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती है और काजू की खेती को बढ़ावा देने और अधिक क्षेत्र काजू की खेती के अधीन लाने के लिए इसे अन्य राज्यों में भी दोहराया जा सकता है।
11. कच्चे नट का आयात अधिकतर कमीशन एजेंटों द्वारा किया जाता है। आयात शुल्क को 10% से घटाकर 2.5% करने से घरेलू कच्चे नट की कीमत में भारी गिरावट आई है। इसलिए किसानों के लिए लाभकारी मूल्य बनाए रखने के लिए सरकार को चाहिए कि वे आयात शुल्क को 2.5% से बढ़ाकर 10% करने पर पुनर्विचार करें।
12. उच्च सघन रोपण के लिए सबसे उपयुक्त किस्मों की पहचान करने के लिए सत्यापन किए जाने की आवश्यकता है।
13. काजू बागान की स्थापना की सर्वोत्तम सफलता दर प्राप्त करने के लिए, विकास विभाग तीन जिलों में नए रोपण कार्यक्रम के क्लस्टर दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
14. सफलता की उच्च दर के लिए बड़े बैगों के साथ एक वर्ष या उससे अधिक आयु की रोपण सामग्री को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए फ़ील्ड परिणाम पहले से ही उपलब्ध हैं।
15. काजू क्षेत्र में तना व जड़ वेधक का नियंत्रण अभी भी एक प्रमुख मुद्दा है और अनुसंधान संगठन इस कीट के प्रभावी नियंत्रण उपायों को विकसित करने में अधिक जोर दे सकते हैं।
16. डीसीसीडी की वित्तीय सहायता से एफएलटीडी के रूप में विभिन्न अनुसंधान संगठनों द्वारा जारी नई किस्मों का किसान के खेत में परीक्षण किया जा सकता है।
17. कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने और विभिन्न मुद्दों का समाधान खोजने के लिए हर छह महीने में विकास विभागों और अनुसंधान संगठनों के बीच नियमित इंटरफ़ेस बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।

ii) भारत सरकार के सचिव (ए एवं सी) द्वारा डीसीसीडी का दौरा

माननीय सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण) श्री मनोज आहूजा आईएएस और श्री संजीव कुमार आईएएस, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार ने 19 अक्टूबर 2022 को काजू और कोको विकास निदेशालय तथा नारियल विकास बोर्ड का दौरा किया और तीनों फसलों के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की।



iii) काजू और कोको, गोवा पर इंटरफ़ेस बैठक की रिपोर्ट

काजू और कोको पर इंटरफ़ेस बैठक 27 अगस्त 2022 को भारत सरकार के बागवानी आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार की अध्यक्षता में पंजिम-गोवा में आयोजित की गई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य काजू और कोको के विकास में आने वाले मुद्दों का पता लगाना और अगले पांच वर्षों के लिए एक कार्य योजना के रूप में एक विकासात्मक रणनीति विकसित करना था ताकि काजू और कोको में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम किया जा सके। बैठक में काजू उत्पादक राज्यों के बागवानी/कृषि विभाग के निदेशक, काजू निगमों के प्रबंध निदेशक, आईसीएआर संस्थान और कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक, काजू और कोको उद्योग के प्रतिनिधि, नर्सरी मालिक और नवोन्मेषी किसान शामिल हुए। बैठक की शुरुआत काजू और कोको विकास निदेशालय के निदेशक डॉ. वेंकटेश एन हुब्ल्ली के स्वागत भाषण से हुई। अपने अध्यक्षीय भाषण में बागवानी आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार ने काजू और कोको को अधिक लाभदायक उद्यम के रूप में विकसित करने में भारत सरकार की पहल का समर्थन करने के लिए सभी खिलाड़ियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आरकेवीवाइ/एमआईडीएच के तहत परियोजना आधारित गतिविधि द्वारा उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता भी बताई। उनके संबोधन में उचित सिंचाई सुविधाओं, विपणन सुविधाओं और एफपीओ को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।





डॉ. वेंकटेश एन हुब्ल्ली ने भारत में काजू और कोको के विस्तृत परिदृश्य और काजू और कोको को बढ़ावा देने में भारत सरकार की पहल पर प्रकाश डाला। उन्होंने देश में कच्चे नट और कोको बीन्स का क्षेत्र-विस्तार करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में कच्चे नट के आयात की गारंटी नहीं दी जा सकती क्योंकि निर्यातक देशों ने अपना स्वयं का प्रसंस्करण कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने मुद्दों पर काबू पाने के लिए भविष्य की रणनीतियों के बारे में भी विस्तार से बताया और विशेष रूप से काजू में उच्च सघन रोपण को अपनाकर उत्पादन बढ़ाने के लिए पांच साल की योजना बताई।

बैठक में एकत्र हुए विशेषज्ञों ने कहा कि काजू क्षेत्र के खेतों, कारखानों और विपणन क्षेत्र में 15 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं और अब यह उद्योग कई कारकों के कारण संघर्षपूर्ण स्थिति में है। इसलिए उद्योग को बचाने के लिए आयात को नियंत्रित करने, हितधारकों को प्रोत्साहन प्रदान करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय काजू को बढ़ावा देने, उच्च सघन रोपण को बढ़ावा देने और पुराने बागानों के पुनर्रोपण को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी-सक्षम खेती विकसित करने और प्रसंस्करण के माध्यम से उद्योग को बचाने की आवश्यकता है। काजू अनुसंधान निदेशालय, पुत्तूर के निदेशक डॉ. टीएन रविप्रसाद ने काजू अनुसंधान की स्थिति और भविष्य की रणनीतियों पर एक विस्तृत भाषण दिया और काजू तना व जड़ वेधक को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों, तथा क्षेत्र विशेष के लिए उच्च सघन रोपण के लिए विशेष किस्मों की पहचान आदि की आवश्यकता के बारे में बताया।

ओडिशा राज्य काजू विकास निगम के प्रबंध निदेशक, आईएएस, श्री.सदानंद नायक ने ओएससीडीसी द्वारा किए जा रहे काजू पुनर्रोपण कार्यक्रम की स्थिति प्रस्तुत की। मृदा संरक्षण, भुवनेश्वर के निदेशक श्री हेमंता कुमार पांडा ने एमजीएनआरईए के तहत काजू विकास में क्लस्टर दृष्टिकोण के महत्व को समझाया, जिसमें सरकारी विभाग तीन से पांच साल तक बागानों का रखरखाव करते हैं और बाद में इन्हें विभिन्न लाभार्थियों को सौंप दिया जाता है। डॉ. बी सुमा, प्रोफेसर और प्रमुख, केएयू, त्रिशूर और डॉ. ई अप्सरा, प्रधान वैज्ञानिक, सीपीसीआरआई, विट्टल ने अपने संस्थानों में उच्च उपज देने वाली किस्मों, बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकियों आदि पर चल रहे शोध पर प्रकाश डाला। डॉ. जलजा, सहायक प्रोफेसर और प्रमुख, सीआरएस, मदाकतरा ने राज्य में काजू विकास परिदृश्य और काजू एप्पल के कई उपयोगों पर विस्तार से बताया। ओडिशा सरकार के अपर निदेशक डॉ. प्रदोष पांडा ने ओडिशा राज्य में काजू के विकास में केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। नर्सरी मालिकों और उन्नतशील किसानों ने भी काजू की खेती में विभिन्न मुद्दे व्यक्त किए थे।

विस्तृत चर्चा और सुझावों के बाद कार्रवाई योग्य बिंदुओं को संबंधित संगठनों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आगे रखा गया।

iv) कोको पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर रिपोर्ट

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य के विकास विभागों के अधिकारियों के लाभार्थ, डीसीसीडी ने कोको पर राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक बी.आई.आर.डी. कैंपस, नाबार्ड, मैंगलोर में आयोजित किया। राष्ट्रीय स्तर के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से कुल 40 अधिकारियों ने भाग लिया।

डीसीसीडी के निदेशक डॉ. वेंकटेश एन हुब्बल्ली तथा नाबार्ड के संकाय सदस्य श्री सतीसन कर्ता ने इस राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समारोह में डॉ. तमिलसेल्वन एम., निदेशक (सेवानिवृत्त), डीएसडी, कालीकट और श्री आर ज्ञानदेवन, सलाहकार, डीसीसीडी उपस्थित थे। अपने परिचयात्मक भाषण में, डॉ. वेंकटेश एन हुब्बल्ली ने राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताया और भारत में कोको के परिदृश्य और कोको की खेती को बढ़ाने में निदेशालय की गतिविधियों पर भी संक्षेप में प्रकाश डाला।



उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र शुरू हुआ। प्रशिक्षण के इन दो दिनों के दौरान, विशेषज्ञों द्वारा निम्नलिखित विस्तृत प्रस्तुतियाँ और विचार-विमर्श किए गए।

डॉ. बी सुमा, प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीआरसी, केएयू ने कोको की किस्मों और कृषि तकनीकों के सभी पहलुओं को कवर किया। कोको में प्रशिक्षण और छंटाई तकनीकों पर एक सत्र का नेतृत्व भी डॉ. सुमा ने किया। डॉ. जे एस मिनिमोल, प्रोफेसर, कोको रिसर्च स्टेशन, केएयू ने एक विस्तृत स्लाइड शो प्रस्तुत किया और कोको में कटाई के बाद का प्रबंधन और मूल्य संवर्धन पर कक्षा ली। डॉ. एस एलेन अण्णारा, प्रधान वैज्ञानिक, आईसीएआर-सीपीसीआरआई, विट्टल ने कोको और ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसंधान परिदृश्य पर एक विस्तृत स्लाइड शो प्रस्तुत किया। डॉ. अण्णारा द्वारा



कोको के फेनोलॉजिकल अध्ययन पर एक कक्षा भी ली गई। सीपीसीआरआई, विट्टल की वैज्ञानिक (पादप रोगविज्ञान) डॉ चैत्रा एम और वैज्ञानिक (कृषि कीट विज्ञान) डॉ मधु टीएन ने कोको में कीटों के जैविक नियंत्रण सहित कीट और रोग प्रबंधन के विस्तृत पहलुओं को प्रस्तुत किया।

कोको के चिकित्सीय और पोषण संबंधी लाभों पर एक कक्षा का नेतृत्व कृषि और बागवानी अनुसंधान स्टेशन, कपिकाड, उल्लाल के एसोसिएट प्रोफेसर (बागवानी) डॉ. रविराजा शेटी ने किया। कैपको, मैंगलोर के अधिकारी श्री श्रीनिवास ने चॉकलेट के वाणिज्यिक उत्पादन के विस्तृत पहलुओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से चॉकलेट बनाने में अपनाई जाने वाली प्रसंस्करण तकनीकों के विस्तृत दृश्य के लिए कैपको कारखाने का दौरा करने का भी अनुरोध किया। वाराणसी ऑर्गेनिक फार्म, मैंगलोर के श्री पार्थ वाराणसी ने कोको की जैविक खेती और जैविक प्रमाणीकरण हासिल करने में शामिल नीतिगत मामलों के बारे में विस्तार से बताया। मॉन्डेलिज़ फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कोको ऑपरेशंस के प्रमुख श्री रूपक भट्ट ने भारत में कोको के विपणन और मूल्य श्रृंखला विश्लेषण के साथ-साथ कोको की वैश्विक बाजार स्थिति प्रस्तुत की।



श्री ज्ञानदेवन, सलाहकार, डीसीसीडी ने बताया कि किस प्रकार कोको, जब नारियल के साथ एक अंतरफसल के रूप में उगाया जाता है, किसानों की आय को दोगुना करने में सहायक होता है। सभी प्रतिभागियों ने डीसीसीडी द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्राप्त बहुमूल्य जानकारी के बारे में प्रसन्नता व्यक्त की और नियमित आधार पर ऐसे और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया। प्रशिक्षण सत्र के अंत में, प्रतिभागियों के लिए कोको की खेती पर एक परीक्षण आयोजित किया गया और विजेताओं को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया।

तीसरे दिन, सभी प्रतिभागियों ने कैम्पको चॉकलेट फैक्ट्री का दौरा किया और कोको मक्खन के निष्कर्षण की प्रसंस्करण तकनीक, कोको द्रव्यमान और कोको पाउडर को अलग

करने की तकनीक और विभिन्न प्रकार की चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया देखने का अवसर मिला। आईसीएआर-सीपीसीआरआई, विट्टल का दौरा भी आयोजित किया गया था, जिसमें डॉ. एलेन अप्सरा, प्रधान वैज्ञानिक, आईसीएआर-सीपीसीआरआई, विट्टल ने प्रतिभागियों को प्रूनिंग और छंटाई के व्यावहारिक पक्ष का प्रदर्शन किया और कोको बीन्स के किण्वन के विभिन्न तरीकों का भी प्रदर्शन किया जो उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। सत्र के समापन समारोह में लिखित परीक्षा के विजेताओं को स्मृति चिन्ह वितरित किए गए, जिसके बाद श्री निखिल वीएम, डीसीसीडी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया।

v) 'किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी' अभियान: कोको सेमिनार

'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत 'किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी' अभियान मनाने के एक भाग के रूप में, काजू और कोको विकास निदेशालय ने वाषतोप्पु ग्राम पंचायत, कुदुम्बश्री, कृषि भवन, मॉडलेज इंडिया लिमिटेड और एएफपीआरओ के सहयोग से दिनांक 26/04/2022 को केरल के इडुक्की जिले के वाषतोप्पु पंचायत में कोको पर एक सेमिनार का आयोजन किया। वाषतोप्पु ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष ने कहा कि पंचायत में कोको की खेती के एकीकृत विकास की व्यापक गुंजाइश है और एमआईडीएच के तहत कोको विकास योजनाओं को पंचायत तक बढ़ाया जा सकता है। संगोष्ठी में लगभग 300 किसानों, जिनमें अधिकतर महिलाएँ थीं, ने भाग लिया। इस अवसर पर तीन सफल महिला किसानों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने उत्पादन दोगुना करने के लिए उन्नत खेती के तरीके अपनाए थे। इस अवसर पर एमआईडीएच की गतिविधियों को दर्शाती एक प्रदर्शनी भी लगाई गई।



अपने संदेश में, निदेशक, डीसीसीडी ने बताया कि 2005 के बाद से डीसीसीडी के प्रयासों से, 70,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कोको के अंतर्गत लाया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि इडुक्की जिले के कोको किसानों को एमआईडीएच योजना के तहत डीसीसीडी द्वारा आगे भी समर्थन दिया जाएगा।



डॉ जे एस मिनिमोल, प्रोफेसर, कोको रिसर्च सेंटर, केएयू ने 'कोको में प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन' विषय पर एक व्याख्यान दिया जो अत्यधिक इंटरैक्टिव था। डॉ. मिनिमोल द्वारा घर में बनी चॉकलेट तैयार करने पर एक छोटा सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाया गया।

मॉडेलिज इंडिया लिमिटेड के एक वरिष्ठ तकनीकी कार्यकारी ने कोको डिजी-ऐप के बारे में बताया, जो कोको की विभिन्न खेती प्रथाओं को समझाता है और संचालन के कैलेंडर को साझा करता है। ऐप में किसानों के पंजीकरण का प्रावधान है। इसके अलावा, प्रतिभागियों को प्रगतिशील कोको किसान श्री सुनील के मॉडल कोको उद्यान का दौरा करने के लिए ले जाया गया ताकि उनके द्वारा अपनाई गई छंटाई तकनीकों, खेती के तरीकों और कीट और रोग प्रबंधन की तकनीक का प्रदर्शन किया जा सके। कार्यक्रम को मलयाला मनोरमा, मंगलम जैसे सभी स्थानीय समाचार पत्रों और डीडी मलयालम और केरल विजन के टीवी चैनलों द्वारा कवर किया गया था।

vi) 'किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी' अभियान: काजू और कोको मेला

केलाडी शिवप्पा नायक कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोग्गा के सहयोग से काजू और कोको विकास निदेशालय ने 28.04.2022 को केएसएनयूएचएस परिसर, शिवमोग्गा में 'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम के अधीन 'किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी' अभियान के तहत काजू और कोको मेले का आयोजन किया।



कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, अनुसंधान स्टेशन के पास उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकियों और उच्च उपज देने वाली किस्मों को उजागर करना और विशेषज्ञों और नवोन्वेषी किसानों के साथ बातचीत के माध्यम से कृषि समुदाय के बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने में मदद करना था। काजू और कोको की खेती के लाभों को आगे बढ़ाने के लिए टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया जैसे मास मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था, जिससे पता चलता है कि ये फसलें छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती

हैं। डॉ. वेंकटेश एन हुब्बल्ली, निदेशक, काजू और कोको विकास निदेशालय, डॉ. एम हनुमंतप्पा, केलाडी शिवप्पा नायक कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोग्गा के कुलपति और विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी, बोर्ड के सदस्य और बागवानी निदेशालय जैसे हितधारक, मॉडलेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कैंपको ने कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें मौजूदा तकनीकों को उजागर करने के लिए प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। अधिक उपज देने वाली किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई और बैनर भी प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर काजू और कोको के 3 नवोन्वेषी किसानों को सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने काजू और कोको की बेहतर उपज प्राप्त करने में बहुत अच्छे परिणाम हासिल किए थे। शिवमोग्गा के आसपास के जिलों से लगभग 1000 किसानों ने भाग लिया। दूरदर्शन, पावर टीवी, नम्मा शिवमोग्गा, टीवी भारत जैसे टेलीविजन चैनल और नम्मा सहाद्री जैसे यूट्यूब चैनल और न्यू इंडियन एक्सप्रेस, विजयवाणी, प्रजावाणी, विजया कर्नाटक, संयुक्त कर्नाटक, जना होराटा और न्यूज जैसे प्रिंट मीडिया ने कार्यक्रम को कवर किया और इस तरह इसे व्यापक प्रचार मिला।

vii) चेंगलायी पंचायत, कन्नूर में नारी शक्ति मेला

काजू और कोको विकास निदेशालय, कोच्चि ने 25.11.2022 को चेंगलायी ग्राम पंचायत, कन्नूर में नारीशक्ति मेला का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री ए जनार्दन, अध्यक्ष, स्थायी समिति (विकास) के स्वागत भाषण से हुई। डीसीसीडी के उप निदेशक श्री दादासाहेब देसायी ने चेंगलायी ग्राम पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती के एम शोभना को अच्छी गुणवत्ता वाले काजू के कलमें सौंपकर समारोह का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री. दादासाहेब देसायी ने काजू क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य और शिक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री प्रजोश और वार्ड सदस्य श्री आशिक चेंगलाई भी समारोह में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह के बाद महिला किसानों के लिए वैज्ञानिक खेती पद्धतियों पर काजू सेमिनार आयोजित किया गया। काजू अनुसंधान निदेशालय, पुत्तूर के वरिष्ठ वैज्ञानिक (मृदा विज्ञान) डॉ. शमसुद्दीन मंगलसेरी ने रोपण से पहले मिट्टी परीक्षण के महत्व, कलमों का चयन, रोपण, आईएनएम/आईपीएम प्रथाओं और काजू में कटाई के बाद के प्रबंधन जैसे विषयों पर एक कक्षा का नेतृत्व किया।

श्री ब्रिजिथ कृष्णा, सीईओ और संस्थापक, ईटरी मालाबारिकस, कन्नूर ने काजू प्रसंस्करण के महत्व पर एक पेपर प्रस्तुत किया और काजू के अंकुरित उत्पादों का प्रदर्शन किया। अपनी प्रस्तुतीकरण में उन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अंकुरित उत्पादों की संभावनाओं पर जोर दिया और लघु उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया। श्री जिनेश कल्याणी, निदेशक, इरिक्कुर एग्रो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, पय्यावुर, कन्नूर ने काजू क्षेत्र में किसान-उत्पादक संगठन के दायरे पर एक पेपर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में लगभग 150 महिला किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में काजू के मूल्य वृद्धि उत्पादों के दायरे और लघु उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की गुंजाइश को भी उजागर



किया। कार्यक्रम का समापन श्री निखिल वी एम, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, डीसीसीडी के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।



viii) नारी शक्ति मेला, किडू, कर्नाटक

काजू और कोको विकास निदेशालय, कोच्चि ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में 21.11.2022 को आईसीएआर-सीपीसीआरआई क्षेत्रीय केंद्र, किडू, कर्नाटक में नारी शक्ति मेले का आयोजन किया। कार्यक्रम में लगभग 500 महिला किसानों ने भाग लिया और उन्हें कोको के उत्पादन और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों से अवगत कराया गया। मत्स्य पालन, बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन मंत्री श्री एस अंगारा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने नारियल, सुपारी, कोको, केला, काली मिर्च, काजू और क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त अन्य फलों के पेड़ों और वन प्रजातियों जैसे स्थानीय महत्व की फसलों के साथ बहु प्रजाति फसल प्रणाली उगाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उचित छंटाई और प्रबंधन के साथ व्यवस्थित रूप से कोको उगाने के दायरे और महत्व और प्रसंस्करण में अवसरों पर प्रकाश डाला। डॉ. एलेन अप्सरा, प्रधान वैज्ञानिक (बागवानी) और डॉ. चैत्रा, वैज्ञानिक (पादप रोगविज्ञान), सीपीसीआरआई, आरएस, विट्टल ने ताड़ आधारित मिश्रित फसल प्रणालियों में कोको की खेती, सीपीसीआरआई से जारी कोको किस्मों, नर्सरी प्रबंधन, उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों, एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन, प्राथमिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी और चॉकलेट बनाने के तरीके जैसे विषयों पर विस्तार से बताया। कार्यक्रम में कुल 500 महिलाओं ने भाग लिया।



ix) काजू पर जागरूकता कार्यक्रम, आलक्कोड, कन्नूर

इस निदेशालय द्वारा 25.07.2022 को आलक्कोड में काजू पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। काजू पर जागरूकता कार्यक्रम में लगभग 150 काजू किसानों ने भाग लिया। आलक्कोड ग्राम पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती आयशा पी सी ने जागरूकता कार्यक्रम में किसानों और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का उद्घाटन आलक्कोड ग्राम पंचायत के अध्यक्ष श्री जोजी कनिकक्कट्टू ने किया। उन्होंने क्षेत्र में काजू किसानों के सुधार के लिए इस निदेशालय की पहल पर प्रकाश डाला। काजू सेल के अध्यक्ष श्री जोस पूमाला ने अध्यक्षीय भाषण दिया। उन्होंने काजू के चरम सीजन के दौरान कच्चे काजू की कीमत में उतार-चढ़ाव के मुद्दों की ओर इशारा किया और किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करने का, इस निदेशालय से अनुरोध किया।



श्री रवींद्र कुमार, उप निदेशक, डीसीसीडी ने मुख्य भाषण प्रस्तुत किया और अपने भाषण में उन्होंने इस निदेशालय द्वारा काजू और कोको की विकास गतिविधियों और क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमों के बारे में बताया। इस अवसर पर श्री जॉय तारमंगलम, रायरोम (सर्वश्रेष्ठ काजू किसान) और श्रीमती शेर्ली संतोष, ओलिवकल, मेरीगिरी (सर्वश्रेष्ठ महिला किसान) को सम्मानित किया गया। उद्घाटन सत्र श्री निखिल वीएम, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, डीसीसीडी, कोचीन के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुआ।

अपराह्न 03.30 बजे तक चले तकनीकी सत्र में क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, पिलीकोड की सहायक प्रोफेसर डॉ. मीरा मंजूषा ने काजू की खेती पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

x) बलाल, कासरगोड में काजू प्रशिक्षण

निदेशालय ने 6 मार्च 2023 को बलाल ग्राम पंचायत में काजू के नए रोपण कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए एक-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में लगभग 50 काजू किसानों ने भाग लिया। विकास कार्य स्थायी समिति, बलाल ग्राम पंचायत के अध्यक्ष श्री



एलेक्स नेदियाकलायिल ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन बलाल ग्राम पंचायत के अध्यक्ष श्री राजू कट्टक्कयम ने किया, जिन्होंने किसानों को काजू में अंतरफसल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। काजू सेल के अध्यक्ष श्री जोस पूमाला ने समारोह की अध्यक्षता की और उन्होंने क्षेत्र में काजू किसानों की भलाई के लिए सब्सिडी प्रदान करने में इस निदेशालय की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया।



श्री. विनीत लुकोस, डीसीसीडी ने इस निदेशालय द्वारा कार्यान्वित काजू और कोको की विकासात्मक गतिविधियों और क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमों के बारे में बताया। डॉ. मीरा मंजूषा, सहायक प्रोफेसर, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन, पिलीकोड ने काजू में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन पर एक विस्तृत कक्षा ली। तकनीकी सत्र के बाद, किसानों को फील्ड दौरे के लिए पास के काजू बागान में ले जाया गया, जहां कीट और रोग प्रबंधन के संबंध में कई प्रश्नों का समाधान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन श्रीमती अनन्या सुसान, डीसीसीडी, कोचीन के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

xi) 'कर्षका सेमिनार', कलगशशेरी पर रिपोर्ट

'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में 31 अगस्त 2022 को कलगशशेरी सरकारी गेस्ट हाउस हॉल में काजू और कोको विकास निदेशालय के वित्तीय सहयोग से विश्वमाता चौरिटेबल फाउंडेशन, कलगशशेरी द्वारा कोको पर एक 'कर्षका सेमिनार' (किसान संगोष्ठी) आयोजित किया गया था। सेमिनार की अध्यक्षता विश्वमाता चौरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री सुनील अरविंद ने की। इस अवसर पर डीसीसीडी के सलाहकार श्री आर ज्ञानदेवन ने काजू और कोको विकास पर एक प्रामाणिक कक्षा ली। समारोह में कृषि और समाज के क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया गया। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण जेट टीवी द्वारा किया गया।



xii) बागवानी विभाग, तमिलनाडु से अध्ययन दल का दौरा

श्रीमती एस. भुवनेश्वरी, बागवानी सहायक निदेशक, पूर्वी मद्रुरै के नेतृत्व में तमिलनाडु बागवानी विभाग के 10 तकनीकी अधिकारियों की एक अध्ययन टीम ने दिनांक 17/05/2022 को डीसीसीडी का दौरा किया। डीसीसीडी के उप निदेशक श्री दादासाहेब देसाई ने अधिकारियों का स्वागत किया और इस निदेशालय की गतिविधियों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। इस अवसर पर भारत, विशेषकर तमिलनाडु में, काजू और कोको की स्थिति पर भी चर्चा की गई।



xiii) प्रदर्शनियों में भागीदारी

क) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

निदेशालय ने 14 से 27 नवंबर 2022 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया था। मेले की थीम 'वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल' थी और निदेशालय ने तदनुसार काजू और कोको के स्थानीय रूप से प्रसंस्कृत उत्पादों को दर्शाते हुए एक स्टॉल लगाया था। इसके अलावा काजू एवं कोको के विकास एवं संवर्धन के संबंध में निदेशालय



की विभिन्न गतिविधियों को भी दर्शाया गया। डॉ. एन.के. पटले, अपर आयुक्त (बागवानी), डॉ. विजया लक्ष्मी नाडेंडला आईएस, अध्यक्ष, सीडीबी, श्री राजीव जैन, सेवानिवृत्त उप सचिव और अन्य व्यावसायिक प्रमुखों ने स्टॉल का दौरा किया।



ख) ग्रामोदय मेला, चित्रकूट, मध्य प्रदेश

निदेशालय ने 09 से 12 अक्टूबर 2022 तक मध्य प्रदेश के चित्रकूट में दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ग्रामोदय मेला (शरदोत्सव) के तीसरे संस्करण में भाग लिया। ग्रामोदय मेला श्री नानाजी देशमुख की जयंती पर और 'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। प्रदर्शनी का विषय केंद्र और राज्य सरकार के तहत विभागों की योजनाओं और गतिविधियों की प्रगति और विकास के साथ-साथ राज्य और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना था। तदनुसार, निदेशालय ने भारत में काजू और कोको को बढ़ावा देने के लिए निदेशालय की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाते हुए काजू और कोको के फ्लेक्स और लाइव सामग्री प्रदर्शित करने वाला एक स्टॉल लगाया। स्टाल पर राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के अधिकारियों और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के कई लोगों ने दौरा किया।



4

प्रशासनिक मामले

4.1 निदेशालय में सूचना का अधिकार

वर्ष 2022–23 के दौरान, इस निदेशालय को विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुरोध प्राप्त हुए थे। इस अवधि के दौरान, श्री पी ए परमेस्वरन, प्रशासनिक अधिकारी को सीपीआईओ के रूप में और डॉ वेंकटेश एन हुब्ल्ली, निदेशक अपीली प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया था। संशोधित प्रोफार्मा की धारा 4 जानकारी इस वर्ष में तैयार की गई है और निदेशालय की वेबसाइट में अपलोड की गई है। सभी संभावित जानकारी जो सार्वजनिक डोमेन के तहत लाई जा सकती है, को संशोधित धारा 4 प्रोफार्मा में शामिल किया गया है। संशोधित धारा 4 की जानकारी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) को भी उपलब्ध कराई गई है, जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पारदर्शिता लेखापरीक्षा करने के लिए नामित एजेंसी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्त कुल अनुरोध	निपटाए गए अनुरोधों की संख्या	कितने में सूचना मना किया गया	कितने अपील मिले
08	08	शून्य	शून्य

4.2 सतर्कता जागरूकता सप्ताह तथा विशेष अभियान 2.0

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 16/08/2022 से 15/11/2022 तक निदेशालय में निवारक सतर्कता उपाय एवं हाउस-कीपिंग गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। इस अवधि के दौरान, उचित रिकॉर्ड प्रबंधन और परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कदम उठाए गए और साथ ही डीसीसीडी की नई वेबसाइट आदि के लिए सिस्टम अध्ययन के माध्यम से प्रौद्योगिकी पहल की गई।

लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, लंबित मामलों को न्यूनतम संभव स्तर तक कम करने के लिए लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 2.0 दिनांक 02/10/2022 से 31/10/2022 तक मनाया गया। स्वच्छता अभियान के साथ चलाया गया यह अभियान सफल रहा क्योंकि कार्यालय परिसर की सफाई की गई और पुराने रिकॉर्ड/फाइलें आदि हटा दिए गए। श्री दादासाहेब देसायी, उप निदेशक इस अभियान के लिए नोडल अधिकारी थे और डेटा नियमित रूप से डीएआरपीजी पोर्टल पर अपलोड किया गया था। विशेष अभियान में की गई गतिविधियों का विवरण नीचे सूचीबद्ध है।



क्र.सं.	गतिविधियाँ	संख्या
1	स्वच्छता अभियान	3
2	रिकॉर्ड प्रबंधन (फाइलो की बहाली)	815
3	रिकार्ड प्रबंधन (फाइल वीडिंग)	357

4.3 दिव्यांग-जन संबंधी रिपोर्ट

दिव्यांग-जन अधिनियम, 2016 की धारा 23 (प) के अनुसार निदेशालय ने पहले ही शिकायत निवारण अधिकारी नामित कर दिया है। अधिकारी का विवरण निदेशालय की वेबसाइट और कार्यालय परिसर के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया गया है। दिव्यांग-जनों के लिए उपयुक्त पहचाने गए मौजूदा पदों की समीक्षा की गई है और पहचाने गए तथा गैर-पहचानित दोनों पदों के लिए एक सूची तैयार की गई है। डीओपीटी के निर्देशानुसार दिव्यांग-जनों के लिए नया आरक्षण रोस्टर तैयार कर लिया गया है और इसे लागू कर दिया गया है। दिव्यांग जन नियम, 2017 के नियम 9 और नियम 10 के तहत निर्धारित संबंधित रजिस्ट्रों का रखरखाव किया जा रहा है।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, दिव्यांग-जन के लिए आरक्षित अवर श्रेणी लिपिक का एक पद कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामित उम्मीदवार द्वारा भरा गया है।

4.4 राजभाषा कार्यान्वयन रिपोर्ट 2022-23

काजू और कोको विकास निदेशालय में राजभाषा कार्यान्वयन की उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ उठाए गए कदम तथा राजभाषा नियम एवं आदेशों के पालन का संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत है।

क) राजभाषा वार्षिक कार्य योजना

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर यह निदेशालय अपने कार्यकलापों और कार्यकारी आवश्यकताओं के मद्देनजर एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करते हैं जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को विशेष प्रधानता दी जाती है। इस वार्षिक कार्य योजना का उद्देश्य न केवल निदेशालय के आंतरिक कार्यकलापों में राजभाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देना है बल्कि निदेशालय के सभी पणधारकों के बीच भी बढ़ावा देना है, जिनमें किसान, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य सरकारी कार्यालय आदि मुख्य हैं।

ख) हिन्दी प्रशिक्षण

निदेशालय के सभी कर्मचारी या तो प्रशिक्षित हैं या उन्हें कार्यसाधक ज्ञान है। तीन कर्मचारी प्रवीणता प्राप्त हैं और उन्हें राजभाषा नियम के नियम 8(4) के अधीन व्यक्तिशः आदेश जारी

कर चुके हैं। रिपोर्ट वर्ष के दौरान, निदेशालय के कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को एक सप्ताह के अनुवाद पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए नामांकित किया गया और सीटीबी, बेंगलूर में 27/03/23 से 31/03/23 तक प्रशिक्षण दिलाया गया। सेवा में शामिल होने के समय उन्होंने तीन महीने का सेवाकालीन दीर्घकालिक पाठ्यक्रम पहले ही पूरा कर लिया था।

ग) धारा 3(3) का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत आने वाले सभी दस्तावेज़ द्विभाषी रूप में ही जारी किए गए हैं। अतः निदेशालय में धारा 3(3) का अनुपालन शतप्रतिशत है।

घ) राजभाषा नियम 1976 का नियम (5)

राजभाषा नियम 1976 के नियम(5) का अनुपालन करते हुए हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के हिन्दी में ही उत्तर दिए गए हैं।

च) राजभाषा नियम 1976 का नियम(11)

राजभाषा नियम 1976 के नियम (11) का कार्यान्वयन करते हुए सभी मोहरें, नाम पट्ट, साइन बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में ही बनाए हैं।

छ) हिन्दी कार्यशाला

निदेशालय में रिपोर्ट वर्ष के दौरान तीन कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण(28/09/22) दौरे की वजह से दूसरी तिमाही के दौरान कार्यशाला नहीं हो पाई। पहली तिमाही के दौरान दिनांक 29/06/22 को निदेशालय के कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा व्याकरण विषय पर कार्यशाला चलाई गई।

तीसरी तिमाही के दौरान निदेशालय में दिनांक 26/10/22 को कोचिन नगर के समस्त केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों के राजभाषा से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक तकनीकी कार्यशाला चलाई गई। भारतीय रिसर्व बैंक की कोचिन शाखा के राजभाषा प्रबंधक डॉ मधुशील आयिल्यत ने कक्षा चलाई। निदेशालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ कोचिन के 15 अन्य कार्यालयों के राजभाषा कर्मियों ने भाग लिया।

चौथी तिमाही के दौरान दिनांक 27/02/23 को निदेशालय के कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने कंप्यूटर में हिन्दी में काम करने का प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला के पहले सत्र में सैद्धांतिक पक्ष पर कक्षा चलाई गई तथा दूसरे सत्र में सबके सीट में जाकर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।



ज) हिन्दी दिवस/पखवाड़ा

निदेशालय में दिनांक 14/09/2021 को निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में बैठक आयोजित करते हुए हिन्दी दिवस मनाया गया। तथापि, संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के मद्देनज़र पखवाड़ा समारोह स्थगित किया गया था और दिनांक 17-10-22 से 29-10-22 तक विविध कार्यक्रमों के साथ मनाया गया।

निदेशालय के कर्मियों के हित में दिनांक 17/10/22 को राजभाषा नीति व नियम पर एक स्लाईड शो का आयोजन किया गया। आगे, निदेशालय के कर्मचारियों के लिए दिनांक 18/10/22 से निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 'आज़ादी के अमृत महोत्सव' को ध्यान में रखते हुए, प्रतियोगिताओं की संख्या बढ़ाई गई और लगभग सभी प्रतियोगिताओं का विषय 'अमृत महोत्सव' ही रहा।

- 1) प्रशासनिक एवं तकनीकी शब्दावली प्रतियोगिता
- 2) टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिता
- 3) आज का शब्द प्रतियोगिता
- 4) टंकण प्रतियोगिता
- 5) निबंध लेखन प्रतियोगिता (अमृत महोत्सव विशेष)
- 6) भाषण प्रतियोगिता (अमृत महोत्सव विशेष)
- 7) प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (अमृत महोत्सव विशेष)
- 8) शब्दशक्ति प्रतियोगिता

प्रतियोगिताओं में एमटीएस सहित सभी कर्मचारियों ने तहे दिल से भाग लिया। पखवाड़े का समापन समारोह दिनांक 11/11/22 को निदेशक की अध्यक्षता में निदेशालय के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया। श्रीमती अनन्या सूसन द्वारा वंदन गीत के उपरांत प्रशासनिक अधिकारी ने सबका स्वागत किया। अपने स्वागत भाषण में श्री पी ए परमेश्वरन, प्रशासनिक अधिकारी ने पिछले एक साल के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में हुई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। फिर निदेशक को अध्यक्ष भाषण के लिए आमंत्रित किया गया। अपने अध्यक्ष भाषण में निदेशक ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाइयाँ देते हुए इस बात को सराहनीय बताया कि पखवाड़ा के दौरान किए कार्यालयीन काम की पुनरीक्षा किए जाने पर हिन्दी पत्राचार एवं नोटिंग में लगभग 5% की वृद्धि हुई है। उन्होंने आशा प्रकट की कि अपने रोजमर्रे के काम में हिन्दी का प्रयोग तहे

दिल से करें। इसके उपरांत प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया गया। अंत में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।

झ) राजभाषा कार्यान्वयन समिति

निदेशालय में नियमानुसार निदेशक की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की है जिसमें सभी राजपत्रित अधिकारी और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, सदस्य हैं। हर तिमाही के अंत में समिति की बैठक नियमानुसार आयोजित की जाती है और कार्यवृत्त, मुख्यालय तथा नराकस को अग्रेषित की जाती है। रिपोर्ट वर्ष में दिनांक 21/06/22, 30/09/22, 06/12/22 तथा 23/03/23 को उक्त समिति की बैठकें आयोजित की गई थी।

ट) आज का शब्द

कर्मचारियों के प्रोत्साहनार्थ एक विशेष योजना सूत्रबद्ध की गयी है जिसमें निदेशालय में दो जगहों पर लगाए गए सफेद बोर्डों पर रोज़ एक हिन्दी शब्द, उसका अंग्रेजी अर्थ, उस हिन्दी शब्द से एक वाक्य तथा उसका अंग्रेजी समवाक्य नियमित रूप से लिखे जाते हैं।

इस प्रकार साल भर के दौरान लिखे जाने वाले शब्दों तथा वाक्यों के आधार पर, हिन्दी पखवाड़े के दौरान एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और पहले, दूसरे और तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को क्रमशः रु 1000/-, 750/- और 500/- की दर पर नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। इस सिलसिले में रिपोर्ट वर्ष में श्रीमती वी एस जयलक्ष्मी, सांख्यिकी अन्वेषक, श्री रोहित एच एस, तकनीकी सहायक तथा श्री डेंस के पॉल, वरिष्ठ संगणक को क्रमशः रु पहले, दूसरे और तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

ठ) हिन्दी पुस्तकों की खरीद

राजभाषा नियम के अनुसार पुस्तकों (संदर्भ पुस्तकों के अलावा) की खरीद में खर्च व्यय का 50% हिन्दी पुस्तकें खरीदने के लिए खर्च किया जाना चाहिए जबकि निदेशालय में तो नियम पुस्तकों के अलावा केवल हिंदी पुस्तकें ही खरीदी जाती हैं। इस प्रकार रिपोर्ट वर्ष में रु.4984/- की हिन्दी पुस्तकें खरीदी गईं।

ड) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यक्रमों में भागीदारी

कोचिन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में निदेशालय की सक्रिय भागीदारी रही है। संयुक्त राजभाषा समारोह के दौरान आयोजित हिंदी गीत प्रतियोगिता में निदेशालय के कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी श्रीमती रश्मि आर आई को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिनांक 14/06/2023 को आयोजित विशेष कार्यक्रम में निदेशालय को वर्ष 2021-22 के दौरान राजभाषा कार्य के उत्तम निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया।



ढ) प्रोत्साहन योजना

कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा जारी प्रोत्साहन योजना चलाई जाती है। जो कर्मचारी अपना कार्यालयीन काम आंशिक या पूर्ण रूप से हिन्दी में करते हैं और साल भर में कम से कम 10,000 शब्द हिन्दी में लिखते हैं वे इस योजना के अधीन पुरस्कार के पात्र होंगे। इसमें कार्यालय के लगभग सभी कर्मचारी भाग ले रहे हैं। पात्र कर्मचारियों को अपने द्वारा किए काम के आधार पर नीचे बताए अनुसार पुरस्कार दिए जा सकते हैं :

प्रथम पुरस्कार	(2 पुरस्कार) / रु.5000/- प्रति प्रतिभागी
द्वितीय पुरस्कार	(3 पुरस्कार) / रु.3000/- प्रति प्रतिभागी
तृतीय पुरस्कार	(5 पुरस्कार) / रु.2000/- प्रति प्रतिभागी

इस सिलसिले में रिपोर्ट वर्ष में निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए :

श्री बिपिन वी, प्रवर श्रेणी लिपिक — रु.5000 /— का प्रथम पुरस्कार

श्री डेंस के पॉल, वरिष्ठ संगणक — रु.5000 /— का प्रथम पुरस्कार

त) तिमाही प्रगति रिपोर्ट

राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के बाद पाँच कार्यदिवस के भीतर तैयार करके मुख्यालय को भेजी जाती है और यह रिपोर्ट नियमित रूप से गृह मंत्रालय के राजभाषा वेबसाइट में भी अपलोड की जाती है।

थ) निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 28/09/22 को निदेशालय के राजभाषा संबंधी कार्य का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण बैठक तिरुवनंतपुरम में आयोजित की गई थी और इसमें निदेशालय के सभी अधिकारीगण तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। समिति को दिए गए सभी आश्वासनों की पूर्ति हुई है और रिपोर्ट समिति सचिवालय को भेजी जा चुकी है।

द) जॉच बिंदु

हर साल की भौति संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए तैयार वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर निदेशालय के कार्यान्वयन के लिए जॉच बिंदुएं रिपोर्ट वर्ष में भी तैयार की गईं और परिचालित की गईं।

घ) अन्य विशेष उपलब्धियाँ

- कोचिन नगर के समस्त केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों के राजभाषा से जुड़े कर्मचारियों के लिए दिनांक 26/10/22 को एक तकनीकी कार्यशाला आयोजित की गई। भारतीय रिसर्व बैंक की कोचिन शाखा के राजभाषा प्रबंधक डॉ मधुशील आयिल्यत ने कक्षा चलाई। निदेशालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ कोचिन के 15 अन्य कार्यालयों के राजभाषा कर्मियों ने भाग लिया। कार्यशाला के संबंध में बहुत ही उत्कृष्ट प्रतिक्रियाएं मिली।

- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिनांक 14/06/2023 को आयोजित विशेष कार्यक्रम में निदेशालय को वर्ष 2021-22 के दौरान राजभाषा कार्य के उत्तम निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। निदेशालय की तरफ से श्री दादासाहेब देसाई, उप निदेशक ने प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त से रोलिंग ट्रॉफी प्राप्त की तथा श्रीमती रश्मि आर आई, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया।
- दिनांक 27/01/23 को आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में निदेशालय को वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए राजभाषा कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। निदेशालय की तरफ से श्री पी ए परमेश्वरन, प्रशासनिक अधिकारी ने माननीय राजपाल श्री अरीफ मुहम्मद खान जी से शील्ड प्राप्त की और श्रीमती रश्मि आर आई, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।



HIGHLIGHTS

- An additional area of 8,456 ha was brought under cashew with high yielding varieties by state and central efforts.
- An additional area of 3,422 ha was brought under cocoa with high yielding varieties by state and central efforts.
- An area of 1200 ha senile and unproductive cashew plantations were replaced and rejuvenated by state and central efforts.
- As a Nodal agency for accreditation of nurseries, 31 cashew nurseries having production capacity of 46.90 lakh grafts and 9 cocoa nurseries having a capacity to produce 18.30 lakhs cocoa hybrid seedlings were accredited for ensuring the production of quality planting materials.
- A total of 7,23,141 cashew grafts and 1,00,000 cocoa hybrid seedlings from accredited nurseries were distributed under DCCD developmental programmes.
- Direct Benefit Transfer by DCCD was made to 8158 cashew and cocoa beneficiary farmers under new planting programmes.
- Two big, 2 small cashew/cocoa nurseries were established and seven nurseries were upgraded by providing financial assistance.
- As a part of publicity and crop promotion activities, 42 district level seminars and 9 field days were organized in various states in association with SAU's/ KVK's/Corporations and ICAR institutes. DCCD also organized two Kisan Bhagidhari Prathamikta Campaign on cashew and cocoa in Kerala and Karnataka, two awareness programme on cashew in Kannur and two Nari ShaktiMela in Kerala and Karnataka during the year. Around 2000 beneficiaries availed the knowledge on cashew and cocoa.
- Under Human Resource Development, 76 field level training programmes, (within the state) were conducted, 3800 farmers were trained on cashew /cocoa farming practice, in association with SAU's & ICAR institutes.
- Under Cashew Apple Utilisation training, 475 unemployed women were trained on preparation of value added products of cashew apple in 19 batches of trainings.
- Two National Level training on cashew/cocoa were conducted by the Directorate for the field/ extension workers of cocoa development departments and 80 officers availed the training .
- Total export earnings from cashew kernels in India during 2022-23 was Rs.2677cr with 44,271 MT .
- Total export earnings from export of cocoa beans and cocoa products in India during 2022-23 was Rs.1242 cr with 34,250 MT.

1

Introduction

The establishment of Directorate of Cashewnut Development in 1966 under Union Ministry of Agriculture paved the way for well-designed developmental strategies of various cashew development programmes in India. Consequent upon the abolition of the Indian Central Spices and Cashewnut Committee, Directorate of Cashewnut Development (DCD) was set up by Government of India i.e. on 1.4.1966, as a subordinate office of the Union Ministry of Agriculture with the primary objective of promoting cashew cultivation in the country with a view to increase production and productivity. In the year 1997, the crop of cocoa was also transferred to Directorate of Cashewnut Development and the institution was renamed as Directorate of Cashewnut and Cocoa Development (DCCD).

The Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Kochi (DCCD) is presently functioning as one of the national level agencies directly under the Union Ministry to Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India, New Delhi mandated to undertake the development of the crop of Cashewnut and Cocoa throughout the country and responsible for implementing, coordinating and monitoring activities relating to Cashew and Cocoa at national level. The Directorate is also responsible for organizing national level training programmes, seminars and workshops on cashew and cocoa and also is the nodal agency for evaluating and accrediting cashew/cocoa nurseries. The formation of this Directorate was a break through in the holistic development of these two versatile horticulture crops. This annual report of the Directorate highlights the activities and achievements during the period from 01-04-2022 to 31-03-2023.

Since the inception of this Directorate, persistent efforts were being undertaken for the development of these crops. Significant improvement has been achieved in expanding area and production of quality planting material through the developmental activities of DCCD and is close monitoring and reviewing of programmes executed by the states. The area and production of cashew and cocoa has been increasing trend since the inception of National Horticulture Mission in 2005 in which priority with greater importance for holistic development of cashew and cocoa were accorded.

The Directorate is associating with all stake holders viz. Development Departments, Research Organizations, Corporations, Local Panchayat and Farmers Organizations for implementing various cashew and cocoa development programmes in the country. The Directorate cordially associates with large spectrum of farming community in transferring improved production technologies by conducting regular training programmes/ workshops/ field campaigns/ seminars, bringing literatures in local languages. The Directorate acts as a coordinator and monitors the activities for promotion of cashew and cocoa between the Central State institutes and the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.



The Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), a centrally sponsored programme launched by Government of India during XIIth plan for holistic development of Horticulture, provides assistance for the development of cashew and cocoa by adopting an integrated approach involving production and productivity improvement, Human Resource Development through training and field visit as well as creation of infrastructure for post-harvest management and marketing. The Directorate is now implementing development schemes under MIDH through various ICAR institutes, KVK's, Research Institutes, Panchayathi Raj institutions, state and central government agencies and corporations.

1.2.Mandate

The Mandate of the Directorate are as follows;

- Formulation, implementation and execution of development programmes of cashew and cocoa and to monitor the implementation of development programmes executed by the State Governments under MIDH.
- Nodal agency to give accreditation, monitor production and distribution of planting materials of cashew and cocoa in the country.
- To coordinate the activities for the promotion of these crops between the Central and State Institutes and the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
- To provide adequate exposure and dissemination of technologies in the entire production sector.
- Function as a data bank on crop area, production, price trends, marketing and trade performance of export and import.
- Advisory body to recommend, watch and monitor the various aspects of crop development, marketing and by product-utilization.
- Take up intensive publicity measures for dissemination of technologies among farmers by publishing literatures, pamphlets, adoption of electronic media coverage, organizing National Conference, seminars, workshops and field days at regular intervals.
- Render technical advice and suggestions to the entrepreneurs involved in the promotion of cashew and cocoa and farming community on various aspects of cultivation.
- Organize national level training programme in cashew and cocoa to the officers involved in implementing cashew and cocoa programmes in various states.

1.3 Organizational Setup

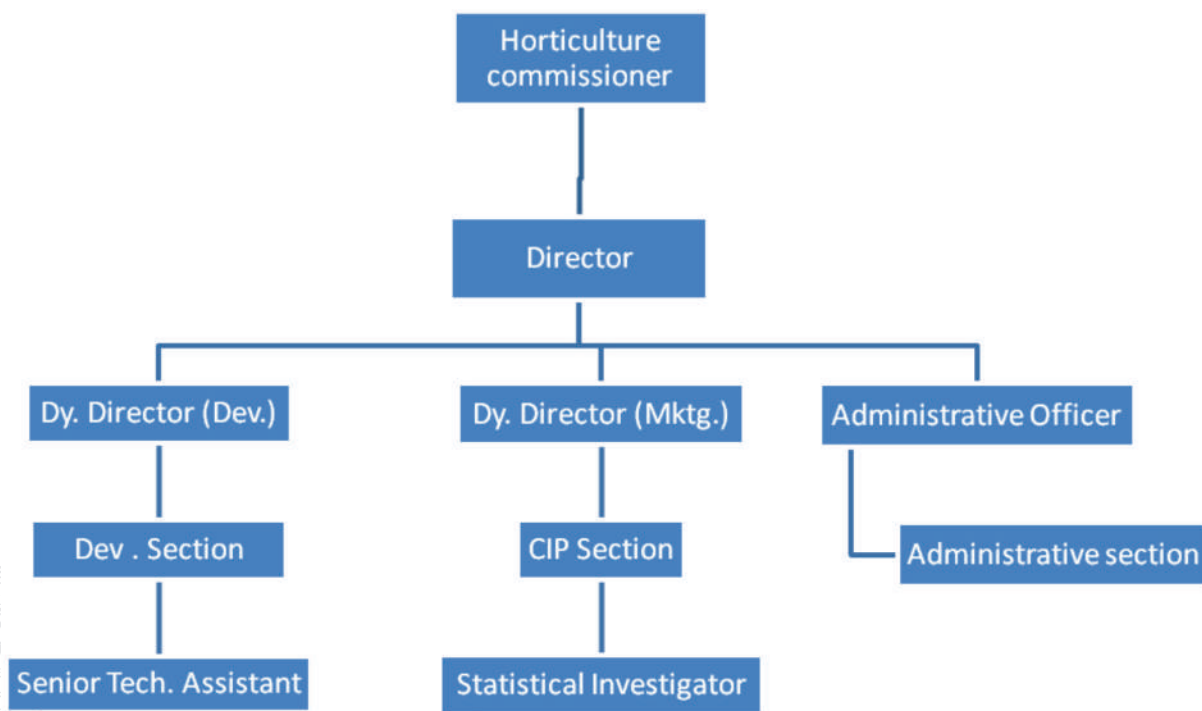
The Directorate of Cashewnut and Cocoa Development is headed by a Director supported by two Deputy Directors, one Administrative officer and other supporting technical and administrative staff. The Directorate has three sections viz. Development section, Crop Information & Publicity

section and Administrative section. The staff strength in the Directorate is given below.

Infrastructure – Staff Position

Designation of the posts	Sanctioned strength	In position(as on 31.03.2023)
Director	01	01
Dy. Director	02	02(1 deputation)
Administrative Officer	01	01
Statistical Investigator	01	01
Senior Technical Assistant	01	01
Junior Translator	01	01
Technical Assistant	04	04(1 deputation)
Stenographer (Gr. I)	02	-
Senior Computer	01	01
Upper Division Clerks	02	01(deputation)
Lower Division Clerks	02	02
Hindi Typist	01	01
Multi-tasking Staff	03	0
Total	22	16 (3 deputation)

ORGANISATIONAL SETUP – DCCD



2

Cashew and Cocoa Scenario

2.1. Cashew

Cashew, a native of Brazil was introduced in India during 16th century. It was only during 1950's that cashew gained commercial importance with the beginning of export of cashew kernels to European countries. Up to 1970's India maintained its pre-eminence in global market of this commodity. Now, it occupies the status of an important commercial crop in the country which has contributed significantly in the upliftment of rural agrarian economy and main livelihood of small and marginal farmers. Indian cashew is ranked best in quality and India exported cashew kernels and CNSL worth of Rs. 2734 cr. during 2022-23 by overcoming the world pandemic situation. Apart from the economic significance, nearly half a million farmers are engaged in the cultivation of cashew and one million people are engaged in processing and allied sector.

Currently, cashew cultivation has spread to about 19 states of the country. It is mainly grown in Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, West Bengal and to a limited extent in Gujarat, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Assam, Tripura, Meghalaya, Nagaland and Andaman and Nicobar Islands.

Directorate of Cashewnut and Cocoa Development under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is assigned for formulation and execution of different cashew development programmes. For doubling farmers income, a three year Road map for the development of cashew has been prepared by DCCD as per the recommendation of Group of Secretaries for covering an area of 1,20,000 ha under cashew approved by Ministry and an area of 87,842 ha was brought under cashew since 2017-18 by state and central effort. Now, Cashew occupies an area of 11.93 lakh ha with the production of 7.82 lakh MT of rawnuts and productivity of 766 kg/ha (2022-23).

Production Scenario of Cashew (2022-23)

Cashew:

STATE	Area (000 Ha)	Production (000 MT)	Pdty (Kg/ha)
Kerala	108.589	74.63	839
Karnataka	138.867	77.85	653
Goa	59.444	25.81	491
Maharashtra	191.551	197.30	1145
Tamil Nadu	174.960	80.39	594
Andhra Pradesh	198.848	132.31	764



STATE	Area (000 Ha)	Production (000 MT)	Pdty (Kg/ha)
Odisha	223.450	126.13	655
West Bengal	14.552	13.28	1169
Jharkhand	15.580	6.60	424
Chhattisgarh	32.585	22.30	716
Gujarat	11.848	7.01	802
Pondicherry	5.000	2.33	466
Assam	1.050	1.16	1105
Tripura	4.250	3.55	835
Meghalaya	8.780	10.38	1182
Manipur	0.900	0.33	367
Nagaland	2.000	0.55	1100
Total	1192.254	781.92	766

At present, nearly 3940 processing units are functioning in India under organized and unorganized sector with a processing capacity of 17 lakh MT raw nuts per year. The industry, therefore, imports nearly 56 percent of rawnuts through imports from the other countries, especially from Africa to meet the demand. Import of raw cashewnut, which began at around 5.297 lakh MT in 2010-11, has increased to 13,29,751 lakh MT in 2022-23. Since African countries have started processing their rawnut themselves, its availability in global market will gradually decline in future. Hence, the shortage has to be supplemented by enhancing domestic production of rawnuts.

While going to make an approach to improve rawnut production, due care should be given for both area expansion as well as improvement in productivity. At present, the area under cashew is 11.93 lakh ha, of which, nearly 75% are in private sector, confining mostly to small and marginal holding, contributing 80% of national production. Out of the total area, 33 percent of existing areas have crossed 45 years of life and are under senile condition which are highly unproductive. The farming community at large is not aware of the scientific and horticultural technology required to be taken up in their field. All the scientific upgradations in terms of variety, usage of clones, INM and IPM packages are the areas that require greater amount of percolation into the field. Improving the scientific upgradations among farming community increases a minimum yield by 15% on the present production. Hence all these issues are addressed under MIDH in a holistic approach to increase the production of cashew in addition to strengthening the planting material production. Accordingly, there is significant increase in area and production of cashew since 2005-06 due to the concentrated attention given to this crop under NHM. The area under cashew during 2004-05 was 8.20 lakh ha with a total production of 5.44 lakh MT. Now, with the implementation of the NHM programmes, the area has increased to 11.93 lakh ha with the total production of 7.82 lakh MT of rawnuts in 2022-23.

2.2 Cocoa

Cocoa is one of the most important commercial plantation crops in the world. It is best known today as a raw material for chocolate. It was introduced in India in the early 19th century, but its cultivation commenced only from 1960s. Now it has become one of the important commercial plantation crops in India for preparation of mainly chocolates. It is mainly cultivated in the four southern states of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Even though Cocoa is conferred plantation status like Tea, Coffee and Rubber, it is rarely recognized as a plantation crop under the Indian agrarian sector. Cocoa beans are highly nutritious and are the only major source of chocolate, being rich in flavonoids, it helps to reduce cholesterol and it is an energy boosting drink. It is highly economical crop and is grown as an ideal inter crop in coconut, oil palm and arecanut based farming system in India. The production of cocoa in India is low in quantity and is negligible compared to major producing countries. Cocoa not only provides additional income per unit area but also enhances productivity of soil by shedding large number of leaf mass at regular intervals. With the implementation of development programmes of cocoa in the previous years, the present area under cocoa is 1,08,985 ha with the total production of 29,792 MT and productivity is 825 kg per ha.

Production scenario of Cocoa (2022-23)

State	Area (ha)	Production (MT)	Pdty(kg/ha)
Kerala	18233	10,535	1100
Karnataka	14269	4,061	650
Tamil Nadu	32580	3,061	350
Andhra Pradesh	43904	12,135	1200
Total	108985	29,792	825

Consumption of cocoa products in India also shows an increasing trend by 15 % annually. India has also earned foreign exchange of more than Rs. 1242 cr. by way of export of cocoa & cocoa products (2022-23). The estimated demand of chocolate industry and confectionaries is around 70,000 MT of Cocoa beans whereas the availability is 38 percent of the demand. The present demand of chocolate industry and confectionaries is of about 70,000 MT of Cocoa beans whereas domestic production is only 38 percent of the demand. Acute shortage of cocoa beans is the main problem now faced by the industry and India has imported 1,28,654 MT of cocoa and cocoa products worth Rs.3531crores for meeting the demand. Earlier the price of cocoa beans was fluctuating widely, but the position now has changed and the average price is ruling between Rs. 150 to Rs. 180 per kg for dry beans depending on the quality. Recognizing the importance of this high value crop, Government of India has given more thrust for promotion of this crop under the centrally sponsored Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH).



2.3 DCCD efforts, activities and achievements

The DCCD as a National Level Agency under Mission for Integrated Development of Horticulture is an effective mechanism for directly interfering with farming community at primary field level and to transfer high end technologies effectively from research to field. The Directorate is associating with all the grass root players like developmental departments, research organizations, corporations, FPOs, local panchayat and farmers organizations, implementing various cashew and cocoa developmental programmes in the country thus resulting in significant boost in the domestic production.

The efforts of the Directorate under various schemes of DAC & FW during last four decades have witnessed four-fold increase in terms of area and seven fold increases in terms of production and more than 100% increase in terms of productivity of cashew in the country. The Directorate, under the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare has been developing this crop in a most befitting manner and will continue with its harmonious coexistence, remaining complementary and supplementary with research organizations, state development departments, industry and above all painstakingly advising large spectrum of farming community to adopt scientific management of cashew to increase production. The schemes and interventions of DCCD not only has development angle but also aims to provide much needed daily livelihood/social upliftment to farmers in backward/Tribal/Forest areas.



3

Implementation status (Cashew /Cocoa)

3. Implementation status on Cashew and Cocoa under MIDH(2022-23)

Sl. No	Activity	Spill over 2021-22				2022-23			
		Physical target	Financial Outlay (in lakhs)	Physical achvmt	Financial achvmt (in lakhs)	Physical target	Financial Outlay (in lakhs)	Physical achvmt	Financial achvmt (in lakhs)
1.	Establishment of new plantation (ha)-								
a.	Cashew- Fresh planting	160	19.20	160	19.20	3800	456.00	3346	401.726
b.	Cashew- 2nd year maintenance	95.25	3.81	-	-	640	25.60	501	20.021
c.	Cashew- 3rd year maintenance	-	-	-	-	803	32.12	752	30.054
d.	Cocoa- Fresh planting	-	-	-	-	200	24.00	200	24.000
e.	Cocoa- 2nd year maintenance	-	-	-	-	149	5.96	148	5.912
f.	Cocoa- 3rd year maintenance	-	-	-	-	150	5.98	149	5.968
2.	Replacing senile plantations and replanting with high yielding varieties (ha)								
a.	Fresh planting	40	4.80	40	4.80	650	78.00	650	78.00
b.	2nd year maintenance	-	-	-	-	1140	45.60	1140	45.60
c.	3rd year maintenance	-	-	-	-	500	20.00	500	20.00
3.	Technology dissemination through FLTD								
a.	Establishment of demonstration plot with high density in cashew	-	-	-	-	100	40.00	59	23.600
b.	Varietal demonstration in cocoa	2	0.83	-	-	-	-	-	-
4.	Nursery programmes(nos.)								
a.	Estt.of High-tech nursery in cashew	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Establishment big cashew nurseries	1	20.00	1	20.00	2	40.00	1	20.000
c.	Establishment small cashew nurseries	1	7.50	1	7.50	2	15.00	1	7.500
d.	Upgradation/ modernization of nurseries (Nos)	3	15.00	3	15.00	4	20.00	4	20.00

ANNUAL REPORT 2022-23



Sl. No	Activity	Spill over 2021-22				2022-23			
		Physical target	Financial Outlay (in lakhs)	Physical achvmt	Financial achvmt (in lakhs)	Physical target	Financial Outlay (in lakhs)	Physical achvmt	Financial achvmt (in lakhs)
e.	Accreditation of nurseries	10	1.10	10	1.10	40	3.00	30	2.968
5.	Publicity for crop promotion including NE states								
a.	National conference (Cashew/Cocoa)	-	-	-	-	1	5.00	1	5.00
b.	District level seminar(Nos.)	2	0.93	2	0.93	40	30.00	40	30.00
c.	Cashew/cocoa fair/day(No.)	3	6.20	3	6.20	3	5.00	6	2.700
d.	Exhibition/ Advertisement/ printing(NB)	-	0.25	-	0.25	NB	21.50	NB	20.590
e.	Stakeholders meet on cashew and cocoa (Nos.)	-	-	-	-	2	4.00	2	3.855
6.	HRD in cashew and cocoa	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	National Level Training on Cashew	-	-	-	-	1	7.50	1	5.750
b.	National Level Training on Cocoa	-	-	-	-	1	4.00	1	4.000
c.	Cashew apple utilization training (nos.)	3	0.39	3	0.398	25	5.00	16	3.250
d.	Farmers training on cashew/ cocoa production technologies (nos.)	-	-	-	-	90	27.00	76	22.70
e.	Skill development training on value addition in cashew and cocoa (nos.)	25	13.65	20	9.85	-	-	-	-
f.	Exposure visit(no.)	-	-	-	-	5	15.00	4	11.050
7.	Production forecast(districts)	9	1.80	4	0.800	8	1.60	8	0.800
8.	Primary processing units in cocoa (no)	-	-	-	-	5	10.00	-	-
9.	Mission management	-	0.99	-	0.990	-	48.54	-	46.261
	Total (Cashew and Cocoa)	-	96.45	-	87.018	-	995.40	-	861.305

NB-Need Based

3.1 Developmental initiatives

The development activities are being implemented in all the traditional and non-traditional Cashew/Cocoa growing states through the execution of various centrally sponsored programmes under MIDH with the financial assistance provided by the Government of India. This is being done in two ways, viz. (i) State efforts through work plan funded by the Directorate of Cashewnut and Cocoa Development (DCCD) and (ii) State work plan executed by concerned State Government according to their priorities and monitored by the DCCD. New plantation development, replanting, production of quality planting materials, trainings, seminars, skill trainings on value addition are the major programmes implemented by the DCCD in association with various stake holders during 2022-23. More over, monitoring of developmental programmes implemented by state horticulture missions is also done by DCCD through review meetings, correspondences, discussion over phone, field visits, evaluation & inspection of the new planting and replanting done in respective states were also carried out.

i) Establishment of New Plantation in the farmer's field (Cashew & Cocoa)

The main objectives of the programme is to develop new plantations with high yielding varieties of cashew and cocoa in farmers field. The programme was implemented directly by DCCD with the association of local panchayat, KVK's, NGO's and Departments. The pattern of assistance was 100% from Govt. of India share i.e. Rs.20,000 per ha and limited to a maximum of 4 ha per beneficiary is extended under the scheme for taking of new planting of Cashew and Cocoa. The financial assistance to the individual beneficiaries was restricted as per the general recommendations by the research institutes i.e. 200 plants per ha for Cashew and 500 plants per ha for Cocoa as intercrop.

Under the programme, cashew and cocoa plantations were established in cluster basis in the states of Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh, Kerala and Goa as per the MIDH guidelines. A total amount of Rs. 568.86 lakhs has been earmarked during the year 2022-23 for establishing 3960 ha of fresh planting and 1742 ha of maintenance under cashew and cocoa. During the year 2022-23, a total area of 3506 ha was newly covered under cashew and cocoa. Total 8192 farmers benefited from the programme. State wise details of the programme is given below.

Karnataka

During the year 2022-23, the new planting programme was implemented in association with KVK's, Research stations and Department of Horticulture. An additional area of 612 ha was brought under the programme with a financial achievement of Rs. 73.46 lakhs in Kalaburagi, Haveri, Hanumanamatti, Gadad, Khanapura, Challakere, Uttara Kannada and Hiriya. Good quality cashew grafts of 1.22 lakhs were distributed among small and marginal farmers for the establishment of new plantations. In addition, 2nd and 3rd year maintenance activity was undertaken in an area of 386 ha under the programme. Total 818 small and marginal farmers benefitted them the programme.

Kerala

During the year 2022-23, the new planting programme was implemented directly in association with Grama Panchayat. An additional cashew area of 323 ha was brought under the programme

with a financial achievement of Rs. 38.37 lakhs in Alankode, Balal, Chapparapadavu, Chengalayi, Kurumathur, Malappattam, Naduvil, Padiyoor, Payyavoor and Udayagiri panchayath of Kannur and Kasaragod districts of Kerala. 64800 nos good quality cashew grafts were distributed among small and marginal farmers for the establishment of new plantations. In addition, 2nd and 3rd year maintenance activity was undertaken in an area of 344 ha under the programme. Total 1759 small and marginal farmers were benefitted from the cashew programme.

During the year 2022-23, the cocoa new planting programme was also implemented directly in association with Grama Panchayat in Wayanad, Idukki, Palakkad and Kozhikode districts of Kerala. An additional cocoa area of 100 ha was brought under the programme with a financial achievement of Rs. 12.00 lakhs in Kaniyambeta, Kanjikuzhi, Koodaranji and Vadakarapathi panchayat and 50000 nos good quality hybrid seedlings were distributed among small and marginal farmers for the establishment of new plantations. Total 293 small and marginal farmers benefitted from the cashew programme.

Goa

During the year 2022-23, the new planting programme was implemented in association with farmers cooperative societies such as Sattari taluka farmers service co-op society and Goa Bagayatdar Kharedi Vikri Sauntha Maryadit. An additional area of 424 ha was brought under the programme with a financial achievement of Rs. 50.87 lakhs. Around 89,651 good quality cashew grafts were distributed among small and marginal farmers for the establishment of new plantations. Total 402 small and marginal farmers benefitted from the programme.

Tribal upliftment programme in Gujarat

The Directorate was implemented cashew new planting programme exclusively for tribal farmers in Tapi, Dang and Valsad districts of Gujarat with an objective to uplift the socio-economic status of tribal farmers. Suitable tribal colonies were identified in association with NGO's Shree Seviyer Public Trust and Shri Ram Education and Gramin Vikas Charitable Trust. An additional cashew area of 2048 ha was brought under the programme with a financial achievement of Rs. 245.77 lakhs. Total of 4.20 lakhs good quality cashew grafts were distributed among tribal farmers from the DCCD accredited cashew nurseries. Total of 2558 tribal farmers benefitted from the programme.

Tribal upliftment programme in Kerala

The Directorate implemented cocoa new planting programme exclusively for tribal farmers in Idukki and Ernakulam districts of Kerala with an objective to uplift the socio-economic status of tribal farmers. Suitable tribal colonies were identified in association with Tribal extension department and Mondelez India Foods (Pvt) Ltd. An additional cocoa area of 100 ha was brought under the programme with a financial achievement of Rs. 12.00 lakhs and 50000 Nos good quality hybrid seedlings were distributed among tribal farmers from the DCCD accredited cocoa nurseries. In addition, 298 ha was covered under 2nd and 3rd maintenance under new planting programme. Total of 903 tribal farmers benefitted from the programme. State wise target and achievement is given below.

a. New planting programme- Cashew& Cocoa (target & achievement-2022-23)

Sl. No	State	Cashew (2022-23)				Cocoa (2022-23)			
		Fresh planting (including spill over)				Fresh planting			
		Phy. Target (ha)	Fin. outlay (Rs in lakhs)	Phy. Achmt. (ha)	Fin. Achmt. (Rs in lakhs)	Phy. Target (ha)	Fin. outlay (Rs in lakhs)	Phy. Achmt. (ha)	Fin. Achmt. (Rs in lakhs)
1	Goa	600	72.00	423.93	50.87	-	-	-	-
2	Gujarat	2100	252.00	2048.16	245.77	-	-	-	-
3	Karnataka	652	78.24	612.2	73.46	-	-	-	-
4	Kerala	330	39.60	322.99	38.76	200	24.00	200	24.00
5	Maharashtra	128	15.36	100.58	12.07	-	-	-	-
6	Nagaland	100	12.00	0	0	-	-	-	-
7	Imphal	50	6.00	0	0	-	-	-	-
	Total	3960	475.20	3507.86	420.93	200	24.00	200	24.00

Sl. No	State	Cashew (2022-23)				Cashew (2022-23)			
		2nd year maintenance				3rd year maintenance			
		Fresh planting (including spill over)				Fresh planting			
		Phy. Target (ha)	Fin. outlay (Rs in lakhs)	Phy. Achmt. (ha)	Fin. Achmt. (Rs in lakhs)	Phy. Target (ha)	Fin. outlay (Rs in lakhs)	Phy. Achmt. (ha)	Fin. Achmt. (Rs in lakhs)
1	Andhra Pradesh	320	12.8	235	9.38	339.5	13.65	289	11.53
2	Karnataka	212	8.48	159	6.36	225.43	9.02	227	9.09
3	Kerala	108	4.32	108	4.28	236.25	9.45	236	9.43
	Total	640	25.6	502	20.02	803	32.12	752	30.05

Sl. No	State	Cocoa (2022-23)				Cocoa (2022-23)			
		2nd year maintenance				3rd year maintenance			
		Fresh planting (including spill over)				Fresh planting			
		Phy. Target (ha)	Fin. outlay (Rs in lakhs)	Phy. Achmt. (ha)	Fin. Achmt. (Rs in lakhs)	Phy. Target (ha)	Fin. outlay (Rs in lakhs)	Phy. Achmt. (ha)	Fin. Achmt. (Rs in lakhs)
1	Kerala	149	5.96	148	5.91	149.75	5.98	149.2	5.97
	Total	149	5.96	148	5.91	149.75	5.98	149.2	5.97



ii) Replacing senile, old cashew plantations and replanting with high yielding varieties.

The scheme envisages removal of senile plantations and replanting with High Yielding Varieties recommended to the location. The Directorate has directly implemented the scheme in identified clusters of senile cashew plantation in the land owned by Forest Departments, State Farms and Corporations of various states.

A total amount of Rs. 148.40 lakhs has been earmarked during the year 2022-23 for 1180 ha of fresh planting, 500 ha of 2nd year and 700 ha of 3rd year maintenance operations. During 2022-23, an area of 690 ha was replanted with high yielding varieties and maintenance activities in area of 1640 ha was carried out in the areas replanted in the year 2020-21 and 2021-22. A total financial assistance of Rs. 148.40 lakhs was released to various agencies as shown below.

Sl No:	State	Physical target (ha)	Financial target (in lakhs)	Physical achievement (ha)	Financial achievement (in lakhs)
1	Karnataka FP	150	18.00	150	18.00
	M2	250	10.00	250	10.00
	M3	0	0.00	0	0.00
2	Tamil Nadu FP	0	0.00	0	0.00
	M2	250	10.00	250	10.00
	M3	238.95	9.55	238.95	9.55
3	Odisha FP	540	64.80	540	64.80
	M2	640	25.60	640	25.60
	M3	261.05	10.45	261.05	10.45
	Total FP	690	82.80	690	82.80
	M2	1140	45.60	1140	45.60
	M3	500	20.00	500	20.00

iii) Technology dissemination through demonstrations/front line demonstrations -Cashew & Cocoa

The objective of this programme is to demonstrate and convince the farmers, the benefits of various scientific production technologies. Each demonstration unit should not exceed 1ha and rate of financial assistance is maximum of Rs. 40,000/- per ha.

High density planting (HDP) is a new approach in cashew sector which is capable of increasing the productivity by accommodating more number of plants per unit area. Conventionally

cashew is planted at 8m x 8m which accommodates 150 to 160 plants per hectare and the plants take 7-8 years to cover the allotted space and to give potential yield of 8 to 10 quintals per hectare with proper management practices. Therefore, high density planting appears to be the most appropriate solution to overcome low productivity due to initial long waiting period for economic returns. To meet the challenge of high productivity, optimization of growth parameters and minimization of the unproductive components of trees without sacrificing the overall health of the tree and quality of the product should be carried out. The control of excessive vegetative growth in the tree for increased productivity is the major principle of high density planting. Hence, controlling tree size by regular pruning in orchards is one of the methods of increasing production. In HDP system, yields are improved in early years of planting. The high density planting reduces the weed growth by early canopy coverage, reduces soil temperature there by increasing the soil moisture content especially during peak summer season and also provides mulching effect. In HDP of cashew, closer spacing has given two times more yield than normal spacing. Cashewnut yield can be increased to four folds upto 6 years and 2.27 folds upto 12 years in HDP system.

In order to popularise and convince this High density planting of cashew among farming community, Directorate established demonstration plots under High density planting in association with various research stations and development departments. During 2022-23, a total 59 FLTD units were established in the state of Karnataka and Kerala with a financial achievement of Rs.23.60 lakhs against the physical target of 100 units.

iv) Nursery programmes

a. Establishment/up-gradation of cashew/cocoa nurseries

The objective of this programme is production and distribution of good quality planting materials to meet the requirement for new planting and replanting of cashew/cocoa in the country. The maximum financial assistance shall be limited to Rs.20.00 lakhs @ 40% of the total project cost for big Model nursery and Rs.7.50 lakhs @ 50% of the total project cost for small nursery. For up-gradation of nurseries, 50% of cost to private sector subject to a maximum of Rs. 5.00 lakh/nursery.

During 2022-23, two small and two big nurseries were established with a financial achievement of Rs.55.00 lakhs and seven nurseries was upgraded with a financial achievement of Rs. 35.00 lakhs in the states of Tamil Nadu, Odisha, Maharashtra, and Kerala.

Sl. No.	Name of nursery	Physical achievement	Financial achievement
1	Supna Agrotech, Odisha	1 (Small nursery)	7,50,000
2.	Sri Kurinji nursery, Tamil Nadu	1 (Small nursery)	7,50,000
3.	Green Solance nursery, Maharashtra	1 (Big nursery)	20,00,000
4.	Shree Swamy nursery, Maharashtra	1 (Big nursery)	20,00,000
5.	ZAHRs, Brahmavar, Karnataka	1 (Up gradation)	5,00,000
6.	RARS, Pilicode, Kerala	1 (Up gradation)	5,00,000
7.	Rasika Nursery, Maharashtra	1 (Up gradation)	5,00,000



Sl. No.	Name of nursery	Physical achievement	Financial achievement
8.	Arolkar Farms, Maharashtra	1 (Up gradation)	5,00,000
9.	Shree Rameshwar nursery, Maharashtra	1 (Up gradation)	5,00,000
10.	Manohar nursery, Maharashtra	1 (Up gradation)	5,00,000
11.	Nilesh nursery, Maharashtra	1 (Up gradation)	5,00,000
	Total		90,00,000

b. Accreditation of nurseries

The DCCD acts as a nodal agency for accreditation of existing new cashew/cocoa nurseries based on the guidelines prepared by the DCCD and issues certificate of accreditation. A committee constituted by the Director, DCCD consisting of an expert from Cashew research, a senior Officer of DCCD and an officer from the Department of Horticulture/Agriculture visit the nursery. On the basis of the assessment report, the Directorate issues the certificate of accreditation to the concerned nurseries. During 2022-23, forty cashew/cocoa nurseries were accredited and an amount of Rs.4.068 lakhs was spent for meeting the contingency expenditure of the inspection team. State wise nursery details are given below;

Statewise cashew nurseries and production capacity – 2022-23

States	Number of nurseries	Production capacity (In lakhs)
Karnataka	4	4,00,000
Maharashtra	10	25,50,000
Tamil Nadu	15	10,40,000
Odisha	2	7,00,000
Total	31	46,90,000

Statewise cocoa nurseries and production capacity – 2022-23

States	Number of nurseries	Production capacity (In lakhs)
Kerala	3	5,55,000
Karnataka	2	2,50,000
Andhra Pradesh	3	9,75,000
Assam	1	50,000
Total	9	18,30,000

v) Status of area expansion by central and state effort

In order to achieve the self-sufficiency in rawnut and cocoa beans, an area of 8,456 ha of Cashew and 3,422 ha of Cocoa new area were established in various states under various schemes during 2022-23 as shown below.

Achievement of Cashew/Cocoa area expansion programmes- 2022-23 (MIDH/RKVY/State programmes/others)

State	Cashew	Cocoa
Karnataka	868	55
Kerala	2068	463
Maharashtra	101	-
Odisha	NR	-
Jharkhand	NR	-
Gujarat	2048	-
Andhra Pradesh	1042	2404
TamilNadu	1720	500
Meghalaya	NR	-
Goa	424	-
Manipur	NR	-
Chhattisgarh	185	-
Madhya Pradesh	NR	-
Nagaland	NR	-
West Bengal	NR	-
Total	8456	3422

#NR- Not Reported

vi) Production Forecast on cashew:

The objective of the programme is to make a realistic assessment of yield of cashew in 2022-23 season. The research or economic wing of State Agricultural University is involved for implementing the programme. The scientists of the respective research centre identifies the enumerators having enumerative ability suited to this objective and give them training for enumeration work. A suitable proforma for collection of crop estimation developed by this Directorate is used by the numerators for the survey. The crop enumeration is done at the time of fruit set (peanut stage).

During 2022-23, this programme was sanctioned for implementation by various Cashew Research Stations at an outlay of Rs 3.40 lakhs including spill over amount of Rs. 1.80 lakhs of 2021-22. The survey was conducted in 10 major districts of Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra in the fruiting season. The scheme was not implemented in the states of Tamil Nadu,



Goa and Odisha for want of proposals from the concerned agencies. An amount of Rs. 1.60 lakhs was utilized during 2022-23 for the purpose by the following agencies.

Sl. No.	Agency/SAU's	Districts Involved in the survey	Amount(Rs.)
1	RFRS Vengurla	Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg, Kolhapur	40000
2	AHRS, Ullal	Dakshina Kannada, Udupi	40000
3	CRS, Bapatla	East, West Godawari	40000
4	CRS, Madakkathara	Kasaragod, Malappuram	40000
		Total	160000

vii) Publicity on crop promotion- Cashew & Cocoa

The dissemination of improved technology on Cashew & Cocoa is essential to the farming community to make their crop a profitable enterprise. New technologies and practices have been developed by the Research institute for giving thrust to the production & productivity of the crops and also to double the farmer's income. In order to achieve this objective, "Publicity for Crop Promotion of Cashew & Cocoa through Technology Dissemination" has been envisaged by DCCD by organizing National Conference, District Level Seminars, Horticulture Fair/Mela/Field day in all cashew and cocoa growing states in association with Research Institute/SAU's/ KVK's. An amount of Rs. 72.88 lakhs was earmarked for publicity programme during 2022-23 and an amount of Rs.69.530 lakhs has been incurred under the various publicity programmes as given below.

a. District level seminar on Cashew & Cocoa

The above event is for one day involving 150 participants consisting of farmers, extension workers, officials, processors and other agencies involved with development of the crop. A financial assistance of Rs. 75,000 is provided for organizing the one day district level seminar on cashew & cocoa and the fund is released to concerned organizing institutes for meeting the charges for arrangement of hall, audio visuals, electricity, publicity materials, pen & writing pads, photography, refreshments by providing working lunch to the participants, honorarium for resource personnel, transports etc.

The programme was successfully implemented in various states by utilizing the 100% of the fund. An amount of Rs. 37.375 lakhs has been incurred for the conducting 51 district level seminars on cashew and cocoa with the participation of 7650 beneficiaries in various states as per the details furnished below.

Cashew

State	No. of Programmes	Amount(Rs.)	No. of Farmers
Andhra Pradesh	4	300000	600
Chhattisgarh	1	75000	150
Gujarat	1	75000	150



State	No. of Programmes	Amount(Rs.)	No. of Farmers
Goa	1	75000	150
Karnataka	10	763501	1500
Kerala	8	527782	1200
Maharashtra	2	144500	300
Madhya Pradesh	1	75000	150
Odisha	5	375000	750
Tamil Nadu	4	300000	600
Total	37	2710783	5550

Cocoa

State	No. of Programmes	Amount(Rs.)	No. of Farmers
Andhra Pradesh	1	75000	150
Assam	1	70000	150
Karnataka	3	206685	450
Kerala	3	225000	450
Tamil Nadu	6	450000	900
Total	14	1026685	2100

b. National conference on Cashew:

A two day National Conference Cashew was scheduled during April 2022 at Bhubaneswar in association with Odisha State Cashew Development Corporation Ltd, Bhubaneswar. The conference was not organised as scheduled, due to engagement in Kisan Bhagidari Campaign. The Conference was rescheduled in the month of January 2023. An amount of Rs. 5.00 lakhs was already committed in 2021-22 for organisation of the conference during 2022-23.

National Conference on Cashew/cocoa is proposed with an objective to evolve strategies to augment domestic production of cashew by adopting feasible and viable technologies. A two days conference on cashew was organised in association with OSCDC on 30 & 31st January 2023 at Bhubaneswar, Odisha with the spill over target of 2021-22 and one day National Conference on Cocoa was also organised in association with Keladi Shivappa Nayak University of Agricultural & Horticulture Sciences at Shivamogga, Karnataka involving officials from state development departments/ state owned corporations/SAUs/research institutes/stake holders in the field of industry and marketing and progressive farmers. Around 350 participants from the above organizations attended the two National Conferences. An amount of Rs. 10.00 lakhs was spent for the conduct of the two conferences including spill over target of 2021-22.



c. Cashew/Cocoa Fair/Field Day:

The objective of the event is to make the farmers/ public to aware the importance, scope, latest technologies of cashew/cocoa cultivation and to make it profitable enterprise by organizing mela/field day in different States. An exhibition will also be arranged for the purpose by depicting various aspects of the crops by putting stalls from different organizations, research, development, inputs producing industries and export consultation on specific issues.

During the year 2022-23, the Directorate conducted 9 number of cashew and cocoa fair / field days in association with SAU's with a participation of 200-1000 farmers per event in Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Odisha. An amount of Rs. 11.20 was allocated for the said programme and out of it, Rs. 8.90 lakhs was spent. A total of 5300 farmers participated in the event. Agency wise details is as below.

Agency	No. of Programmes	No. of Farmers	Amount(Rs.)
AHRS, Ullal	1	300	50000
ARS, Hanumanmatti	1	1000	120000
CPCRI, Vittal	1	1000	150000
CRS, Bapatla	1	300	50000
DCCD	1	300	60000
HRS Ambajpetta	1	200	30000
OSCDC, Bhubaneswar	1	1000	200000
UAS, Raichur	1	1000	200000
ZAHRS, Mudigere	1	200	30000
Total	9	5300	890000

d. Stake holders meet on cashew and cocoa

To evolve a developmental strategy in the form of an actionable plan for future and to bridge a gap between demand and supply in the cashew and cocoa sector, meeting of stake holders is envisaged involving all the stake holders of cashew and cocoa in various states.

During the year 2022-23, the Directorate conducted a stake holders meet on Cashew and Cocoa on 27.08.2022 under the Chairmanship of Dr.Prabhat Kumar, Horticulture Commissioner, Govt. of India at Panaji, Goa. Another one is scheduled to be held during 2023 in association with University of Agricultural Sciences, Raichur. A total expenditure of Rs. 3.855 lakhs was utilised for the said programme.



- e. **Publicity activities viz. Exhibitions, Advertisements, Printing of Literatures, development of video, workshop, training on processing, documentation and publicity through AIR, Door Dharsan etc. for the promotion of Cashew and Cocoa crop.**

Exhibitions, field days and any other training campaigns/workshops in the Cashew & Cocoa growing states on need basis with the financial assistance from MIDH are proposed under the scheme. Besides this, financial assistance is also provided for development of booklets, pamphlets, folders etc. in various regional languages. The implementing agencies will be provided grant-in aid in the preparation & printing of cashew and cocoa literatures on need basis in English and Regional languages for distribution among farming communities and extension workers. Development of video on cultivation, processing aspects of cashew and cocoa for broadcast is also envisaged under the publicity programmes. Advertisements depicting developmental/ value addition and promotion of cashew and cocoa at important occasions/events will also be provided to institutions/societies & media engaged in horticulture development to create awareness about latest technologies on Cashew & Cocoa among farming community of India. Field days and any other campaign will be conducted in the Cashew & Cocoa growing states on need basis.

During the year 2022-23, this Directorate had extended financial assistance to various research and state development agencies for printing literature on cashew and cocoa for distribution among farmers and extension workers in regional and English languages. The Directorate also conducted/extended financial support for one day seminars /field days/workshop/awareness programme on cashew and cocoa in various states as below;

1. As a part of the celebration of Kisan Bhagidari-Prathmikta Hamari Campaign under the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the Directorate of Cashewnut and Cocoa Development organized a Seminar on Cocoa on 26.04.2022 at Vazhathoppu Panchayat, Idukki, Kerala in association with Vazhathoppu Grama Panchayat, Kudumbasree, Krishi Bhavan and Mondelez India (P) Ltd Food .
2. Directorate of Cashewnut and Cocoa Development in association with Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga organized Cashew & Cocoa fair under the 'Kisan Bhagidari Prathmikta Hamari' campaign under Azadi Ka Amrit Mahotsav on 28.04.2022 at KSNUAHS Campus Shivamogga.
3. The Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Kochi organized Naari Shakthi Mela at Chengalay Grama Panchayath, Kannur on 25.11.2022.



4. One day awareness programme on cashew was conducted on 25.07.2022 at Alakkode in association with Alakkode Grama Panchayath, Kannur.
5. The Directorate conducted a one day training programme for the beneficiaries of new planting programme of cashew in the Balal Grama Panchayat, Kasaragod on 6th March 2023.

The Directorate had published Quarterly journal of the Directorate “The Cashew and Cocoa Journal” for the year 2022 and Annual Report of DCCD for 2021-22, printed through GEM portal . A Souvenir on Cashew is also published during the occasion of National Conference on Cashew held on 30-31st January 2023 at Bhubaneswar.

The Directorate also participated in various exhibitions by putting stalls during the year as below;

1. Horticulture Value chain Exhibition at Pune on 1st and 2nd November 2022 organized by National Horticulture Board, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Mela.
2. Agri Exhibition at Morena, Madhya Pradesh on 11-13 November 2022 organised by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India.
3. 3rd Gramoday Mela & Sharadotsav on 9-12 October 2022 at Chitrakoot, Madhya Pradesh organised by Deendayal Research Institute, New Delhi, on the occasion of birth anniversary of Nanaji Deshmukh.
4. India International Trade Fair organised by Extension Division, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India from 14-27 November 2022 at Pragati Maidan, New Delhi.

An amount of Rs. 20.843 lakhs was spent for all above activities of publicity programmes during 2022-23.

viii) Human Resource Development (HRD) for Cashew & Cocoa:

The objective of the scheme is to promote rapid growth of cashew and cocoa development by narrowing the gaps in knowledge and skill, both managerial and technical by giving training to all the people involved in the cashew and cocoa sector. The component wise details of the scheme are as under.

a. Training programme on cashew and cocoa on production technologies

The programme provides appropriate training to the farmers in various aspects of cashew and cocoa farming consisting of production technology, varieties, high density planting, organic cultivation, pest management, processing, value addition, marketing etc.

The participants of the training will be the members from the farming community particularly self-help groups, women and youth interested in Agri business as a profession, Agri business entrepreneurs and members of farmer interest groups coming under the field of cashew and cocoa.

During the year 2022-23, this Directorate had conducted 64 nos cashew field level training programme and 12 nos. cocoa trainings in association with various SAUS/Research Institutes/state departments. A total of 3800 farmers availed training on various production technologies in cashew and cocoa during 2022-23. An amount of Rs. 22.70 lakhs was spent under the scheme. Statewise details of achievement is as below.

Cashew

State	No. of Programmes	Amount(Rs.)	No. of Farmers
Chhattisgarh	2	60000	100
Gujarat	5	150000	250
Karnataka	9	260000	450
Kerala	14	420000	700
Maharashtra	6	180000	300
Madhya Pradesh	1	30000	50
Odisha	2	60000	100
Tamil Nadu	18	540000	900
West Bengal	2	60000	100
Total	64	1910000	3200

Cocoa

State	No. of Programmes	Amount (Rs.)	No. of Farmers
Andhra Pradesh	5	150000	250
Andhra Pradesh	2	60000	100
Karnataka	4	120000	200
Kerala	4	120000	200
Tamil Nadu	2	60000	100
Total	12	360000	600

b. Skill development training on value addition in cashew and cocoa

The objective of the programme is to provides appropriate training to the farmers/entrepreneurs/youth in cashew and cocoa value addition in the respective research institutes/SAU^{nl}. The duration of the programme will be one day and 3 days.

During 2022-23, a total 13.65 lakhs was provided as spill over target for conducting 25 such trainings and out of this, 11 trainings were conducted with an outlay of Rs. 9.85 lakhs in Kerala, Karnataka and Odisha. An amount of Rs. 9.780 lakhs was spent for the training and agency wise achievement is as below.



Agency	No. of Programmes	Amount
CTC, UAHS, Shivamogga (including infrastructure)	1	225000
DCR, Puttur	1	75000
OSCDC, Bhubaneswar		
(including infrastructure)	1	223000
CRC, Vellanikkara	6	60000
CRC, Vellanikkara	1	60000
AEEC, Huvinahadagali	1	335000
Total	11	978000

c. Exposure visit of farmers to centre of excellence

The objective of the visit is to expose tribal and other farmers from non-traditional cashew growing districts of the States to the traditional growing districts of other States for familiarizing production and management practices being followed in the other states. A batch consisting of 50 farmers will be trained under the scheme and duration of the training will be 7 days. The assistance will be provided to the agencies involved in the training programme both in the government sector as well as private as per the MIDH norms, for which a project based proposal is to be submitted.

During the year 2022-23, the exposure visit programme was conducted by 4 agencies in the state of Assam, Madhya Pradesh and Karnataka in association with various SAU^s/Research Institutes/ state departments. Around 200 farmers were availed the training from the centres of excellence in outside state. An amount of Rs. 11.05 lakhs was spent by the following agencies during 22-23.

Agency	No. of Programmes	No. of Farmers	Amount(Rs.)
AEEC, Huvinahadagali	1	50	275000
KVK, Hanumanamatti	1	50	275000
Sahejna, Balaghat	1	50	275000
NEO, Assam	1	50	280000
Total	4	200	1105000

d. Training on cashew apple utilization for unemployed women

The utilization of cashew apple at present takes place only in Goa and that too for fermented beverages. In all other States, cashew apple is being wasted. In order to popularize the usage of cashew apple, training on preparation of cashew apple syrup are imparted to the unemployed women. The beneficiaries selected under the scheme are trained in the respective research institutes of SAU's. The cost involved of Rs. 20,000 per batch of 25 people was provided as contingency to the research institutions.

A total of 19 batches of training were conducted for unemployed women in the respective research institute of SAU's and KVK's for preparation of cashew apple syrup from cashew apple and 475 women participants availed the training. An amount of Rs.3.648 lakhs was spent including the spill over amount of Rs. 0.398 lakhs for the cashew apple training in the states of Kerala, Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh and Gujarat. The state wise details are as below.

State	No. of Programmes	Amount (Rs.)	No. of Farmers
Andhra Pradesh	2	40000	50
Gujarat	2	40000	50
Karnataka	7	125000	175
Kerala	6	120000	150
Maharashtra	2	39810	50
Total	19	364810	475

e. National level training programme on Cashew and Cocoa

The objective of the programme is to give training to the field level implementing officials of various development departments in implementing the developmental schemes of cashew and cocoa envisaged under MIDH in the farmers field and extend required farming techniques to the cultivators. The duration of the training will be 3 days. The training will be conducted at one of the research institutes viz. Directorate of Cashew Research, Puttur, ZARS, Brahmavar, RFRS, Vengurla, NABARD, BIRD, Mangalore, CPCRI, Vittal, KAU, Vellanikkara and DCCD Kochi. The participants will be from all cashew/Cocoa growing states with special emphasis to North East region to make aware and promote the cultivation in larger scale.

During 2022-23, one National Level Training Programme on Cocoa was conducted at BIRD Campus, Mangalore with a participation of 40 officials from various cocoa growing states by utilising the spill over target of 2021-22. Another one national level training on Cocoa was also conducted at Dr. YSRHU, VK Gudem, Andhra Pradesh from 3-5 April 2023 and 40 participants attended the programme. National Level training on Cashew is proposed for the field/extension officials of Cashew growing states during May-July 2023 at Keladi Shivappa Nayak University of Agricultural and Horticultural Sciences, Shivamogga. Around 60 officials will be participating in the training. An amount of Rs. 9.750 lakhs was incurred towards the conduct of the above trainings during 2022-23.

3.2. National Campaigns(AKAM) , seminars /trainings/ workshops/ awareness programme etc. organised by DCCD

i. National Conference on Cashew, Bhubaneswar

A National Conference on Cashew was organized by Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Govt. of India in association with Odisha State Cashew Development Corporation Ltd., on 30th and 31st January 2023 at Odisha State Convention Centre, Loka Seva Bhavan, Bhubaneswar. The theme of the conference was "Encashing technological innovations for production and productivity of cashew". The main objective of the conference was to discuss in detail with all



the stakeholders in the field of research, development, industry and marketing of the challenges and opportunities in cashew in various cashew growing states and also to design future development strategies to increase production, productivity and doubling farmer's income. As intended, the conference had an in depth discussion with all the stake holders coming under the purview of cashew sector from major cashew growing states and to draw feasible strategies to doubling farmers income by improving production and productivity of cashew. The conference was attended by nearly 250 delegates including scientists, development officers, farmers, processors, exporters and entrepreneurs.



The inaugural session commenced with the welcome address by Dr. Venkatesh N. Hubballi, Director, DCCD. A Goodwill Message of Shri. Naveen Patnaik, Hon'ble Chief Minister of Odisha was played on the occasion.

Dr. Arabinda Kumar Padhee, IAS, Principal Secretary (Department of Agriculture & Farmers Empowerment), Govt. of Odisha inaugurated the conference. In his inaugural address he stated that cashew has got great importance in the present era of life. He also stated that huge potentiality is existing in the state to bring this crop for meeting the demand of rawnut production, productivity, where the role of industries is the key issue that needs to be discussed in the forum.

Prof. Pravat Kumar Roul, Vice Chancellor, OUAT, Bhubaneswar was Guest of Honour on the occasion and conveyed that organization of this conference has great importance in the present context of Odisha. He has also assured that OUAT Bhubaneswar will continue various promotional activities for scientific cultivation of the cashew crop and will give possible support to the farming community.

Dr. Prabhat Kumar, Horticulture Commissioner, Govt. of India while delivering his Guest of Honour address stated that cashew is a high value crop and domestic production is not sufficient to meet the demand of cashew industries in the country. Hence there is an urgent need for enhancing domestic production and productivity. He has stated that more and more cashew nurseries should be established and accredited to ensure the quality of cashew grafts. The thrust should be given towards removal of senile plantation to be replaced with regional specific high yielding varieties. Massive intensive transfer of technology programmes has to be organized through Krishi Vigyan Kendra s and also by using mass media. He has also stated that a road map for promotion of cashew in



untapped areas is to be taken up for augmenting the production and productivity of raw cashewnut in the country. He also highlighted the urgent need for adoption of medium high density planting to enhance production in the shortest time.

Shri. Subash Chandra Moharana, Chairman, OSCDC Ltd. Bhubaneswar also stated that his corporation will take all measures to train and create awareness among farming communities on the



beneficial aspects of cashew cultivation.

To commemorate the occasion a “Souvenir” was released followed by awards to best cashew farmers, best cashew nurseries and best cashew implementing agencies. The inaugural function was concluded with vote of thanks by Shri. Sadananda Nayak, IAS, Managing Director, OSCDC Ltd.

Technical session:

Technical session started in continuation of the inaugural session. The deliberations were carried out in four technical sessions. All the issues on quality planting materials, production, processing, marketing, export and industrial needs of cashew sector were deliberated in the conference and drawn suitable recommendations to in order to draw feasible development strategies.

Recommendations

After 2 days of deliberations in the conference on various issues, the following recommendations have been emanated.

1. DCCD may conduct series of meetings with all the stake holders of cashew sector and evolve a strategy in promoting holistic cashew development and also to bring a road map for cashew development for 10 years.
2. Senile plantation is the bottleneck in cashew productivity and constitute around 30 % of



total cashew area. In order to enhance production and productivity, efforts should be made to convert existing senile cashew plantations under cashew corporations and farmers field into productive cashew plantation by removing and replanting with high yielding varieties and by adopting good agricultural practices.

3. The cashew apple is successfully utilized in the state of Goa for the production of alcohol i.e. Feni and same model need to replicated in other states.
4. The developmental departments need to give priority in completing the new planting before 15th August except in the state of Andhra Pradesh and Tamil Nadu where these two states receives good rainfall during North East monsoon.
5. The quality planting materials of cashew with the minimum age of 6 months should be selected for distribution to the farmers.
6. The DCCD should provide financial assistance for the establishment and up-gradation of cashew nurseries wherever good entrepreneurs are available.
7. The accreditation of cashew nurseries shall be given priority and inspection of nurseries should be conducted before the month of June every year.
8. The medium high density planting consisting of 400 plants per hectare should be given priority in new planting programme in order to enhance production at the shortest time possible.
9. Research organizations also need to prioritize in evaluating and releasing dwarf varieties at the earliest.
10. The Government of Goa provides minimum support price for rawnuts and same may be replicated in other states in order to promote and bring more area under cashew to reduce the dependency on import of rawnuts from other countries.
11. Import of rawnuts is mostly done by commission agents. Reducing import duty from 10 % to 2.5% has drastically brought down the price of domestic rawnut price . Hence Govt may revisit this area to enhance import duty from 2.5% to 10% so as to maintain the remunerative price for farmers and to maintain sustenance in promotion of cashew development.
12. The validation need to be carried out for identifying the most suitable varieties for high density planting.
13. In order to achieve the best success rate of establishment of cashew plantation in the field, development departments may concentrate cluster approach of new planting programme in three districts and may be rotated every third year.
14. Planting materials of one year or more with bigger bags may also be promoted for higher success rate in the establishment, since field results are already available.
15. The control of CSRB is still a major issue in the cashew sector and research organizations may



provide more thrust in developing effective control measures of CSRB.

16. Multi location trials may be conducted in farmer's field of new varieties released by various research organizations as a FLTD with the financial assistance of DCCD.
17. Regular Interface meetings should be conducted between development departments and research organisations in every six months in order to evaluate programmes and to find the solution.

ii) Visit of Secretary(A&C)& Financial Adviser, Govt. of India to DCCD

The Hon'bl Secretary(Agri. & Farmers Welfare) Shri Manoj Ahuja IAS and Shri. Sanjiv Kumar IAS, Additional Secretary and Financial Advisor, Govt. of India made a visit to Directorate of Cashewnut and Cocoa Development & Coconut Development Board on 19th October 2022 and reviewed the development programmes of Cashew, Cocoa and Coconut.



iii) Report of the Interface meeting on Cashew and Cocoa, Goa

Interface meeting on cashew and cocoa was held on 27th August 2022 at Panjim-Goa under the Chairmanship of Dr. Prabhat Kumar, Horticulture Commissioner, Government of India. The main objective of the meeting was to find out many confronting issues in Cashew and Cocoa and to evolve a developmental strategy in the form of an actionable plan for next five years and to bridge the gap between demand and supply in the cashew and cocoa sector. Directors of Dept. of Horticulture/ Agriculture of cashew growing states, Managing Director of cashew corporations, Scientists from ICAR institute and Agriculture Universities, representatives from Industry, Nursery owners and Innovative farmers have attended the meeting. The meeting commenced with the welcome address by Dr. Venkatesh N. Hubballi, Director, Directorate of Cashewnut and Cocoa Development. In his Chief Guest address Dr. Prabhat Kumar, Horticulture Commissioner, Govt. of India stressed the need for active involvement of all the players to support the Govt. of India's initiatives in developing cashew and cocoa as a more profitable enterprise. He also indicated the need to increase the productivity and production by a project based activity under RKVY/MIDH and to promote allied activities in cashew and cocoa. Need of irrigation facilities, marketing and promotion of FPO's were also stressed in his address



Dr. Venkatesh N. Hubballi highlighted detailed scenario of cashew and cocoa in India and the Govt. of India's initiatives in promotion of cashew and cocoa. He also stressed the need for increasing area and domestic production of rawnut and cocoa beans in the country since import of rawnuts in future will not be guaranteed because exporting countries have started their own processing set up. He also detailed the future strategies to overcome the issues and narrated a five year plan for increasing the production by adopting high density planting especially in cashew.

Many experts gathered in the meeting have stated that more than 15 lakhs people are working in farms, factories and marketing of cashew sector and now the industry is in struggling position due to several factors. So government intervention is needed to save the industry by the way of controlling unhealthy imports, incentives to the stakeholders, promoting Indian cashew at national and international forums, promotion of high density planting and replanting, tech enabled farming and processing of cashew. Dr. T.N Raviprasad, Director, Directorate of Cashew Research, Puttur, has given a detailed note on status of cashew research and future strategies and pointed out various approaches to control Cashew Stem & Root Borer, varietal identification for high density planting for different regions.

Shri. Sadananda Nayak, IAS, Managing Director of Odisha State Cashew Development Corporation has presented the status of cashew replanting programme by OSCDC. Shri. Hemantha Kumar Panda, Director of Soil Conservation, Bhubaneswar explained cluster approach in cashew development under MGNREGA, wherein government departments maintain the gardens for three to five years and later on are handed over to beneficiaries. Dr. B Suma, Professor and Head KAU, Thrissur and Dr. E. Apshara, Principal Scientist, CPCRI, Vittal highlighted the high yielding varieties, improved production technologies and also ongoing research in their institutes. Dr. Jalaja, S Menon Assistant Professor and Head CRS, brought forward the cashew development scenario in the state and multiple use of cashew apple utilization. Dr. Pradosh Panda, Additional Director, Government of Odisha also highlighted the need of concentrated approach in cashew development in the state of Odisha. Nursery owners and innovative farmers have also expressed various issues in Cashew cultivation.

iv) Report on National Level Training Programme on Cocoa

The National Level Training Programme on cocoa was organized by DCCD from 12th to 14th October 2022 at BIRD Campus, NABARD, Mangalore for the benefits of officials of developmental departments in the state of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Around 40 officers from various states attended the National Level Training Programme.

Dr. Venkatesh N Hubballi, Director, DCCD, along with Shri. Satheesan Kartha, Faculty Member, NABARD inaugurated the National Level Training programme. Other dignitaries present in the NLT were Dr. Tamil selvan M., Director(Retd.), /S DASD, Calicut, Shri. S Jnanadevan, Consultant, DCCD. The introductory address and welcome address was given by Dr. Venkatesh N. Hubballi. In his introductory address, he explained the objectives of National Level Training programme and also highlighted brief scenario of Cocoa in India and the activities of the Directorate in connection to Cocoa cultivation.



The technical session was started after completion of inaugural session. During the first two days, the following presentations and deliberations were made in details by experts.

Dr. B Suma, Professor & Head, CRC, KAU covered all the aspects of varieties and agro techniques in cocoa. A session on training and pruning techniques in cocoa was also led by Dr. Suma. Dr. J S Minimol, Professor, Cocoa Research Station, KAU presented a detailed slide show and lecture class on post-harvest management and value addition in Cocoa. Dr. S Elain Apshara, Principal Scientist, ICAR-CPCRI, Vittal presented a detailed slide show on the research scenario of cocoa and client needs. A Class on Phenological studies of Cocoa was also taken by Dr. Apshara. Dr. Chaitra M, Scientist(Plant Pathology) and Dr. Madhu T N, Scientist (Agri. Entomology) CPCRI, Vittal presented detailed aspect of pest and disease management including biological control in relation to Cocoa.

A class on Therapeutic potential and nutritional benefits of cocoa was led by Dr. Raviraja Shetty, Associate Professor (Horticulture), Agricultural & Horticultural Research Station, Kapikad, Ullal. Shri. Srinivas, Officer, CAMPCO, Mangalore, presented detailed aspect to Commercial production

of Chocolate. He also requested all the participants to visit the CAMPCO factory for detailed view of processing techniques followed in making of chocolate. Shri. Partha Varanasi, Varanashi Orgnaic Farms, Mangalore, explained in detail about Organic cultivation of cocoa and organic certification and also policy matter involved therein. Shri. Roopak Bhat, Head, Cocoa Operations, Mondelez Food India(P) Ltd. presented the global market status of Cocoa along with Marketing and value chain analysis of cocoa in India and in world.



Shri. Jnanadevan, Consultant, DCCD explained how cocoa cultivation when grown with Coconut can aid in doubling farmers income. All officials participating in the training programme expressed their happiness regarding the valuable information received from this training programme organised by Director, DCCD and requested to conduct such training programmes regularly. A surprise test on cocoa cultivation was carried out and the winners were awarded mementos.

On the third day, all the participants visited CAMPCO chocolate factory and got an opportunity to observe processing techniques of extracting cocoa butter, separating cocoa mass and cocoa powder and the process of making different varieties of chocolates. A visit to ICAR-CRCRI, Vittal was also done wherein Dr. Elain Apshara, Principal Scientist, ICAR-CPCRI, Vittal demonstrated the practical pruning, training practices to the participants and also demonstrated various methods of fermentation that can be done to obtain high quality cocoa beans.

The session was concluded with valedictory function wherein mementos were distributed to the winners of the written test and a vote of thanks delivered by Shri. Nikhil V M, DCCD.

v) Kisan Bhagidari-Prathamikta Campaign :Cocoa Seminar

As a part of the celebration of Kisan Bhagidari-Prathamikta Hamari Campaign under the Azadi Ka Amrit Mahotsav in the country, the Directorate of Cashewnut and Cocoa Development has organized a Seminar on Cocoa at Vazhathoppu Panchayat, Dist-Idukki, Kerala on 26.04.2022 in association with Vazhathoppu Grama Panchayat, Kudumbasree, Krishi Bhavan and Mondelez Food India (P) Ltd. and AFPRO. The Vice President of Vazhathoppu Grama Panchayath said there is vast scope for integrated development of cocoa cultivation in the panchayath and cocoa development schemes under MIDH may be extended to the panchayath. Around 300 numbers of farmers, mostly women, participated in the Seminar. Three successful women farmers were also honoured on the



occasion who had practiced innovative cultivation methods to double the production. An exhibition was also arranged depicting the activities of MIDH during the occasion.



In his message, Director, DCCD has informed that with the efforts of DCCD from 2005 onwards, an area of more than 70,000 ha has been brought under cocoa and Cocoa farmers of Idukki District will be further supported by DCCD under MIDH scheme.

Dr. J.S. Minimol, Professor, Cocoa Research Centre, KAU delivered a talk on 'Processing and value addition in Cocoa' which was highly interactive. A small session on preparation of homemade chocolate was also taken up by Dr. Minimol which will be beneficial for increasing farmer's income.

The Sr. Technical Executive, Mondeliz Food India (P) Ltd., explained about Cocoa DIGI App, a digital App on various cultivation practices on Cocoa and calendar of operations with provision for registration of farmers. Further, the participants were taken to visit model Cocoa garden of Shri Sunil, a progressive cocoa farmer to demonstrate the technology of pruning techniques, cultivation methods, pest and disease management adopted by him resulting in better management of Cocoa plantations. The programme was covered in all local news papers viz. Malayala Manorama, Mangalam and TV channels of DD Malayalam and Kerala Vision.

vi) Kisan Bhagidari-Prathamikta Campaign : Cashew and Cocoa Fair

Directorate of Cashewnut and Cocoa Development in association with Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga organized Cashew & Cocoa fair under the 'Kisan Bhagidari Prathamikta Hamari' campaign under Azadi Ka Amrit Mahotsav on 28.04.2022 at KSNUAHS Campus Shivamogga.



The main theme of the programme is to highlight various technologies and high yielding varieties available with the research and to disseminate the technologies to a large mass of farming community by way of interacting with experts and innovative farmers in the event. Mass media like TV channels and print media have been extensively utilized to further communicate the benefits of cashew and cocoa cultivation wherein these crops play a very important role in improving economic conditions of small and marginal farmers. Dr. Venkatesh. N. Hubballi, Director, Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Dr. M Hanum anthappa, Vice Chancellor of Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga and all the senior officials of the university, board members & stakeholders like Directorate of Horticulture, Mondelez Food India (P) Pvt Ltd & CAMPCO participated. An Exhibition was also arranged to highlight the technologies on High yielding varieties and other technologies by placing live exhibits and banners. On this occasion 3 Innovative farmers of cashew and cocoa were felicitated wherein these farmers achieved very good results in getting better yield of cashew and cocoa. Nearly 1000 farmers are participated from adjoining districts of Shivamogga. Television channels like Doordarshan, Power TV, Namma Shivamogga, & TV Bharat youtube channels like Namma sahyadri and Print media's like New Indian Express, Vijayavani, Prajavani, Vijaya Karnataka, Samyukta Karnataka, Jana Horata & News next covered the programme.

vii) Naari Shakthi Mela at Chengalayi Panchayath, Kannur

The Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Kochi organized Naari Shakthi Mela at Chengalay Grama Panchayath, Kannur on 25.11.2022. The programme was started with welcome address of Shri. A Janardhanan, Chairman, Standing Committee (Development). Shri. Dadasaheb Desayi, Deputy Director, DCCD inaugurated the function by handing over good quality cashew grafts to Smt. K. M Sobhana, Vice President, Chengalayi Grama Panchayath. In his inaugural address, Shri. Dadasaheb Desayi stressed the importance of women involvement in cashew sector. Shri. Prajosh, Chairman, Health and Education Standing Committee, Shri. Ashiq Chengalayi, Ward member also attended and facilitated the function. After the inaugural function a cashew seminar on scientific cultivation practices was conducted for women farmer. Dr. Shamsudheen Mangalasseri, Senior Scientist (Soil Science), Directorate of Cashew Research, Puttur delivered a class on the topic and covered importance of soil testing before planting, selection of grafts, planting, INM/ IPM practices and post-harvest management in cashew. Afterwards, Shri. Brijith Krishna, CEO and Founder, Eatery Malabaricus, Kannur presented a topic on importance of cashew processing and exhibited various cashew sprout products. In his presentation, he stressed the scope of sprouted products in domestic and international market and also narrated various schemes for promoting small scale industries and startups. Shri. Jinesh Kalayani, Director, Irikkur Agro Farmers Producer Company, Payyavur, Kannur has presented a topic on scope of farmer producer organization in cashew sector. Around 150 women farmers attended the programme. The programme exposed the scope of value added products of cashew in domestic and international market and also for promoted small scale industries and startups. The programme was concluded with vote of thanks by Shri. Nikhil V M, Sr. Technical Assistant, DCCD.



viii) Nari Shakti Mela, Kidu, Karnataka

The Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Kochi organized Naari Shakthi Mela at ICAR-CPCRI Regional Centre, Kidu, Karnataka on 21.11.2022 as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Around 500 women farmers attended the programme and they were benefitted with awareness on production and processing technologies of Cocoa. Shri. S. Angara, Minister of Fisheries, Ports and Inland Water Transport inaugurated the program. He stressed the need of growing multi species cropping systems with crops of local importance like coconut, arecanut, cocoa, banana, pepper, jack, cashew and other fruit and forest species and farming systems suitable for the region. He highlighted the scope and importance of growing cocoa systematically with proper pruning and management and the opportunities in processing. Dr. Elain Apshara, Principal Scientist (Horticulture) and Dr. Chaithra, Scientist (Plant Pathology) of CPCRI, RS, Vittal detailed the cocoa cultivation in palm based mixed cropping systems, cocoa varieties released from CPCRI, nursery management, advanced production technologies, integrated pest and disease management, primary processing technology and chocolate making methods. A total of 500 women participated and gained knowledge on cocoa and its products. Specifically women groups, Gramadevathe of Ivarnadu, Sharadha Group, Nellyady, PailarOkkootta, Sullia, Mangala Raitha Shakthi, Murulya, Sullia showed interest and enthusiasm in chocolate making.



ix) Awareness programme on Cashew, Alakkode, Kannur

One day awareness programme on cashew was organised on 25.07.2022 by this Directorate at Alakkode and was conducted successfully. Around 150 cashew farmers participated in the awareness programme on Cashew. Smt. Aysha P. C, Vice President, Alakkode Grama Panchayath welcomed the farmers, Panchayath Presidents, Chairman, Cashew Cell and DCCD Officials to the awareness programme. The awareness training programme was inaugurated by Shri. Joji Kannikkattu, President, Alakkode Grama Panchayath. He pointed out the initiation of this Directorate for betterment of cashew farmers in the region in his speech. Shri. Jose Poomala, Chairman, Cashew Cell gave the presidential address. He pointed out the issues of price fluctuation of raw cashewnut during peak season and requested this Directorate to help the farmers for obtaining better price for their produce.



Shri. Ravindra Kumar, Deputy Director, DCCD delivered the keynote address and in his speech he explained about the development activities and area expansion programmes of Cashew and Cocoa by this Directorate. Shri. Joy Taramangalam, Rayarom (best cashew farmer) and Smt. Sherly Santhosh, Olikkal, Merygiri (best women farmer) were honoured on the occasion. The inaugural session was ended up with vote of thanks by Shri. Nikhil VM, Senior Technical Assistant, DCCD, Cochin.



The technical session was started with lecture class on Cashew cultivation by Dr. Meera Manjusha, Asst. Professor, Regional Agricultural Research Station, Pilicode.

x) Training on Cashew, Balal, Kasaragod

The Directorate conducted a one-day training programme for the beneficiaries of new planting programme of cashew in the Balal Grama Panchayat on 6th March 2023. Around 50 cashew farmers participated in the training programme. Shri. Alex Nedyakalayil, Chairman, Vikasana Karya Standing Committee, Balal Grama Panchayat welcomed the participants. The training programme was inaugurated by Shri. Raju Kattakayam, President, Balal Grama Panchayath, Balal who encouraged the farmers to opt inter cropping with cashew instead of sole cropping systems and Shri. Jose Poomala, Chairman, Cashew Cell presided over the function and he mentioned the initiation and role of this Directorate and the subsidies provided for betterment of cashew farmers in the region.



Shri. VineethLukose, DCCD explained about the developmental activities and area expansion programmes of Cashew and Cocoa implemented by this Directorate. Dr. Meera Manjusha, Assistant Professor, Regional Agricultural Research Station, Pilicode took a detailed class on Integrated Pest and Disease Management in Cashew. After the technical session, the farmers were taken to nearby cashew garden for field visit where several queries regarding pest and disease management were addressed. The training programme was concluded with a vote of thanks by Smt. Anannya Susan, DCCD, Cochin.

xi) Report on Karshaka seminar, Kalamassery

As part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav programmes a Karshaka seminar on cocoa was organised by Vishwamata Charitable Foundation, Kalamassery with the financial support of Directorate of Cashewnut and Cocoa Development on 31st August 2022 at Kalamassery Govt. Guest house hall. The Seminar was presided over by the Shri. Sunil Aravind, Chairman, Vishwamata Charitable Foundation. Shri. Jnanadevan, Consultant, DCCD took an authentic class on Cashew and Cocoa Development during the occasion. Eminent people in the field of agriculture and society were honoured in the function. The entire program was telecasted by Jet TV.



xii) Visit of study team from Dept. of Hort, TN

A study team consisting of 10 technical officers from Tamil Nadu Horticulture department headed by Smt. S. Bhuvaneswari, Assistant Director of Horticulture, Madurai East visited DCCD on 17.05.2022. Shri. Dadasaheb Desayi received the officials. A brief presentation on activities of this Directorate was presented by Deputy Director and status on cashew and cocoa in India especially Tamil Nadu were discussed in the meeting.



xiii) Participation in Exhibitions

a. Participation in India International Trade Fair

The Directorate had participated in the India International Trade Fair (IITF 2021) from 14th to 27th November 2022 at PragatiMaidan, New Delhi. The theme of the trade fair was 'Vocal to Local, Local to Global' and the Directorate had put up stall accordingly depicting locally processed products of cashew and cocoa. Apart from this, various activities of the Directorate with regard to development



and promotion of Cashew and Cocoa were also depicted. The stall was visited by several Ministry officials including Dr. N. K Patle, Addl. Commissioner (Hort.), Dr. Vijaya Lakshmi Nadendla IAS, Chairman, CDB, Shri. Rajeev Jain, Retd. Deputy Secretary and other business pioneers.



b. Participation in Gramodaya Mela, Chitrakoot, Madhya Pradesh

The Directorate had participated in the 3rd edition of Gramodaya Mela (Sharadotsav) from 09th to 12th October 2022 at Chitrakoot, Madhya Pradesh, organised by Deendayal Research Institute, New Delhi. The Gramodaya Mela is organised on the birth anniversary of Shri. Nanaji Deshmukh and as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. The theme of the exhibition was to showcase the progress and development of the plans and activities of the departments under central and State Govts. and also the cultural heritage of the State and Nation. Accordingly the Directorate put up a stall displaying flex and live materials of cashew and cocoa depicting various activities of the Directorate for the promotion of cashew and cocoa in India. The stall was visited by officials from state and central Govt. departments and lot of people from the areas located in the state of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.



4

Administrative matters**4.1. RTI in DCCD**

During the year 2022-23, this Directorate had received requests under provisions of RTI Act seeking various kinds of information. During this period Shri P.A. Parameswaran, AO was designated as CPIO and Dr. VenkateshN.Hubballi, Director as Appellate authority. The Section 4 information in revised proforma has been prepared in this year and uploaded in the Directorate's website. All possible information which can be brought under the public domain has been included in the revised Section. 4 proforma. The details of RTI requests received and disposed during the year is an under.

Total No. of RTI requests received	Total No. of requests disposed off	Total No. of request in which information was denied	Total No. appeals received
08	08	Nil	Nil

4.2 Vigilance and Special Campaign 2.0

In accordance with the directive of Central Vigilance Commission preventive vigilance measures cum house keeping activities has been organized for the period from 16/08/2022 to 15/11/2022. During this period, steps were taken for proper record management, management of assets, technology initiative by way of system study for new website of DCCD etc.

As per the directions of Ministry of Public Grievances and Pensions, Special Campaign 2.0 for disposal of pending matters was observed from 02/10/2022 to 31/10/2022 to reduce the pendency to the minimum possible level. The campaign run along with swatchtha drive were successful as the office premises were cleaned and old records/files etc were weeded out. Shri. Dadasaheb Desayi, Deputy Director was the nodal officer for the campaign and data was regularly uploaded to DARPG portal. The detailed of the activities carried out in the special campaign are listed below.

SL No.	Activities	Numbers
1	Cleanliness Campaign	3
2	Record management (file reviewed)	815
3	Record management (file weeded)	357

4.3 .Report on PwD

As per Section 23 (i) of the PwD Act, 2016 the Directorate has already designated Grievance Redressal officer. The details of the officer has been displayed on Directorate website and at the entrance of office premises. The existing posts identified as suitable for PWDs have been reviewed and list has been prepared both for identified and non –identified posts. The new reservation roster



for PWDs have been prepared and made operations as per DOPT directive. Respective as stipulated under Rule.9 and Rule.10 of PWD Rules, 2017 are being ,maintained.

During the year one post of Lower Division Clerk reserved for person with disabilities have been filled up by the candidates nominated by Staff Selection Commission.

4.4 Official Language Implementation Report 2022-23

A brief report on the steps taken towards progressive implementation of Official Language in the Directorate of Cashewnut and Cocoa Development and compliance of Official Language Rules and Orders is presented below.

a) Official Language Annual Action Plan

On the basis of the annual program issued by the Department of Official Language, this Directorate has prepared an annual action plan, keeping in view its activities and executive needs, in which special importance has been given to the use of information technology. The objective of this Annual Action Plan is not only to promote the progressive use of Official Language in the internal activities of the Directorate but also to promote among all the stakeholders of the Directorate, mainly farmers, scientists, technical experts, State Government offices etc.

b) Hindi training

All the staff of the Directorate are either trained or have working knowledge of Hindi. Three staff members possess proficiency in Hindi and they have been issued individual orders as per Rule 8(4) of OL Rules.

During the report year, the Junior Translation Officer of the Directorate was nominated for one week Translation Refresher Course and imparted training at CTB, Bangalore from 27/03/23 to 31/03/23. She had already completed the in-service long term course of three months when she joined service.

c) Compliance with section 3(3)

All documents covered under Section 3(3) of the Official Languages Act 1963 are issued in bilingual form only. Therefore, the compliance of section 3(3) in the directorate is 100%.

d) Rule (5) of the Official Language Rules, 1976

In compliance with Rule (5) of Official Language Rules, 1976, all the letters received in Hindi have been replied to in Hindi only.

f) Rule (11) of the Official Language Rules, 1976

In compliance of rule (11) of the Official Language Rules, 1976 all seals, name plates, signs boards etc are prepared in Hindi.



g) Hindi Workshop

During the report year three workshops were organized in the Directorate. Due to visit of Parliament Committee on OL, workshop could not be held during the second quarter. During the first quarter, a workshop was conducted by the Junior Translation Officer of the Directorate on 29/06/22 on the subject Hindi Grammar.

During the third quarter, a Technical workshop was organized on 26/10/22 wherein employees from all Central Government Offices and PSUs of Cochin were invited to attend. Dr. Madhusheel Ayillyat, Manager(OL), Reserve Bank of India, Cochin took class on Kanthasth and other technical tools available in the Official Language field. All officers and staff members of this Directorate and Hindi staff from 15 organisations participated in the workshop.

The fourth quarter's workshop was held on 27/02/23 wherein the Junior Translation Officer of the Directorate took classes on doing work in computer in Hindi. Theory class was taken during morning session and in the afternoon session, the staff were given practical training at their seats.

h) Hindi Divas/Fortnight

Hindi day was celebrated in the Directorate on 14/09/2022 with a meeting at the Seminar Hall. However, due to the visit of the Parliament Committee on OL, the Hindi Fortnight Celebrations scheduled to be held from 14th September to 28th September was postponed to October. Thus, Hindi Fortnight 2022 was organized from 17/10/22 to 29/10/22 with various programmes and competitions.

On 17/10/22, a slide show on Official Language Rules and Policy was organized for the benefit of the staff members. From 18/10/22, the following competitions were organized for the promotion of Hindi in the office and to encourage the employees. In view of 'Azadi ka Amrit Mahotsav' the number of competitions were increased and the subject of most of the competitions was Amrit Mahotsav.

- 1) Competition on Administrative and Technical Terminology
- 2) Noting and Drafting Competition
- 3) Aaj ka sabd Competition
- 4) Hindi Typing Competition
- 5) Essay writing completion on Amrit Mahotsav
- 6) Elocution competition on Amrit Mahotsav
- 7) Quiz competition (giving importance to Amrit Mahotsav)
- 8) Competition on word power.

All the employees including MTS, wholeheartedly participated in the competitions. The closing ceremony of the fortnight was organized on 11/11/22 in the seminar hall of the Directorate under the Chairmanship of the Director. After the invocation by Smt. Annanya Susan, the Administrative Officer welcomed everyone. In his welcome address, Shri PA Parameswaran, Administrative Officer, highlighted the achievements made in the implementation of Official Language during the past one year. Then the Director was invited for the Presidential Address. In his Presidential address, the Director while congratulating the winners of the competitions said that it is commendable that there has been an increase of about 5% in Hindi correspondence and noting after the review of the official work done during the fortnight. He expressed the hope that all would increase the use Hindi wholeheartedly in their daily work. Prizes were distributed to the winners of the competitions. Finally the program ended with vote of thanks by Smt Resmi, Junior Translation Officer.

i) Official Language Implementation Committee

According to the OL rules, an Official Language Implementation Committee has been constituted in the Directorate under the chairmanship of the Director, in which all gazetted officers and the Junior Translation Officer are members. At the end of every quarter, the meeting of the committee is organized as per rules and the minutes are forwarded to the Headquarters and TOLIC. During the report year, the meetings of the said committee were held on 21/06/22, 30/09/22, 06/12/22 and 23/03/23 during the report year.

j) Aaj ka sabd

A special scheme has been formulated for the encouragement of the employees, in which a Hindi word, its English meaning, a sentence from that Hindi word and its English equivalent are regularly written on white boards installed at the two floors in the Directorate. Thus, based on the words and sentences written during the year, a competition is organized during the Hindi fortnight and the first, second and third prize winners will be awarded cash prize of Rs.1000/-, 750/- and 500/- respectively. During the report year, Smt. V.S Jayalakshmi, Statistical Investigator, Shri. Rohith H.S, Technical Assistant and Shri. Dense K Paul, Senior Computer were awarded first, second and third prizes respectively.

k) Purchase of Hindi Books

According to the Official Language Rules, 50% of the expenditure on the purchase of books (other than reference books) should be spent for the purchase of Hindi books, whereas in the Directorate, only Hindi books are purchased apart from the Rule books. Thus, in the report year, Hindi books worth Rs.4984/- were purchased.



l) Participation in the programs of Town Official Language Implementation Committee

The Directorate has actively participated in all the programs organized by the Kochi TOLIC. The Junior Translation Officer was awarded second prize in singing competition held in connection with Joint Hindi Fortnight celebrations.



In a special meeting organized on 14/06/23, the Directorate was awarded First Prize for OL implementation for the year 2021-22. Shri Dadasaheb Desai, Deputy Director received the rolling trophy from the Principal Chief Income Tax Commissioner and Smt. Resmi R. I received the certificate.



m) Incentive scheme

In order to encourage the use of Hindi in official work, the incentive scheme issued by the Department of Official Language is implemented in the Directorate. Employees who do their official work partially or wholly in Hindi and write at least 10,000 words in Hindi in a year are eligible for rewards under this scheme. Almost all the employees of the office are participating in this. Eligible employees can be given cash prize on the basis of their performance as detailed below:

1st Prize R (2 Prizes) @ Rs.5000/- per participant

2nd Prize (3 Prizes) @ Rs.3000/- per participant

3rd Prize (5 Prizes) @ Rs.2000/- per participant

In this regard, the following awards were given in the report year:

Shri Bipin V, UDC - First Prize of Rs.5000/-

Shri Dense K Paul, Senior Computer - First Prize for Rs.5000/-

n) Quarterly Progress Report

Quarterly progress report on implementation of Official Language is prepared and sent to the Headquarters within five working days after every quarter and this report is also uploaded in the Official Language website of Ministry of Home Affairs regularly.

o) Inspection

Parliament Committee on Official Language had inspected the OL related work of the Directorate on 28/09/2022. The inspection meeting was held at Trivandrum wherein all the officers of the Directorate and officers from Ministry of Agriculture and Farmers Welfare had attended. All the assurances given at the meeting have been complied with and the report sent to the Parliament Committee.

p) Check points

As done every year, on the basis of the annual program prepared for the implementation of the Official Language Policy of the Union Government, the check points for the implementation of the Directorate was prepared in the report year too and was circulated among staff.

q) Other special achievements

- A special technical workshop was organized on 26/10/2022 wherein OL staffs from all Central Government offices and PSUs of Cochin were invited. Dr. Madhusheel Ayillyat, Manager(OL), Reserve Bank of India, conducted the class. Classes were taken in the workshop mainly on Kanthastha, and also all other OL related IT. Hindi staff from 15 organisations attended the workshop. All 15 officers/employees of this Directorate too had participated. The feedback was excellent.
- In a special meeting organized on 14/06/23, the Directorate was awarded First Prize for OL implementation for the year 2021-22. Shri Dadasaheb Desai, Deputy Director received the rolling trophy on behalf of the Directorate from the Principal Chief Income Tax Commissioner and Smt. Resmi R I received the certificate.
- The Directorate was awarded first prize for implementation of OL during the year 2020-21, by the Department of Official Language at a function held on 27/01/23 at Trivandrum. Shri P A Parameswaran, Administrative officer received the shield on behalf of the Directorate from the Hon'ble Governor of Kerala Shri. Arif Muhammed Khan and Smt. Resmi R. I, Junior Translation Officer was awarded the certificate.

National conference on Cashew held on
30-31 January 2023 at Bhubaneswar





Interface meet on Cashew and Cocoa held on 27th August 2022 in Panjim,
Goa





National Level Training on Cocoa held from 12th – 14th October 2022 at BIRD, Mangalore





**Kisan Bhagidari Prathamikta Campaign Cocoa Seminar held on 26th April
2022 at Vazhathoppu, Idukki**





Kisan Bhagidari Prathamikta Campaign Cashew and Cocoa Fair held on 28th April 2022 at Shivamogga





Cashew and Cocoa nursery Accreditation





New plantation Development : CASHEW & COCOA





Replanting programme of Cashew under





HRD- Training programme on cashew and cocoa





HRD- Training programme on chocolate preparation





HRD- Training programme on cashew and cocoa

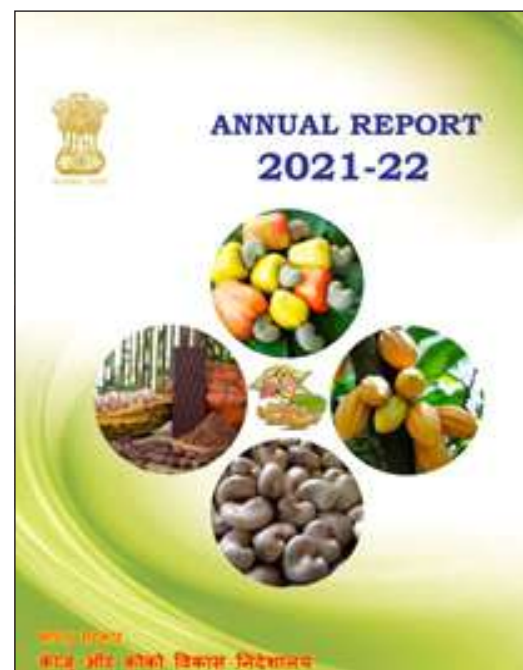
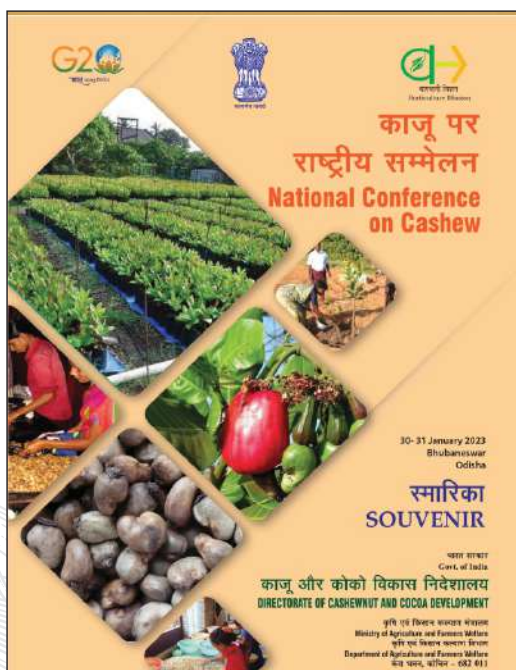
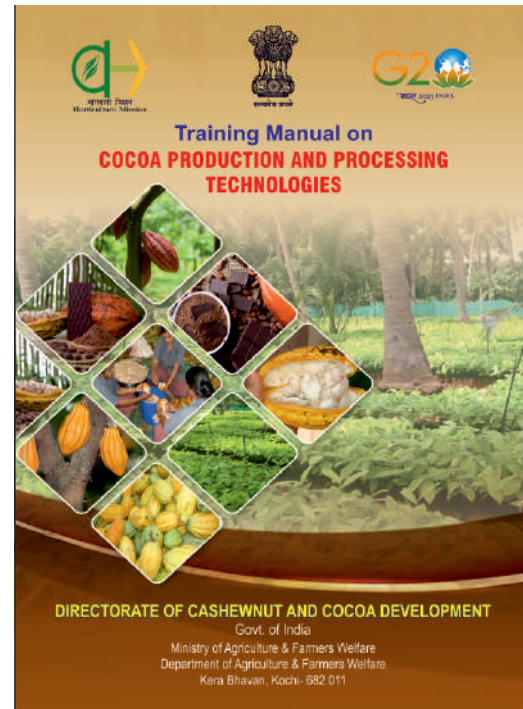
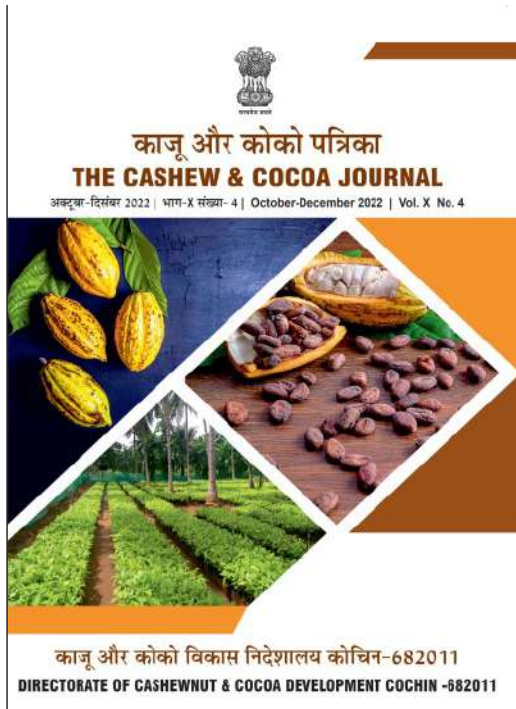




HRD- Training programme on chocolate preparation



Publication of the Directorate of Cashewnut and Cocoa Development





काजू और कोको विकास निदेशालय

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, केरा भवन-कोचिन, केरल, भारत

DIRECTORATE OF CASHEWNUT & COCOA DEVELOPMENT
Government of India

Department of Agriculture & Farmers Welfare,
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Kera Bhavan, Kochi-682011, Kerala, India